

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर स्थिति पत्र

संस्करण - 2

नवम्बर-2017

वीवीपीएटी

कंट्रोल यूनिट

बैलट यूनिट

भारत निर्वाचन आयोग

इलेक्ट्रॉनिक
वोटिंग
मशीन (ईवीएम)
पर
स्थिति पत्र



भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001

विषय-सूची तालिका

परिचय

भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की यात्रा

सामाजिक-राजनीतिक फीडबैक

विधिक हस्तक्षेप एवं न्यायालयीन मामले

भारतीय ईवीएम: डिजाइन और विनिर्माण प्रोटोकॉल

ईवीएम संरक्षा एवं सुरक्षा: तकनीकी और प्रशासनिक

तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) की भूमिका

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में प्रौद्योगिकी का क्रमिक विकास एवं संस्थापन

अंतर्राष्ट्रीय तुलना

वीवीपीएटी

वर्तमान मुद्दे और विवाद

सभी राजनीतिक दलों की बैठक

ईवीएम चुनौती

वर्तमान स्थिति

निष्कर्ष

अनुबंध

संक्षिप्तियां एवं परिवर्णी शब्द

एसी	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
बीईएल	भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड
बीयू	मतपत्र इकाई
सीयू	नियंत्रण इकाई
डीआरएम	डायरेक्ट रिकॉर्डिंग मशीनें
ईसीआई	भारत निर्वाचन आयोग
ईसीआईएल	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
ईएमबी	निर्वाचन प्रबंधन निकाय
ईआरसी	निर्वाचकीय सुधार समिति
ईवीएम	इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
एचसी	उच्च न्यायालय
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
ओटीपी	एकबारगी प्रोग्राम-योग्य
पीसी	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
एससी	सुप्रीम कोर्ट
टीईसी	तकनीकी विशेषज्ञ समिति
वीवीपीएटी	वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल

परिचय:

भारत लगभग 850 मिलियन पंजीकृत मतदाताओं वाला दुनिया का सबसे बड़ा सहभागी लोकतंत्र है। संसद और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का संवैधानिक अधिदेश भारत निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है।

भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक इकाई है, जिसने पिछले 66 वर्षों से संसद और विभिन्न राज्य विधान सभाओं के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, जागरूक और विश्वसनीय तरीके से निर्वाचनों का नियमित रूप से सफलतापूर्वक संचालन किया है। आयोग को दुनिया भर में निर्वाचन प्रबंधन में "वैश्विक स्वर्ण मानक" के रूप में व्यापक रूप से मान्यता-प्राप्त है जिसने निर्वाचनों के कुशल और व्यावसायिक संचालन में निरंतर उच्चतर मानक स्थापित किए हैं।

आयोग निर्वाचन प्रक्रियाओं और प्रणालियों में सुधार लाने और इन्हें चुस्त-दुरुस्त करने में नवीनतम प्रौद्योगिकीय प्रगतियों को अपनाने, अंगीकृत करने और कार्यान्वित करने में अग्रणी रहा है।

आयोग ने समुचित विधिक अवलंब द्वारा अनुसमर्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय और सुरक्षित तरीके से देश के कोने-कोने में मतों को दर्ज करने, उनका भंडारण एवं गणना करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का चलन शुरू करने की अग्रणी पहल की है। ईवीएम का उपयोग देश में निर्वाचकीय प्रक्रिया में निरंतर सुधार करने, इसे स्तरोन्नत और सशक्त करने के आयोग के अदम्य संकल्प को प्रदर्शित करता है।

आयोग ने पिछले 23 वर्षों में राज्य विधान सभाओं के 107 साधारण निर्वाचनों और 3 लोकसभा निर्वाचनों का संचालन करने में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। राज्यों की सूची, उन वर्षों के साथ जिनमें विधानसभा निर्वाचनों में 100% ईवीएम का इस्तेमाल किया गया, **अनुबंध-1** पर रखी गई है।

वर्ष 2014 के लोकसभा निर्वाचनों में 55.41 करोड़ (554 मिलियन) मतदाताओं ने ईवीएम का प्रयोग करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

भारत में निर्वाचकीय परिदृश्य पर सकारात्मक निर्वाचकीय सुधार के रूप में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की वर्ष 1982 में हुई शुरुआत के समय से ही, ईवीएम पर राजनैतिक सहित विभिन्न पक्षों द्वारा आरोप और आक्षेप लगाए जाते रहे हैं। हाल ही में, मार्च 2017 में पांच राज्यों के विधानसभा निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के बाद, ईवीएम के विरुद्ध फिर से कतिपय आरोप लगाए गए हैं। तेरह राजनैतिक दलों के एक समूह ने 10 अप्रैल 2017 को आयोग से मुलाकात की और ईवीएम के उपयोग के बारे में कतिपय संदेह व्यक्त किए।

इस बात पर जोर दिए जाने की जरूरत है कि भांति-भांति की तकनीकी सुरक्षा, प्रशासनिक प्रोटोकॉल और आयोग द्वारा अधिदेशित प्रक्रियात्मक रक्षोपाय ईवीएम की अक्षुण्णता, गड़बड़ी के प्रति प्रतिरोधात्मकता और विश्वसनीयता को सद्दृढ़ता से सुनिश्चित करते हैं। आयोग द्वारा विहित सख्त प्रक्रियाएं और सुपरिभाषित मतदान प्रक्रियाएं किसी भी प्रकार के छल-कपट से ईवीएम को सुरक्षित करते हैं।

यह स्पष्ट करना भी महत्वपूर्ण है कि आयोग संसद और राज्य विधानसभा के सभी भावी निर्वाचनों में वीवीपीएटी का 100% कवरेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में वीवीपीएटी और नवीनतम पीढ़ी (एम3) की ईवीएम की खरीद के लिए आवश्यक निधियां संस्वीकृत की गई हैं और जैसाकि विनिर्माताओं द्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है, बीईएल और भारत निर्वाचन आयोगएल द्वारा मशीनें भारत निर्वाचन आयोग को सितंबर 2018 तक विनिर्मित करके डिलीवर किए जाने की उम्मीद है।

वर्तमान समय में जब ईवीएम पर एक बार फिर से इसकी प्रभावकारिता और सद्दृढ़ता को लेकर एक और बहस छेड़ी जा रही है इसलिए हितधारकों के साथ परामर्श किया जाना आवश्यक हो जाता है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की यात्रा

भारत में मतदान प्रणाली कई प्रकार के बदलावों से गुजर चुकी है। वर्ष 1952 और 1957 में लोकसभा के पहले दो साधारण निर्वाचनों के दौरान, प्रत्येक अभ्यर्थी को एक पृथक मतपेटी आबंटित की जाती थी जिस पर अभ्यर्थी का प्रतीक चिह्न चिपकाया जाता था। अभ्यर्थियों के नामों और प्रतीकों को मतपत्र पर मुद्रित नहीं जाता था और मतदाताओं को अपनी पसंद के अभ्यर्थी के मतपत्र बॉक्स में पूर्व-मुद्रित मतपत्र डालना होता था। इस प्रणाली से विभिन्न हितधारकों के मस्तिष्क में छेड़छाड़, बूथ कैचरिंग और गड़बड़ी की आशंका उत्पन्न होती थी इसलिए जल्द ही इसे बदल दिया गया। वर्ष 1960-61 में, केरल और उड़ीसा में विधान सभाओं के मध्यावधि निर्वाचनों के दौरान मतपत्र पर चिह्नित करने की प्रणाली शुरू की गई और यह प्रणाली 1999 के लोकसभा निर्वाचन तक जारी रही।

ईवीएम का चलन शुरू किए जाने से पहले, भारतीय निर्वाचनों में मत डालने के लिए सर्वव्यापी मतपत्रों का इस्तेमाल काफी सफलतापूर्वक किया जाता था। मतपत्रों के उपयोग में काफी समय लगता था, इसमें बूथ-कैचरिंग और मतपत्र-बक्से को ठूसने जैसी कुप्रथाओं, गलत/त्रुटिपूर्ण रूप से चिह्नित किए जाने की वजह से अमान्य मतों की बड़ी संख्या होने, मतगणना प्रक्रिया के लम्बे समय तक चलने, अधिक संख्या में विवाद होने और परिणाम की विलंब से घोषणा किए जाने की संभावना बनी रहती थी। इन सबके अलावा, यह पारिस्थितिक रूप से विकृतकारी और पर्यावरण के अननुकूल पद्धति थी।

हालांकि, उसकी तुलना में ईवीएम के काफी अधिक तुलनात्मक और उल्लेखनीय फायदे हैं।

- i. ईवीएम द्वारा मतदान करने का तरीका कहीं अधिक सरल और मतदाता-अनुकूल है क्योंकि मतदाता को केवल अपनी पसंद के अभ्यर्थी के पक्ष में अपना मत डालने के लिए बीयू पर बटन दबाना होता है।
- ii. ईवीएम प्रणाली के तहत कोई मत अमान्य नहीं होता है, जबकि मतपत्र पेपर प्रणाली में बड़ी संख्या में मतपत्रों को अविधिमान्य कर दिया जाता था और कुछ मामलों में, ऐसे अविधिमान्य मतपत्रों की संख्या निर्वाचित अभ्यर्थी के विजयी अंतर (मार्जिन) से अधिक होती थी।
- iii. यह प्रणाली लेखा-परीक्षण-योग्य, पारदर्शी, सटीक, सुरक्षित है और मानवीय त्रुटि को कम करने में मदद करती है।
- iv. यह कुछ घंटों में तेजी से परिणाम देती है, जो भारत जैसे बड़े देशों के लिए विशेष रूप से संगत है जिसमें निर्वाचन-क्षेत्रों में कई सौ हजार मतदाता होते हैं और जिनमें मतगणना करने में पहले कई दिन और सप्ताह लगते थे।

- v. इसके अतिरिक्त, ईवीएम मतदान प्रणाली से न केवल समय, ऊर्जा और धन की बचत होती है बल्कि इस प्रक्रिया में लाखों-करोड़ों पेड़ों की भी बचत होती है।
- vi. पहले करोड़ों की संख्या में मतपत्रों को छापना पड़ता था जिसे मुद्रित किए जाने के लिए सैकड़ों टन पेपर की आवश्यकता पड़ती थी और मतपत्रों का मुद्रण-कार्य काफी लंबी समयावधि के लिए बहुत सारे सरकारी मुद्रणालयों में किया जाता था और इन सभी कार्यों में प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में निर्वाचन कर्मचारियों को लगाना पड़ता था।
- vii. इसके अतिरिक्त, देश में मतदान के लिए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिकी में प्रगति के नवोन्मेषी उपयोग से समग्रतः भारतीय समाज की रचनात्मकता, आविष्करिता और पथप्रदर्शक कुशाग्रता को भरपूर प्रोत्साहन मिलता है और यह अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में देश की छवि और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का कार्य करता है।

जैसा कि बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, 7 से अधिक दशकों तक मतपत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, दोनों के साथ निर्वाचनों के संचालन के संचित तुलनात्मक अनुभव का महत्व और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग के असंख्य निर्विवाद फायदे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को मत देने का पसंदीदा साधन बनाते हैं।

एकदम स्पष्ट है कि मतपत्रों का उपयोग एक पारंपरिक, काल-दोषयुक्त और पुरातन मतदान विधि थी। मतपत्रों का उपयोग करने की पूर्ववर्ती परिपाटी से जुड़ी उपर्युक्त समस्याओं को दूर करने के लिए, और प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ अद्यतन बने रहने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग ने 1977 में ईवीएम का विचार प्रस्तुत किया।

वर्ष 1977 में भारत निर्वाचन आयोग के तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री एस.एल. शकधर ने हैदराबाद में एक दौरे के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) से निर्वाचनों को संचालित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करने की संभावना का अध्ययन करने का अनुरोध किया। इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल), हैदराबाद, जो आण्विक ऊर्जा मंत्रालय का एक लोक उपक्रम है, को निर्वाचन संचालित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को अभिकल्पित और विकसित करने का कार्य सौंपा गया। वर्ष 1979 में, एक प्रोटो-टाइप विकसित किया गया और 6 अगस्त, 1980 को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसके प्रचालन का प्रदर्शन किया गया।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), बेंगलुरु, जो रक्षा मंत्रालय का एक उपक्रम है, ने भी "माइक्रोकम्प्यूटर आधारित एक मतदान उपकरण विकसित किया था, जिसका उन्होंने कंपनी के विभिन्न संघों के निर्वाचनों

के लिए इस्तेमाल किया था।" जनवरी 1981 में, ईवीएम का विनिर्माण करने के लिए बी.ई.एल. ने भारत निर्वाचन आयोग से सम्पर्क किया और 29 जुलाई, 1981 को आयोग ने निर्वाचनों में ईवीएम के उपयोग के संबंध में बीईएल, ईसीआईएल, विधि मंत्रालय के प्रतिनिधियों और कुछ राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की।

19 मई, 1982 को, भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम के उपयोग के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निदेश जारी किए और केरल के 70-परूर विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र (एसी) में एक निर्वाचन में मशीनों का उपयोग करते हुए पचास मतदान केंद्रों पर प्रायोगिक आधार पर निर्वाचन संचालित किए। इन ईवीएम का आगे 1982-83 में देशभर के 10 उप-निर्वाचनों में इस्तेमाल किया गया हालांकि, ईवीएम के उपयोग को विहित करने वाले किसी भी विशिष्ट कानून के न होने के कारण निर्वाचन को एक याचिका (एसी जोस द्वारा दायर वर्ष 1982 की निर्वाचन याचिका 01) में चुनौती दी गई और 5 मार्च, 1984 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निर्वाचन में ईवीएम का तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके उपयोग के लिए विधि में कोई विनिर्दिष्ट उपबंध न कर दिया जाए। परिणामतः, संसद द्वारा दिसंबर 1988 में विधि में संशोधन किया गया और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में एक नई धारा 61क अंतःस्थापित की गई। यह संशोधन 5 मार्च, 1989 को प्रवृत्त हुआ। उच्चतम न्यायालय ने अन्नाद्रमुक बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य {(2002 यू.जे.(1)387} के मामले में अपने निर्णय में धारा 61क की संवैधानिक विधिमान्यता अभिनिर्धारित की।

हालांकि, देश के राजनीतिक परिवेश में भारत की मतदान प्रणाली में इस नए प्रवेशक के संबंध में संदेह और अटकलें बनी रहीं। लोगों का भरोसा हासिल करने और नई इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली की प्रामाणिकता की संपुष्टि करने के लिए, भारत सरकार ने जनवरी 1990 में एक निर्वाचकीय सुधार समिति (ईआरसी) स्थापित की, जिसमें श्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में कई राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल थे। ईआरसी ने सिफारिश की कि तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा ईवीएम की जांच की जाए। परिणामतः, श्री एस सम्पत, अध्यक्ष, आरएसी, डीआरडीओ की अध्यक्षता में एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था जिसकी सूची में अन्य लोगों के साथ-साथ डॉ. पी.वी. इंदिरेशन (आईआईटी, दिल्ली), डॉ राव सी. कासारबाडा (ईआर और डीसी, त्रिवेंद्रम) जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक शामिल थे। टीईसी के सदस्य सदैव तकनीकी उत्कृष्टता रखने वाले और प्रतिष्ठित अकादमिक/शोध रिकॉर्डधारी प्रसिद्ध पेशेवर रहे हैं। अप्रैल 1990 में, विशेषज्ञ समिति ने, इसे तकनीकी रूप से सशक्त, सुरक्षित एवं पारदर्शी बताते हुए, सर्वसम्मति से बिना और कोई समय गंवाए ईवीएम के उपयोग की अनुशंसा की। 24 मार्च, 1992 को सरकार द्वारा ईवीएम के उपयोग के संबंध में निर्वाचन संचालन नियम, 1961 में आवश्यक संशोधन अधिसूचित किए गए।

वर्ष 1998 में, भारतीय निर्वाचनों को संचालित करने के लिए ईवीएम के उपयोग पर एक आम सहमति बनी। 1998 में, मध्यप्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के तीन राज्यों में 16 विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया वर्ष 1999 में ईवीएम का उपयोग और आगे बढ़ाकर 46 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया, और बाद में फरवरी 2000 में हरियाणा राज्य विधानसभा मतदानों में 45 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। 2001 में, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन पूरी तरह से ईवीएम का उपयोग करके संचालित किए गए थे। तदुपरांत, सभी राज्य विधानसभा निर्वाचनों में इस मशीन का इस्तेमाल देखा गया।

2004 में, लोकसभा के निर्वाचनों में सभी 543 संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। एक नई प्रौद्योगिकीय रूप से समुन्नत मतदान प्रणाली ने मतपत्रों का उपयोग करने की पूर्ववर्ती मतदान पद्धति को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया। वर्ष 2000 से, भारत में 107 राज्य विधानसभा निर्वाचन और लोकसभा के 3 साधारण निर्वाचन (2004, 2009 और 2014) आयोजित किए गए हैं जिनमें ईवीएम का उपयोग करते हुए मत डाले और रिकॉर्ड किए गए हैं (अनुबंध 1)।

वर्ष 2001 में ईवीएम में कई प्रकार के प्रौद्योगिकीय परिवर्तन किए गए और 2006 में मशीनों को आगे और अधिक स्तरोन्नत किया गया। वर्ष 2006 से पहले के ईवीएम को 'एम1 ईवीएम' के रूप में जाना जाता है, जबकि 2006 से 2010 के बीच विनिर्मित ईवीएम को 'एम2 ईवीएम' कहा जाता है। वर्ष 2013 से उत्पादित ईवीएम को अगली पीढ़ी 'एम 3 ईवीएम' के रूप में जाना जाता है।

भारतीय ईवीएम में नवीनतम परिवर्धन मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) है, जिसका चलन 2013 में ईवीएम आधारित मतदान प्रणाली में पारदर्शिता लाने के एक अतिरिक्त उपाय के रूप में शुरू किया गया था। आयोग द्वारा वीवीपीएटी मॉडल को विकसित करने का कार्य तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) के मार्गदर्शन में ईवीएम विनिर्माताओं को सौंपा गया था।

एक प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया और जुलाई 2011 में तिरुवनंतपुरम (केरल), दिल्ली, चेरापूंजी (मेघालय), जैसलमेर (राजस्थान) और लेह (जम्मू-कश्मीर) में फील्ड परीक्षण आयोजित किए गए। पहले फील्ड परीक्षणों के बाद आयोग ने विनिर्माताओं को निदेश दिया कि वे वीवीपीएटी को फिर से डिजाइन करें।

नए मॉडल के विनिर्माण के बाद जुलाई-अगस्त 2012 में दूसरा फील्ड परीक्षण आयोजित किया गया। 19 फरवरी, 2013 को, टीईसी द्वारा अंतिम मॉडल अनुमोदित किया गया। यह मॉडल 10 मई, 2013 को आयोजित हुई बैठक में राजनीतिक दलों को दिखाया गया था। निर्वाचन संचालन नियम, 1961 में संशोधन किया गया और 14 अगस्त, 2013 को अधिसूचित किया गया, जिससे भारत निर्वाचन आयोग ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का उपयोग करने में सक्षम हुआ। 4 सितंबर, 2013 को, वीवीपीएटी का पहली बार नागालैंड में 51-नोकसेन विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के उप-निर्वाचन में इस्तेमाल किया गया।

इस बीच 8 अक्टूबर, 2013 को, एक जनहित याचिका के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को वीवीपीएटी प्रणाली का चरणबद्ध तरीके से चलन शुरू करने का निदेश दिया। वर्ष 2013 में, भारत निर्वाचन आयोग ने 20,000 वीवीपीएटी का प्रापण किया जिनका विभिन्न निर्वाचनों में इस्तेमाल किया गया। वर्ष 2017 में हाल ही में संपन्न राज्य विधानसभा निर्वाचनों के दौरान पंजाब में 33 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों, मणिपुर में 6 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों, उत्तराखंड में 3 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश में 30 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों और गोवा में 40 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में 53,500 वीवीपीएटी का इस्तेमाल किया गया।

भारतीय निर्वाचनों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम)

दिनांक	घटनाओं का कालक्रम
1977	भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम का विचार प्रस्तुत किया
1979	एक प्रोटो-टाइप विकसित किया गया
6 अगस्त, 1980	राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदर्शन
जनवरी 1981	बीईएल ने ईवीएम के विनिर्माण के लिए भारत निर्वाचन आयोग से संपर्क किया
29 जुलाई, 1981	भारत निर्वाचन आयोग ने बीईएल, ईसीआईएल, विधि मंत्रालय के प्रतिनिधियों और कुछ राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की
19 मई, 1982	ईवीएम का पहली बार केरल में 70-परूर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया
1982-83	ईवीएम का देश के विभिन्न हिस्सों में 10 उप-निर्वाचनों में उपयोग किया गया
5 मार्च, 1984	भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निर्वाचनों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता
दिसंबर 1988	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में एक नई धारा 61क अंतःस्थापित की गई (उच्चतम न्यायालय ने 2001 में धारा 61क की विधिमान्यता को बरकरार रखा)
15 मार्च, 1989	संशोधन प्रवृत्त हुआ
जनवरी 1990	भारत सरकार द्वारा निर्वाचकीय सुधार समिति (ईआरसी) का गठन किया गया
अप्रैल, 1990	तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने ईवीएम के उपयोग की सिफारिश की
24 मार्च, 1992	सरकार द्वारा निर्वाचन संचालन नियम, 1961 में आवश्यकता संशोधन अधिसूचित किए गए
1998	भारतीय निर्वाचनों का संचालन करने के लिए ईवीएम के उपयोग पर एक आम सहमति बनी
1999-2004	विभिन्न राज्य विधानसभा निर्वाचनों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया

2004 - 2014	लोकसभा में लगातार तीन निर्वाचनों में ईवीएम का उपयोग किया गया
14 अगस्त, 2013	वीवीपीएटी का उपबंध करने के लिए निर्वाचन संचालन नियम, 1961 में आगे और संशोधन किए गए और अधिसूचित किए गए
4 सितंबर, 2013,	वीवीपीएटी का पहली बार नागालैंड में 51-नोकसेन विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के उप-निर्वाचन में उपयोग किया गया
8 अक्टूबर, 2013	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को निदेश दिया कि वीवीपीएटी प्रणाली का चरणबद्ध तरीके से चलन शुरू किया जाए
2013 - अब तक	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वीवीपीएटी का चरणों में सीमित संख्या में चलन शुरू किया गया
अप्रैल 2017	2017-18 और 2018-19 के दौरान 3173.47** करोड़ रुपये की लागत से 16,15,000 वीवीपीएटी की खरीद करने के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ। आयोग द्वारा विनिर्माण अत्यावश्यकताओं की शर्त के अधीन सभी अपेक्षित वीवीपीएटी का सितंबर, 2018 तक प्रापण कर लिया जाएगा। ** मूल्य मोलभाव समिति द्वारा कीमत का निर्धारण करने के बाद। 16,15,000 वीवीपीएटी की लागत घटकर रु. 2616.30 करोड़ हो गई।

सामाजिक-राजनैतिक फीडबैक

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के उपयोग का अर्थ है प्रौद्योगिकी और भरोसे, परम्परा और आधुनिकता का सम्मिश्रण, जैसे कि घोड़े द्वारा चालित गाड़ी से आगे बढ़कर मोटर वाहनों का इस्तेमाल करना।

1982 में, जब ईवीएम का पहली बार केरल में इस्तेमाल किया गया था, तो एक अभ्यर्थी सिवान पिल्लई ने निर्वाचन से पहले ही इसके इस्तेमाल को चुनौती दी थी। लेकिन, केरल उच्च न्यायालय ने उसकी चुनौती स्वीकार नहीं की और एक पायलट परियोजना के रूप में ईवीएम का चलन शुरू किया गया। दिलचस्प बात यह है कि चुनौतीकर्ता श्री पिल्लई ने परिणाम घोषित होने पर निर्वाचन जीत लिया। हालांकि, उसके बाद श्री पिल्लई के प्रतिद्वंद्वी ने ईवीएम का चलन शुरू करने को चुनौती दी। उक्त निर्वाचन 1984 में उच्चतम न्यायालय का विनिर्णय आने के बाद पेपर मतपत्रों के साथ फिर से संचालित किया गया।

हालांकि, ईवीएम के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय का 1984 का विनिर्णय विधिक तकनीकी आधार पर था न कि उनकी मौलिक उपयुक्तता पर, और यह विधिक ठहराव वर्ष 1988 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में किए गए संशोधन के माध्यम से ठीक कर दिया गया।

देश के बड़े हिस्सों में बड़े पैमाने पर फैली निरक्षरता और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए भारत में मतदान के लिए ईवीएम के प्रचलन के प्रति कुछ संदेह व्यक्त किया गया। 'ना' कहने वाले व्यक्तियों द्वारा अक्सर यह दलील दी जाती थी कि निर्धन, निरक्षर, वंचित लोगों का विशाल जनसमूह, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में, ईवीएम के प्रति सुगमता में कठिनाईयों एवं परेशानियों का सामना करेंगे और अज्ञानता, मतदान-क्रिया के बारे में जानकारी या जागरूकता के अभाव में मत देने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। हालांकि, आयोग द्वारा शुरू किए गए समेकित एवं संकेंद्रित सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम, (विशेष रूप से ईवीएम के प्रति जागरूकता और जानकारी फैलाने के लिए) और आखिरी निर्वाचक तक पहुंचने की इसकी प्रतिबद्धता ने सभी रुकावटों और आशंकाओं को कारगर रूप से प्रभावहीन कर दिया है। भारतीय समाज के प्रतिनिधिक समूहों को उत्सुकतापूर्वक एवं सकारात्मक रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) अपनाकर अपने मत ईवीएम पर डालते हुए निर्वाचकीय प्रक्रिया में सक्रियतापूर्वक एवं उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए देखकर काफी संतोष एवं खुशी होती है।

निर्वाचकीय परिदृश्य पर ईवीएम के आगमन के बाद से इसके उपयोग पर राजनीतिक दलों और व्यक्तियों सहित विभिन्न पक्षों द्वारा आक्षेप व्यक्त किए जाते रहे हैं। ईवीएम के प्रति व्यक्त की गई चुनौती का सामना करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक असाधारण उपाय के रूप में सभी हितधारकों को 3 से 7 अगस्त, 2009 के बीच एक खुली चुनौती दी कि वे सामने आएँ और यह सिद्ध करके दिखाएँ कि क्या

ईसीआई-ईवीएम में छेड़-छाड़ की जा सकती है। उनमें से कोई भी यह सिद्ध नहीं कर पाया कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है।

वर्ष 2017 में, पांच राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा होने के उपरान्त, कुछ राजनितिक दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर पुनः आशंकाएं व्यक्त की।

विधिक हस्तक्षेप और न्यायालय संबंधी मामले

वर्ष 2001 से विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष ईवीएम के साथ संभावित छेड़छाड़ के मामले उठाए गए हैं। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

- (i) मद्रास उच्च न्यायालय - 2001
- (ii) केरल उच्च न्यायालय - 2002
- (iii) दिल्ली उच्च न्यायालय - 2004
- (iv) कर्नाटक उच्च न्यायालय - 2004
- (v) बॉम्बे उच्च न्यायालय (नागपुर पीठ) - 2004
- (vi) उत्तराखंड उच्च न्यायालय - 2017
- (vii) भारत का उच्चतम न्यायालय, 2017

विश्लेषण: ऊपर उल्लिखित सभी उच्च न्यायालयों ने ईवीएम के प्रयोग से सम्बन्धित प्रशासनिक उपायों और तकनीकी सुदृढ़ता के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया है कि ईवीएम विश्वसनीय, भरोसेमंद और पूर्णतः छेड़छाड़ रहित है। इनमें से कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल अपीलों को खारिज कर दिया है।

वर्ष 2004 में एडवोकेट श्री प्राण नाथ लेखी द्वारा यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया जिन्होंने यह आरोप लगाया कि निर्वाचन परिणामों में यूपीए को लाभ पहुंचाने के लिए ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई थी। परंतु उच्च न्यायालय को इस याचिका में कोई मेरिट नहीं मिली। इस संदर्भ में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि **“निःसंदेह यह आविष्कार इलेक्ट्रॉनिक और कम्प्यूटर तकनीक में एक महान उपलब्धि है और यह एक राष्ट्रीय गर्व का विषय है।”** यह आदेश एक हारे हुए अभ्यर्थी जिन्होंने येलहांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम मशीनों की भूमिका को चुनौती दी थी, द्वारा वर्ष 1999 में दाखिल दलील पर दिया गया था। न्यायालय ने सुरक्षापायों का अध्ययन किया और बीईएल वैज्ञानिकों से पूछताछ की और यह निर्णय दिया कि मशीनें छेड़छाड़ रहित हैं और उनसे छेड़छाड़ किए जाने का कोई भी प्रयास लोगों की नज़रों से बच नहीं सकता है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय, दोनों ने यह पाया कि निर्वाचन में ईवीएम प्रयोग के मतपत्र/मतपेटी निर्वाचन प्रणाली की तुलना में बहुत से लाभ हैं। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने ईवीएम से छेड़छाड़ की किसी भी शंका से स्पष्ट रूप से इंकार किया। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणी पर कृपया ध्यान दिया जाए:

“कोई भी वाइरस या बग इस कारण से प्रारम्भ होने का भी कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि ईवीएम की किसी पर्सनल कम्प्यूटर से तुलना नहीं की जा सकती। कम्प्यूटरों में प्रोग्रामिंग का, जैसा कि सुझाया गया है, ईवीएम से कोई सरोकार नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन वाले कम्प्यूटर की अंतर्निहित सीमाएं होती हैं और उनके डिजाइन के कारण उनमें प्रोग्राम में परिवर्तन किया जा सकता है जबकि ईवीएम स्वतंत्र इकाई है और ईवीएम का प्रोग्राम पूरी तरह से एक भिन्न प्रणाली है”।

बॉम्बे उच्च न्यायालय (नागपुर पीठ) ने कुछेक गवाहों से पूछताछ की जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के क्षेत्र में सुविज्ञ होने का दावा करते थे। तथापि, इन गवाहों ने न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया कि ईवीएम से छेड़छाड़ तब तक संभव नहीं है जब तक कि किसी व्यक्ति को उसके बारे में पूर्ण ज्ञान और मशीनों तक मुक्त पहुंच न हो।

ऐसे मामलों में से एक में माननीय केरल उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 6.2.2002 में ईवीएम प्रणाली की दक्षता पर अपनी सराहना रिकार्ड की है। उक्त निर्वाचन याचिका पर केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील (एआईआर 2003 एससी 2271) में मान्य ठहराया गया था। विभिन्न न्यायालयों के समक्ष यह अभिस्वीकृत किया गया है कि भारत में ईवीएम में प्रयुक्त डाटा या तकनीक पाइरेसी के अधीन नहीं है क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की इसकी विषय-वस्तु के बारे में कुछ भी नहीं जानता है या किसी भी व्यक्ति की ईवीएम तक अनधिकृत या बेरोकटोक पहुंच नहीं है।

अक्टूबर, 2013 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने और अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ईसीआई को चरणबद्ध तरीके से वीवीपीएटी प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की।

माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दिनांक 02 जून, 2017 के अपने निर्णय में निम्नलिखित अनुसार टिप्पणी की:

“प्रथम दृष्टया ईसीआई की संपूर्ण प्रेस रिलीज के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रणाली में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। विनिर्माण के स्तर पर भी इसमें कोई छल-कपट नहीं किया जा सकता। कुंजियों को दबाकर ट्रिज़न हॉर्स को सक्रिय करके भी परिणामों को बदला नहीं जा सकता। ईसीआई-ईवीएम से प्रत्यक्ष रूप से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें माइक्रोकंट्रोलर्स, कुंजियों की डायनामिक कोडिंग, प्रत्येक कुंजी प्रेस करने की तारीख व समय के अंकन आदि का उपयोग करती हैं। इन ईवीएमों के साथ पारवहन के दौरान या भंडारण स्थल पर भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। ईवीएम को छेड़छाड़ - रोधी बनाने के लिए नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था है।”

इसके अतिरिक्त, 09 अगस्त, 2017 को वीवीपीएटी के 100% प्रयोग पर अनेक याचिकाओं पर निर्णय लेते हुए, भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि:

“प्रति-शपथपत्र में निहित भारत निर्वाचन आयोग का उपर्युक्त कथन यह स्वीकार करता है कि याचिकाओं में की गई सभी प्रार्थनाएं पूरी हो गई हैं और उनका समाधान हो गया है। यह भी स्पष्ट है कि भारत सरकार ने निर्वाचनों जो कि निकट भविष्य में होने हैं, की अवधि के दौरान अपेक्षित वीवीपीएटी यूनिटों की खरीद के लिए निधियां संस्वीकृत कर दी हैं। व्यक्त की गई स्थिति संदेह का कोई अवसर नहीं छोड़ती कि आगामी सभी निर्वाचन वीवीपीएटी का प्रयोग करते हुए आयोजित किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रबुद्ध अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान इस अविस्थिति को दोहराया गया था।

उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में हमारा यह सुविचारित मत है कि वर्तमान मामलों में हमारी तरफ से किसी और न्यायनिर्णय की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार द्वारा विधिवत रूप से अनुसमर्थित, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दाखिल प्रति-शपथपत्र के अनुसार सभी मामलों को एक साथ मिलाकर तदनुसार उनका निपटान किया जाता है।”

अभी तक 33 (तीस) मामले विभिन्न न्यायालयों (उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय सहित) में दाखिल किए गए हैं जिनमें ईवीएम से संबंधित मामलों को उठाया गया है। इनमें से 26 (छब्बीस) याचिकाएं न्यायालयों द्वारा पहले ही निरस्त की जा चुकी हैं और शेष न्यायिक प्रक्रियाधीन हैं।

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन: डिज़ाइन और विनिर्माण प्रोटोकॉल:

भारतीय ईवीएम और वीवीपीएटी का विनिर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (परमाणु उर्जा विभाग, भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) द्वारा किया जाता है। ईवीएम के सॉफ्टवेयर को बीईएल और ईसीआईएल के चुनिंदा इंजीनियरों द्वारा एक दूसरे से अलग इन-हाउस रूप से तैयार किया जाता है। कुछ इंजीनियरों का यह चुनिंदा सॉफ्टवेयर विकास समूह सोर्स कोड को डिज़ाइन और तैयार करता है। सॉफ्टवेयर को तैयार करने के पश्चात, सॉफ्टवेयर की अपेक्षित विशिष्टियों के अनुसार (एसआरएस) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अन्य स्वतंत्र परीक्षण समूह द्वारा सॉफ्टवेयर का मूल्यांकन और परीक्षण किया जाता है जो यह सुनिश्चित करता है कि सॉफ्टवेयर को इसके अभिप्रेत प्रयोग हेतु निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार बनाया गया है। ईवीएम हेतु मूल स्रोत कोड को हर समय नियंत्रित स्थितियों के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्टोर किया जाता है और यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सॉफ्टवेयर विकास समूह से बाहर किसी भी व्यक्ति को ज्ञात नहीं होता है।

वर्ष 2010 तक विनिर्मित एम 1 और एम 2 ईवीएम में सोर्स प्रोग्राम कोड से एकत्रित मशीन कोड को एक बारगी प्रोग्रामेबल(ओटीपी) माइक्रो कंट्रोलर में राइटिंग हेतु माइक्रो कंट्रोलर विनिर्माता को दिया जाता है। इस मशीन कोड से वास्तविक मूल स्रोत कोड को रीड नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के ओटीपी माइक्रोकंट्रोलर के लिए एक बार प्रोग्राम किए गए कोड में परिवर्तन नहीं किया जा सकता और किसी भी उपाय से पढ़ा नहीं जा सकता है। तकनीकी प्रगति, पीएसयू परिसरों में मशीन कोड की राइटिंग को चिप में परिवर्तित करने की अनुमति देती है, अतः एम3(2013 के बाद) ईवीएम में प्रोग्राम को पीएसयू परिसर में ही चिप में बर्न किया जाता है। भारत में माइक्रो कंट्रोलर्स तैयार करने के लिए अपेक्षित सुविधाओं के अभाव में इन्हें विदेशी विनिर्माताओं से प्राप्त किया जाता है।

मशीन कोड की प्राप्ति तक माइक्रो कंट्रोलर विनिर्माता पारवहन के दौरान किसी भी परिवर्तन का सत्यापन करते हैं और ओटीपी एरिया में माइक्रो कंट्रोलर में इस कोड को प्रोग्राम करते हैं। इन सैम्पल्स को फिर ईवीएम में एसेंबल किया जाता है और कोड की प्रामाणिकता और कार्यात्मकता हेतु उसका मूल्यांकन और सत्यापन किया जाता है। इस सत्यापन के सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही पीएसयू द्वारा माइक्रो कंट्रोलर विनिर्माता को थोक में निर्माण करने की अनुमति दी जाती है।

फैक्टरी में ईवीएम के उत्पादन के दौरान निर्धारित गुणवत्ता योजना और कार्य निष्पादन परीक्षण प्रक्रियाओं के अनुसार उत्पादन समूह द्वारा कार्यात्मक परीक्षण किया जाता है। उत्पादन समूहों से ईवीएम के नमूनों की गुणवत्ता आश्वासन समूह जो कि पीएसयू के अंदर एक स्वतंत्र इकाई है, द्वारा कार्यात्मकता हेतु नियमित रूप से जांच की जाती है।

ईसीआई को इनकी आपूर्ति के पश्चात, ईवीएम को कड़ी प्रशासनिक और सुरक्षित स्थितियों के अधीन रखा जाता है, इनका पारवहन और उपयोग किया जाता है। जब इनका निर्वाचनों के लिए प्रयोग किया जाता है

तो स्टैकहोल्डरों और मीडिया संवीक्षा की पूर्ण निगरानी में इनका प्रचालन किया जाता है और रखा जाता है।

ईवीएम सॉफ्टवेयर को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि यह मतदाता को केवल एक बार ही वोट डालने की अनुमति देता है। बैलेट यूनिट से मतदाता द्वारा दिए गए वोट को पीठासीन अधिकारी द्वारा कंट्रोल यूनिट पर बैलेट को सक्षम बनाने के बाद ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। मतदाता द्वारा "कैंडीडेट" बटन दबाने पर मतदाता अभ्यर्थी बटन के पास लाल एलईडी जलते हुए देखता है और एक लंबी बीप सुनाई देती है जो यह प्रकट करती है कि मत रिकॉर्ड हो गया है। कंट्रोल यूनिट मशीन का डिज़ाइन इस प्रकार का होता है कि यह बैलेट यूनिट के अलावा अन्य कोई सिग्नल प्राप्त नहीं करता है। यह किसी बाहरी सिग्नल पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देता है (न ही यह किसी भी समय बाहर से कोई सिग्नल प्राप्त ही करता है) अगले मतदाता के लिए कंट्रोल यूनिट पर पीठासीन अधिकारी द्वारा बैलेट एनेबल करने पर ही केवल अगला मत रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस बीच, बीयू बाहर के किसी भी सिग्नल के प्रति निष्क्रिय हो जाता है (कंट्रोल यूनिट के सिग्नल को छोड़कर)। विशेष रूप से डिज़ाइन की गई यह विशिष्ट कि यह 12 सेकण्ड्स से पहले दूसरा वोट स्वीकार नहीं कर सकता है, इस कारण अनेकों वोट इकट्ठे नहीं दिए जा सकते हैं। मतों पर तारीख व समय मुद्रांकित होता है और मतदान से पहले व मतदान के बाद में कोई मत नहीं डाला जा सकता है।

वोटर वेरीफ़ाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम (वीवीपीएटी) का आरंभ वर्ष 2013 में मतदान प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए किया गया था। वीवीपीएटी, ईवीएम से संलग्न एक अतिरिक्त इकाई है जो कि पेपर की एक छोटी पर्ची, जिस पर मतदाता द्वारा मत दिए गए अभ्यर्थी का प्रतीक, नाम और क्रम संख्या होती है, मुद्रित करता है जोकि 'दिखाई पड़ने वाली विन्डो' में 07(सात) सेकंड तक दिखता रहता है। बैलेट यूनिट पर बटन दबाने के पश्चात मतदाता दिखाई पड़ने वाली विन्डो के माध्यम से वीवीपीएटी पर मुद्रित पर्ची देख सकता है और इस प्रकार से वह अपनी पसंद के अभ्यर्थी के लिए रिकॉर्ड किए गए मत का सत्यापन कर सकता है। ये पेपर पर्चियां स्वतः ही कट जाती हैं और वीवीपीएटी के सील किए हुए डिब्बे में स्टोर हो जाती हैं और ईसीआई द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बाद में उन्हें कंट्रोल यूनिट में मतों की दोबारा जांच करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। वीवीपीएटी में पर्चियों का मुद्रण अभ्यर्थी बटन के पास एलईडी लाइट के जलने और ईवीएम सिस्टम में बीप की आवाज होने के अलावा मतदाताओं के लिए एक अतिरिक्त सत्यापन है। वीवीपीएटी को चरणबद्ध रूप में शुरू किया जा रहा है। वर्तमान में निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ ईसीआई के पास 54500 वीवीपीएटी हैं। सरकार के अनुमोदन के अनुसरण में, ईसीआईएल और बीईएल सितम्बर, 2018 तक निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019 के संचालन के लिए अपेक्षित 16,5000 वीवीपीएटी मशीनों के विनिर्माण और आपूर्ति के लिए वचनबद्ध हैं।

ईवीएम संरक्षा और सुरक्षा विशिष्टियां

तकनीकी उपायों और साथ ही ईसीआई द्वारा निर्धारित कड़ी सुरक्षा प्रक्रियाओं, दोनों ही के कारण, ईवीएम मशीनें छेड़छाड़ रहित हैं, जिसके द्वारा कोई भी अप्राधिकृत व्यक्ति ईवीएम/वीवीपीएटी तक अपनी पहुंच नहीं बना सकता है। अतः, ये किसी भी प्रकार की छेड़छाड़/छल कपट से सुरक्षित हैं भले ही यह मतदान पूर्व हो या मतदान के दौरान, उसका भंडारण किया जा रहा हो या विनिर्माता से राज्य/जिले अथवा विलोमतः रूप से पारवहन किया जाए या इसे एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जा रहा हो।

तकनीकी सुरक्षापाय जो ईवीएम को छेड़छाड़ - रहित बनाते हैं, निम्नलिखित हैं:

- (i) आयोग द्वारा प्रयोग की जाने वाली ईवीएम अकेले चल सकने योग्य (स्टैंड अलोन) मशीनें होती हैं और इनमें किसी प्रकार का नेटवर्क नहीं होता है, यह एक-बारगी प्रोग्रामेबल (ओटीपी) मशीन होती है जिसे न तो कम्प्यूटर द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है और न ही ये इंटरनेट या किसी अन्य नेटवर्क से जुड़ी होती हैं और इसलिए इन्हें हैक नहीं किया जा सकता है।
- (ii) इस मशीन के साथ छेड़छाड़ करने/इसमें गड़बड़ी करने से रोकने के लिए इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से संरक्षित किया जाता है। इन मशीनों में प्रयुक्त प्रोग्राम (सॉफ्टवेयर) को एक-बारगी प्रोग्रामेबल (ओटीपी)/मास्कड चिप में बर्न किया जाता है ताकि इसे बदला न जा सके या इससे छेड़छाड़ न की जा सके।
- (iii) ईवीएम के सॉफ्टवेयर को बीईएल (रक्षा मंत्रालय का पीएसयू) और ईसीआईएल (परमाणु उर्जा मंत्रालय का पीएसयू) में एक दूसरे से भिन्न इंजीनियरों के चयनित समूह द्वारा इन-हाउस रूप से तैयार किया जाता है।
- (iv) सॉफ्टवेयर डिजाइन के पूर्ण हो जाने के पश्चात सॉफ्टवेयर अपेक्षाओं के विनिर्देशों (एसआरएस) के अनुसार स्वतंत्र परीक्षण समूह द्वारा सॉफ्टवेयर का मूल्यांकन और परीक्षण किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सॉफ्टवेयर को इसके अभीष्ट प्रयोग के लिए निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार ही तैयार किया गया है।
- (v) ऐसे मूल्यांकन के सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के पश्चात, मशीन कोड माइक्रो कंट्रोलर विनिर्माता को दिया जाता है ताकि इसे माइक्रो कंट्रोलर में राइट किया जा सके। इस मशीन कोड से सोर्स कोड को पढ़ा नहीं जा सकता। सोर्स कोड को कभी भी पीएसयू के सॉफ्टवेयर समूह के बाहर किसी को भी सुपुर्द नहीं किया जाता है।
- (vi) प्रारंभतः, माइक्रो कंट्रोलर विनिर्माता मूल्यांकन हेतु पीएसयू को इंजीनिरिंग नमूने उपलब्ध कराता है। इन नमूनों को ईवीएम में एसेम्बल किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है और व्यापक रूप से इसकी प्रकार्यात्मकता हेतु सत्यापन किया जाता है। इस सत्यापन के सफलतापूर्वक समापन के पश्चात ही पीएसयू द्वारा माइक्रो कंट्रोलर विनिर्माता को थोक में इसका उत्पादन करने की सहमति दी जाती है।
- (vii) ईवीएम के लिए सोर्स कोड को हर समय नियंत्रित परिस्थितियों में रखा जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसकी पहुंच केवल प्राधिकृत व्यक्तियों तक ही हो, जाँच एवं संतुलन बनाया जाता है।

- (viii) फैक्टरी में उत्पादन के दौरान निर्धारित गुणवत्ता योजना और निष्पादन परीक्षण प्रक्रियाओं के अनुसार, उत्पादन समूह द्वारा कार्यात्मक परीक्षण किया जाता है।
- (ix) सॉफ्टवेयर को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि यह मतदाता को केवल एक बार ही मत डालने की अनुमति देता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंट्रोल यूनिट पर बैलेट को सक्षम बनाने के पश्चात ही बैलेट यूनिट से निर्वाचक द्वारा वोट रिकार्ड किया जा सकता है। मशीन किसी भी समय बाहर से कोई सिग्नल प्राप्त नहीं करती है। अगला वोट तभी रिकार्ड किया जा सकता है जब पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट पर बैलेट को सक्षमकारी बना देता है। इस बीच मशीन बाहर के किसी भी सिग्नल (कंट्रोल यूनिट को छोड़कर) के प्रति निष्क्रिय हो जाती है।
- (x) गुणता आश्वासन समूह, जो कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के मध्य एक स्वतंत्र इकाई है, के द्वारा उत्पादन बैचों से ईवीएमों के नमूनों की नियमित जांच की जाती है।
- (xi) ईसीआई-ईवीएम में वर्ष 2006 में कुछ अतिरिक्त विशिष्टियां प्रारंभ की गई थीं यथा **बैलेट यूनिट (बीयू) और कंट्रोल यूनिट (सीयू)** के बीच डाइनेमिक कोडिंग, रियल टाइम क्लॉक लगाना, फुल डिस्प्ले (पूर्ण प्रदर्शन) प्रणाली लगाना और ईवीएम में प्रत्येक कुंजी-दबाने का समय एवं तारीख का मुद्रांकन करना।
- (xii) वर्ष 2006 में तकनीकी मूल्यांकन समिति ने निष्कर्ष निकाला कि वायरलेस या बाहरी या ब्लूटूथ अथवा वाईफाई के माध्यम से कोडेड सिग्नल द्वारा कंट्रोल यूनिट से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती क्योंकि कंट्रोल यूनिट में कोई उच्च आवृत्ति रिसेवर और डाटा डीकोडर नहीं होता है। कंट्रोल यूनिट केवल बैलेट यूनिट से विशेष रूप से कोडीकरण किए गए और डायनेमिक रूप से कोडेड डाटा को ही स्वीकार करता है। कंट्रोल यूनिट द्वारा किसी भी प्रकार के बाहरी स्रोत का कोई भी डाटा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

ईवीएम को हैंडल करने हेतु ईसीआई द्वारा निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रियाएं सख्त हैं

आयोग ने किसी भी संभावित दुष्प्रयोग या प्रक्रियात्मक खामियों का निवारण करने के उद्देश्य से सुरक्षा उपायों तथा प्रक्रियात्मक नियंत्रण एवं संतुलन की व्यापक प्रशासनिक व्यवस्था की है। इन सुरक्षा उपायों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों तथा उनके प्रतिनिधियों के सक्रिय तथा दस्तावेजी समावेशन से प्रत्येक स्तर पर पारदर्शी रूप से लागू किया जाता है ताकि ईवीएम की क्षमता तथा विश्वसनीयता पर उनका विश्वास बनाया रखा जाए। सभी कार्यों और प्रक्रियाओं का जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), रिटर्निंग अधिकारी (आरओ), सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) और अन्य अधिकारी तथा संबंधित राज्य सरकार के पदाधिकारी, जो कि ईसीआई की डीमड प्रतिनियुक्ति पर होते हैं और जो, जहां तक निर्वाचन संबंधी ड्यूटियों का संबंध है, इसके अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण में होते हैं, के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। ये सुरक्षापाय निम्नलिखित हैं:-

- i. प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्माताओं के इंजीनियरों द्वारा निर्वाचन में प्रयोग किए जाने वाली प्रत्येक ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) की जाती है। किसी भी गड़बड़ी वाली ईवीएम अर्थात् या तो ईवीएम

- चालू नहीं हो रही हो या उसमें परिणाम प्रदर्शित नहीं हो रहे हों तो उसे अलग रखा जाता है तथा उसे निर्वाचन में प्रयोग नहीं किया जाता है।
- ii. निर्माणकर्ता प्रथम स्तरीय जांच के समय यह प्रमाणित करते हैं कि ईवीएम में लगे सभी उपकरण वास्तविक हैं। इसके पश्चात, ईवीएम के कंट्रोल यूनिट के प्लास्टिक कैबिनेट को "पिंक पेपर सील" का प्रयोग करके मुहरबंद किया जाता है, जिस पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है और इसे स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। इस चरण के पश्चात, ईवीएम की कंट्रोल यूनिट के प्लास्टिक कैबिनेट को खोला नहीं जा सकता है। ईवीएम के अन्दर के किसी भी उपकरण तक कोई पहुंच नहीं हो सकती है।
- iii. एफएलसी के समय प्रत्येक ईवीएम की कार्यात्मकता पर कुछ मतों के साथ छद्म मतदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त एफएलसी के समय 1% ईवीएमों पर 1200 मत, 2% ईवीएमों पर 1000 मत तथा 2% ईवीएमों पर 500 मत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष डाले जाते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रथम स्तरीय जांच के दौरान इस मॉक पोल के परिणामों का एक प्रिंट आऊट तथा मॉक पोल के दौरान डाले गए प्रत्येक मत का आनुक्रमिक प्रिंट आऊट लिया जाता है तथा राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को दिखाया जाता है। इस प्रयोजन के लिए राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को यादृच्छिक रूप से मशीनें चुनने की अनुमति दी जाती है। शेष मशीनों में, मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए संतोषजनक होती है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को स्वयं मॉक पोल करने की अनुमति होती है। जिला निर्वाचन अधिकारियों/रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा इन सभी का रिकार्ड रखा जाता है।
- iv. तत्पश्चात् स्टोर में रखे गए ईवीएम को मतदान केन्द्रों में वितरित करने से पूर्व अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा दो बार यादृच्छिकीकृत किया जाता है, एक बार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मशीनों को आबंटित करने के लिए तथा दूसरी बार मतदान केन्द्रों में आबंटित करने के लिए। किसी विशेष मतदान केन्द्र को आबंटित ईवीएम की क्रम संख्या वाले ईवीएम की ऐसी सूचियों को राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जाता है। पूर्ण पारदर्शिता हेतु यह यादृच्छिकीकरण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैनात केन्द्रीय प्रेक्षकों और राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ईवीएम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर(ईटीएस) के माध्यम से किया जाता है। किसी विशिष्ट मतदान केन्द्र को आबंटित ईवीएम की क्रम संख्या वाली ईवीएम सूची राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाई जाती है।
- v. ईवीएम की अभ्यर्थी सेटिंग प्रक्रिया के दौरान बैलेट पेपर को बैलेट यूनिट पर फिक्स कर दिया जाता है और ईवीएमों को किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की संख्या हेतु तैयार किया जाता है। यहां यह नोट किया जाए कि मतपत्र में नामों की व्यवस्था और बैलेट यूनिट में नामों की व्यवस्था वर्णानुक्रम में है, पहले राष्ट्रीय और राज्यीय मान्यताप्राप्त दल, उसके पश्चात अन्य राज्यीय पंजीकृत दल और तत्पश्चात निर्दलीय। अतः, वह क्रम जिसमें अभ्यर्थियों के नाम बैलेट यूनिट पर प्रदर्शित होते हैं वह अभ्यर्थियों के नाम और उनकी पार्टी समबद्धता के सापेक्ष होते हैं और उसका

पता पहले नहीं लगाया जा सकता है। बैलेट पेपर में अभ्यर्थियों के नामों के क्रम की यह व्यवस्था वोटों के हेर-फेर हेतु सॉफ्टवेयर के किसी पूर्व-निर्धारित हेर-फेर की संभावना पर प्रभावी ढंग से रोक लगाता है। अतः, किसी विशेष राजनैतिक दल के अभ्यर्थियों की क्रम संख्या प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में अलग-अलग होगी और इसका पहले से निर्धारण नहीं किया जा सकता है, इसलिए गड़बड़ी की किसी भी संभावना से इंकार किया जाता है।

- vi. अभ्यर्थी की सेटिंग पूरी हो जाने पर, ईवीएम के बैलेट यूनिट को भी धागा/पिंक पेपर सील से मुहरबंद किया जाता है ताकि बैलेट यूनिट के भीतरी हिस्से में भी किसी की पहुँच न हो। इन पिंक सीलों पर राजनीतिक दलों/अभ्यर्थी के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर भी दर्ज होते हैं।
- vii. ईवीएम की तैयारी और अभ्यर्थी सेटिंग के समय के दौरान, आरओ एवं उनके नामोद्दिष्ट अधिकारियों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता के लिए अभ्यर्थी या उनके एजेंटों की उपस्थिति में प्रत्येक ईवीएम पर पुनः छद्म मतदान संचालित किया जाता है।
- viii. मतदान के दिन, पीठासीन अधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों/मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर लेकर उनकी उपस्थिति में प्रत्येक मतदान केन्द्र में कम से कम 50 मत डालकर छद्म मतदान संचालित किया जाता है और प्रत्येक पीठासीन अधिकारी से इस आशय का एक छद्म मतदान प्रमाण-पत्र हासिल किया जाता है।
- ix. छद्म मतदान समाप्त होने के पश्चात, सीयू पर सभी बटनों, सिवाय उन बटनों के जिनका उपयोग मतदान के संचालन के लिए किया जाता है, के प्रति अभिगम्यता को अवरुद्ध करने के लिए कंट्रोल यूनिट पर और एक धागा सील और ग्रीन पेपर सील लगाए जाते हैं। इन पेपर सीलों तथा धागा सीलों पर मतदान एजेंटों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की अनुमति दी जाती है। मतदान समाप्त होने के पश्चात, पीठासीन अधिकारी मतदान एजेंटों की उपस्थिति में सीयू पर "क्लोज" बटन दबाते हैं। तत्पश्चात, ईवीएम में कोई भी मत डाला नहीं जा सकता।
- x. उसके पश्चात पूरे ईवीएम को मुहरबंद कर दिया जाता है। अभ्यर्थियों और एजेंटों को सीलों पर अपने हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाती है जिसकी वे मतगणना से पहले मुहर की अक्षुण्णता देखने के लिए जांच कर सकते हैं। अभ्यर्थी/प्रतिनिधि ईवीएम को मतदान केन्द्रों से मतगणना भण्डार गृहों तक ले जाने वाले वाहनों के पीछे चलते हैं।
- xi. इसके अतिरिक्त स्ट्रांग रूम, जिनमें मतगणना हेतु ईवीएम रखे जाते हैं, भी मुहरबंद किए जाते हैं और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल(सीएपीएफ) गार्डों द्वारा चौबीसों घंटे पूरी तरह सुरक्षित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों तथा उनके प्रतिनिधियों को स्ट्रांग रूम पर अपने स्वयं का सील(मुहर) लगाने की अनुमति दी जाती है। उन्हें स्ट्रांग रूम पर चौबीसों घंटे निगरानी करने की भी अनुमति दी जाती है। भण्डारण गृहों के चारों तरफ सुरक्षा बल तीन स्तरों में तैनात किए जाते हैं। जिसमें भीतरी रिंग की रक्षा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) द्वारा की जाती है।
- xii. एफएलसी, मतदान से पूर्व ईवीएम की तैयारी छद्म मतदान आदि अनिवार्यता अभ्यर्थियों अथवा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संचालित किए जाते हैं और उनका विधिवत रूप से दस्तावेज रखा जाता है।

- xiii. ईवीएम के यादृच्छिकीकरण के साथ-साथ मतदान केन्द्रों में प्रतिनियुक्त मतदान कर्मचारियों को भी एक त्रिस्तरीय यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया के माध्यम से यादृच्छिकीकृत किया जाता है।

भण्डारण एवं परिवहन प्रोटोकॉल:

भारत निर्वाचन आयोग निम्नलिखित प्रक्रियाओं एवं अनुदेशों का पालन करके यह सुनिश्चित करता है कि ईवीएम/वीवीपीएटी का भण्डारण एवं परिवहन हर समय ईसीआई के सख्त नियंत्रण के अधीन होता है।

अ. गैर-निर्वाचन अवधि के दौरान:

गैर-निर्वाचन अवधि का अर्थ है वह निर्वाचन याचिका (ईपी) अवधि (यानी पिछले निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से 45 दिन) के बीतने के बाद और निर्वाचन-क्षेत्र में अगले निर्वाचन की घोषणा तक।

ई वी एम का वास्तविक सत्यापन:

गैर-निर्वाचन अवधि के दौरान, जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) द्वारा ई वी एम का शत-प्रतिशत वास्तविक सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ, आयोग ई वी एम-भंडारगारों को खोलने के लिए निदेश जारी करता है। आयोग से निदेश प्राप्त होने पर, जिला निर्वाचन अधिकारी निम्नलिखित कार्रवाई करते हैं:-

- क) मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि ई वी एम-भंडारगारों, जिनमें किसी निर्वाचन याचिका या न्यायालय मामलों से संबंधित ई वी एम रखे गए हैं, को ई वी एम के वास्तविक सत्यापन के प्रयोजनार्थ नहीं खोला जाएगा।
- ख) जिला निर्वाचन अधिकारी ई वी एम-भंडारगार (उपर्युक्त (क) में उल्लिखित ई वी एम-भंडारगार के सिवाय) को खोलने के प्रयोजनार्थ एवं ई वी एम का वास्तविक सत्यापन संचालित करने के लिए एक निर्वाचन प्राधिकारी को नामित करेंगे।
- ग) राष्ट्रीय एवं राज्यीय मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों को ई वी एम भंडारगार खोलने एवं बंद करने की तारीख एवं समय के बारे में कम से कम 24 घंटे पहले लिखित में सूचित किया जाएगा। उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को भंडारगार को खोलने एवं बंद होने के समय उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट पर राजनैतिक दलों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे।

ई वी एम का भंडारण

- i. ई वी एम का भंडारण, जहां कहीं भी संभव हो, कोषागार में किया जाएगा।
- ii. जहां कोषागार में भंडारण नहीं किया गया हो, ईवीएम का भंडारण एक पृथक ऐसे भंडारगार में किया जाना चाहिए जहां ई वी एम से भिन्न कुछ भी नहीं रखा गया हो।
- iii. सामान्यतया, ई वी एम का भंडारण जिला मुख्यालयों में किया जाना चाहिए।

- iv. हालांकि, यदि ई वी एम का भंडारण जिला मुख्यालयों में करना संभव नहीं हो तो ई वी एम भंडारगार तहसील मुख्यालयों से कमतर स्थान पर नहीं किया जाना चाहिए।
- v. किसी भी ई वी एम को आयोग के विशिष्ट अनुमोदन के बिना किसी भी प्रयोजन के लिए ई वी एम भंडारगार से बाहर नहीं रखा जाएगा (अर्थात् सभी ई वी एम को ई वी एम भंडारगार में रखा जाना चाहिए और किसी अन्य स्थान पर नहीं)
- vi. ई वी एम भंडारगार में एक(1) से अधिक प्रवेश बिंदु नहीं होना चाहिए। यदि भंडारगार में कोई अन्य दरवाजे या खिड़कियां हैं तो उन्हें चिनाई या कंक्रीट का प्रयोग करके बंद कर दिया जाना चाहिए।
- vii. ई वी एम भंडारगार के प्रवेश को डबल लॉक सिस्टम से सुरक्षित कर दिया जाना चाहिए। चाबियां जिला निर्वाचन अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में रखी जाएगी तथा प्रत्येक के पास एक चाबी होगी। चाबियों का सौंपा जाना और प्राप्त करना सीटीसी का एक हिस्सा होगा।
- viii. भंडारगार, नमी, कीटो, कृतकों आदि से अवश्य मुक्त होना चाहिए। समुचित अग्निरोधी इंतजाम अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। भंडारगार को बाढ़/जल जमाव के खतरे/दरारों/लीकेज/टूटी खिड़की आदि से मुक्त होना चाहिए। स्ट्रांग रूम में दुर्गंध दूर के लिए वायु-संचलन (एयर-सर्कुलेशन) के लिए इन्लेट/आउटलेट उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन एग्जॉस्ट फैन लगाए जाएं।
 - क) एग्जॉस्ट फैन को स्ट्रांग रूम के अग्रभाग पर लगाया जाएगा जहां सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं न कि पीछे की ओर
 - ख) एग्जॉस्ट फैन को छत के नीचे यथा-संभव उच्चतम बिंदु पर लगाया जाएगा;
 - ग) छिद्र/निकास, जहां एग्जॉस्ट फैन लगाया जाएगा, वहाँ पर एक मजबूत आयरन ग्रिल लगाया जाएगा।
 - घ) ई वी एम को सुरक्षित रीति से रखा जाना चाहिए।
- (ix) चौबीसों घंटे पुलिस/सुरक्षा गार्ड तैनात करके भंडारगार पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किया जाना चाहिए।

ई वी एम का संचलन

गैर-निर्वाचन अवधि के दौरान, ई वी एम को आयोग के विशिष्ट अनुमोदन के बिना ई वी एम भंडारगार के अंदर या बाहर नहीं ले जाया जाएगा। आयोग के निदेश पर ई वी एम के अंतरा राज्य एवं अंतर-राज्य स्थानांतरण की दशा में, निम्नलिखित का सख्ती से पालन किया जाएगा:-

- i. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ई वी एम के स्थानांतरण के बारे में आयोग के निदेश की सूचना संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को देगा।
- ii. जिला निर्वाचन अधिकारी अपेक्षित संख्या में ई वी एम को स्थानांतरित करने के लिए ई वी एम-भंडारगार को खोलने के लिए प्रभारी अधिकारी को लिखित आदेश जारी करेगा (करेंगे)।

- iii. जिला निर्वाचन अधिकारी का लिखित आदेश प्राप्त होने पर नामित अधिकारी बाहर ले जाई जाने वाले ई वी एम को चिह्नित करेगा तथा ऐसे ई वी एम के ब्योरे की प्रविष्टि मास्टर स्टॉक रजिस्टर/संचलन रजिस्टर में करेगा तथा ई वी एम को प्राप्त करने के प्रमाणस्वरूप, ई वी एम प्राप्त करने वाले अधिकारी से लिखित पावती लेगा।

मरम्मत के लिए प्रोटोकॉल:-

मतदान अवधि या गैर-मतदान अवधि के दौरान त्रुटिपूर्ण पाए गए ईवीएम तथा जिनके लिए इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत की आवश्यकता है, उन्हें मरम्मत हेतु बीईएल और ईसीआईएल विनिर्माताओं के पास भेजा जाता है। और उन्हें ईटीएस के अंतर्गत ट्रैक किया जाता है विनिर्माता से मरम्मत की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आयोग द्वारा मरम्मत किए गए ईवीएम आबंटित किए जाते हैं।

ईवीएम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर(ईटीएस):- आयोग ने एक आधुनिक वस्तु-सूची प्रबंधन प्रणाली के रूप में ईटीएस का चलन शुरू किया है जिसमें सभी ईवीएम/वीवीपीएटी की पहचान और वास्तविक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रियल टाइम आधार पर ट्रैक की जाती है और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदेशित इन मशीनों का कोई भी संचलन अनिवार्यतया इस प्रणाली के माध्यम से होगा।

आ. निर्वाचन अवधि के दौरान

ई वी एम का वास्तविक सत्यापन:

यदि वर्ष के दौरान साधारण निर्वाचन है तो जिला निर्वाचन अधिकारी ई वी एम की प्रथम स्तरीय जांच के दौरान ई वी एम का शत-प्रतिशत वास्तविक सत्यापन करेगा और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से विहित फॉर्मेट में आयोग को रिपोर्ट भेजेगा।

ई वी एम का भंडारण

मतदान पूर्व-भंडारण : ई वी एम की प्रथम स्तरीय जांच तथा प्रथम यादृच्छिकीकरण के बाद ई वी एम संबंधित रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर को सौंप दिया जाएगा। रिटर्निंग आफिसर निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे:-

- i) रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर अपने निर्वाचन-क्षेत्र के लिए आबंटित ई वी एम का भंडारण वीडियोग्राफी के अधीन, राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम में करेगा। मतदाताओं के प्रशिक्षण एवं जागरूकता के निमित्त ई वी एम को पृथक स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा ताकि मतदान के निमित्त ई वी एम (रिजर्व ई वी एम सहित) को ई वी एम की तैयारी से पहले खोले जाने की जरूरत न हो। रिजर्व ईवीएम वे ईवीएम होते हैं जिन्हें मतदान के दिन खराब/त्रुटिपूर्ण ईवीएम को बदलने हेतु उपयोग में लाया जाता है। रिजर्व इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें(ईवीएम) मतदानों के लिए नामोद्दिष्ट अन्य ईवीएम की तरह अभ्यर्थी सेटिंग और मतपत्र नियतन के साथ विधिवत रूप से तैयार की जाती हैं और उन्हें सुरक्षा एवं भंडारण प्रोटोकॉलों के उन्हीं मानकों से गुजारा जाता है।

- ii) इसके पश्चात् रिटर्निंग आफिसर ई वी एम (अभ्यर्थी सेटिंग) की तैयारी के समय मतदान के निमित्त ई वी एम (रिजर्व ई वी एम सहित) वाले स्ट्रांग रूम को वीडियोग्राफी के अधीन, अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोलेगा।
- iii) रिटर्निंग आफिसर स्तर पर ई वी एम की तैयारी के बाद, रिजर्व ई वी एम सहित ई वी एम को पुनः वीडियोग्राफी के अधीन, अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा।
- iv) उसके बाद रिटर्निंग आफिसर मतदान दलों के प्रस्थान के दिवस को ई वी एम (रिजर्व ई वी एम सहित) वाले स्ट्रांग रूम को वीडियोग्राफी के अधीन, अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोलेगा।
- v) मतदान के दिन मतदान पूरा होने के बाद, मतदान में प्रयुक्त ई वी एम को वीडियोग्राफी के अधीन, अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में डबल लॉक प्रणाली में भंडारण हेतु स्ट्रांग रूम में हिफाजत से वापस रखा जाएगा।

मतदान में प्रयुक्त ई वी एम का स्ट्रांग रूम में भंडारण के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया:

- (i) सभी पीठासीन अधिकारियों या संग्रहण दलों को वोटिंग मशीनों एवं निर्वाचन कागज पत्रों एवं सामग्री को बिना किसी परिहार्य देरी के भंडारण केन्द्रों में जमा कर देना चाहिए। इस संबंध में चूक करने वाला कोई भी अधिकारी स्वयं को अनुशासनिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाएगा।
- (ii) रिटर्निंग आफिसर किसी विशेष मतदाता केन्द्र से प्राप्त वोटिंग मशीनों को ढेर बनाकर रखने के लिए वर्गों के रूप में फ्लोर स्पेस के विनिर्दिष्ट भाग को भंडारण कक्ष या भवन, नामोद्दिष्ट कर सकता है। इसके लिए व्यवस्था में मतदान केन्द्रों की क्रम संख्या का पालन किया जाना चाहिए।
- (iii) एक मतदान केन्द्र से प्राप्त सभी बैलट यूनिट (टों) तथा कंट्रोल यूनिट को निरपवाद रूप से एक ही वर्गाकार घेरे में एक स्थान पर एक साथ रखा जाना चाहिए। कंट्रोल यूनिट को बैलट यूनिट (टों) के ऊपर रखा जाना चाहिए। प्रत्येक मतदान केन्द्र के संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे गए प्ररूप 17-ग के भाग-1 की एक प्रति मतदान केन्द्र से संबंधित कंट्रोल यूनिट के ऊपर रखी जानी चाहिए। मतदान प्रारंभ होने और मतदान की समाप्ति पर पीठासीन अधिकारियों द्वारा की गई घोषणाओं वाले सीलबंद लिफाफे को भी मतदान में प्रयुक्त ई वी एम के साथ स्ट्रांग रूम में रखा जाना चाहिए। दर्ज मतों के लेखे की डुप्लीकेट प्रति और पेपर सील लेखा की डुप्लीकेट प्रति पीठासीन अधिकारी की डायरी तथा दूसरे रिकॉर्डों तथा मतदाता रजिस्टर (17क), सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेटों की रिपोर्टों, पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त इनपुट (इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेश को देखें) आदि के साथ रिटर्निंग आफिसर की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए। किन्हीं भी परिस्थितियों में, इन कागज-पत्रों/रिकॉर्डों को स्ट्रांग रूम, जहां ई वी एम रखे जाते हैं, में नहीं रखा जाना चाहिए।
- (iv) वोटिंग मशीनों को रखते समय इनकी कतारों के बीच पर्याप्त स्थान छोड़ा जाना चाहिए ताकि बाद में बिना क्रम (मतदान केन्द्रों की क्रम सं. की दृष्टि से) के प्राप्त अन्य मशीनों को पहले प्राप्त एवं रखी गई किन्हीं वोटिंग मशीनों को अन्यत्र ले जाने की आवश्यकता के बिना उनके उपयुक्त आबंटित स्थान पर रखा जा सके।

- (v) यदि किसी अभ्यर्थी की ऐसी इच्छा हो तो उन्हें उस स्थान, जहां वोटिंग मशीनों को मतगणना होने तक रखा जाता है, पर निगरानी रखने के लिए अपने अभिकर्ता को तैनात करने की अनुमति दी जा सकेगी और उन्हें ऐसे भवन, जिसमें मशीनों को रखा गया है, के दरवाजों एवं खिड़कियों पर रिटर्निंग आफिसर द्वारा लगाई गई सील के अतिरिक्त अपनी स्वयं की सील लगाने की अनुमति दी जा सकेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी वोटिंग मशीनें प्राप्त होने एवं उन्हें रखे जाने के तुरंत बाद, रूम को लॉक कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद मतगणना के लिए नियत दिवस की सुबह तक किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। यदि इस अंतराल के दौरान, किसी अपरिहार्य कारण से, कक्ष को खोला जाना हो तो रिटर्निंग आफिसर द्वारा अभ्यर्थियों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को लिखित में सूचना देकर बुलाया जाना चाहिए और उनकी उपस्थिति में कक्ष को खोला जाना चाहिए और उस प्रयोजन, जिसके लिए रूम को खोला जाता है, के पूरा होने के शीघ्र बाद, अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों को पुनः दरवाजे के ताले एवं खिड़कियों पर अपनी सील लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- (vi) जब कभी उस रूम, जिसमें वोटिंग मशीनें रखी गई हैं, को खोलना आवश्यक हो तो लॉग बुक में समुचित प्रविष्टियां दर्ज की जानी चाहिए जिसमें कक्ष में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों, ऐसे प्रवेश करने के प्रयोजन, प्रवेश के समय, बाहर निकलने के समय, गार्डों के हस्ताक्षर आदि का ब्योरा होना चाहिए। ये आदेश मूल मतगणना और पुनर्गणना, यदि कोई है, के बीच अंतराल के दौरान वोटिंग मशीनों के भंडारण पर स्वाभाविक रूप से लागू होंगे।

मतदान उपरांत भंडारण: स्ट्रांग रूम, जहां मतदान में प्रयुक्त ई वी एम को मतगणना के लिए रखा जाता है, की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए निम्नलिखित आदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा-

- i. स्ट्रांग रूम में डबल लॉक सिस्टम होना चाहिए। एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास तथा दूसरी चाबी संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के पास होनी चाहिए।
- ii. मतगणना के लिए मतदान में प्रयुक्त ई वी एम वाले स्ट्रांग रूम के लिए तीन घेराबंदी वाले सुरक्षा इंतजाम चौबीसों घंटे किए जाने चाहिए। केन्द्रीय पुलिस बल को स्ट्रांग रूम के ठीक बाहर सबसे भीतरी परीधीय सुरक्षा व्यवस्था में तैनात होना चाहिए तथा राज्य सशस्त्र पुलिस को सबसे बाहरी परीधीय सुरक्षा के लिए तैनात रहना चाहिए।
- iii. निर्वाचन लड़ रहे सभी अभ्यर्थियों को स्ट्रांग रूम के सुरक्षा इंतजाम पर गहन नजर रखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को तैनात करने हेतु लिखित में सूचित किया जाना चाहिए। उन्हें ऐसे अवस्थान की आंतरिक परिधि के बाहर खड़ा होने की अनुमति दी जानी चाहिए, जहां से वे स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्वार को देख सकें। जहां तक संभव हो, समुचित शेड, पेय जल आदि जैसी सुविधाएं उन्हें प्रदान की जाएंगी। यदि स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्वार को सीधे नहीं देखा जा सकता है तो ऐसे अवस्थान पर सी सी टी वी का इंतजाम किया जाना चाहिए ताकि वे सी सी टी वी पर स्ट्रांग रूम के दरवाजे को देख सकें। ऐसी दशा में, उन्हें स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को देखने, सत्यापित करने और संतुष्ट होने के लिए बैचों में आंतरिक परिधि में आवधिक रूप से ले जाया जाएगा। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और उनके अभिकर्ताओं के लिए चिह्नित स्थान पर एक बड़े टी वी स्क्रीन पर स्ट्रांग रूम को प्रदर्शित करते हुए सीसीटीवी की व्यवस्था की जाएगी ताकि वे स्ट्रांग रूम की अनवरत निगरानी कर सकें।

- iv. स्ट्रांग रूम के निकट नियंत्रण कक्ष को चौबीसों घंटे कार्यशील होना चाहिए।
- v. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ एक राजपत्रित अधिकारी को स्ट्रांग रूम के सुरक्षा इंतजाम के अनुवीक्षण के लिए चौबीसों घंटे ड्यूटी पर रखा जाना चाहिए।
- vi. स्ट्रांग रूम के पास एवं भीतर अग्निशामकों का पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए।
- vii. अप्रयुक्त ई वी एम की सुरक्षा के लिए भी चौबीसों घंटे इंतजाम होने चाहिए।
- viii. निम्नलिखित प्रोटोकॉलों का अनुपालन किए बिना किसी व्यक्ति को आंतरिक परिधि में आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए:-
 - क) केन्द्रीय पुलिस बल द्वारा लॉग बुक रखा जाएगा जिसमें द्वितीय सुरक्षा घेरा अर्थात् मध्य परिधि को पार करने वाले व्यक्ति (यों) के नाम (मों), उसके (उनके) पार करने की तारीख, समय, अवधि के बारे में प्रविष्टि की जानी चाहिए। इसमें प्रेक्षकों, जिला निर्वाचन अधिकारियों या पुलिस अधीक्षकों, या अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं या किसी अन्य व्यक्ति के दौरे शामिल हैं।
 - ख) ऐसे आगंतुकों द्वारा किए गए सभी दौरों का रिकॉर्ड रखने के लिए केन्द्रीय पुलिस बल टुकड़ी को वीडियो कैमरे दिए जाने चाहिए।
- (ix) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ई वी एम रखे जाने की संपूर्ण अवधि के दौरान स्ट्रांग रूम अवस्थानों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस बारे में संबंधित विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष को पृथक रूप से लिखा जाना चाहिए। स्थानीय विद्युत बोर्ड अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाना चाहिए। निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थानापन्न जेनरेटर्स का अनिवार्य इंतजाम किया जाना चाहिए।
- (x) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, भारत निर्वाचन आयोग के प्रभारी उप निर्वाचन आयुक्त तथा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी/पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त/रिटर्निंग आफिसरों के फोन नंबर अभ्यर्थियों को दिए जाने चाहिए जो इसे स्ट्रांग रूम अवस्थान (नों) पर निगरानी रखने वाले अपने प्रतिनिधियों को दे सकेंगे। अभ्यर्थी अपने प्रतिनिधियों को यह सलाह दे सकेंगे कि वे किसी आपात स्थिति में इन अधिकारियों से संपर्क करें।
- (xi) स्ट्रांग रूम के सभी प्रवेश बिंदुओं (दरवाजे आदि) को उपलब्ध वेबकैम एवं लैपटॉप का प्रयोग करके लगातार वीडियोग्राफी के अधीन रखा जाना चाहिए। यदि स्ट्रांग रूम के अन्य दरवाजे हैं तो उन्हें भी वेबकैम/वीडियोग्राफी द्वारा कवर किया जाना चाहिए।
- (xii) रिटर्निंग आफिसर को भंडारण परिसर का (केवल आंतरिक परिधि तक) प्रत्येक दिन सुबह एवं शाम में दौरा करना चाहिए और लॉग बुक एवं वीडियोग्राफी की जांच करनी चाहिए तथा प्रत्येक दिन स्थिति के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट भेजनी चाहिए। जिला मुख्यालय में स्ट्रांग रूम के अवस्थित होने की दशा में, जिला निर्वाचन अधिकारी को यह कार्य करना चाहिए। जहां स्ट्रांग रूम जिला मुख्यालय से बाहर स्थित हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी को यथा संभव बार-बार और कम से कम 3 या 4 दिवसों में एक बार उसका दौरा करना चाहिए।
- (xiii) किसी अधिकारी या मंत्री या किसी अन्य राजनैतिक कार्यकर्ता के वाहन सहित किसी भी वाहन को सुरक्षित परिसर, जहां ई वी एम रखी गई हैं, के भीतर नहीं आने दिया जाना चाहिए। वाहनों से उतरने का

बिंदु बाहरी सुरक्षा परिधि के आगे चिह्नित किया जाना चाहिए, इसके बाद केवल पैदल मार्ग जोन होना चाहिए।

(xiv) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जिलों के भीतर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा तथा प्रोटोकॉल के सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। इस मैनुअल की प्रति सभी अभ्यर्थियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों एवं केन्द्रीय पुलिस बल कमांडेंट को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(xv) मतों की गणना के दिन स्ट्रांग रूम को अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों, रिटर्निंग आफिसर एवं प्रेक्षक की उपस्थिति में विडियोग्राफी के अधीन खोला जाना चाहिए।

(xvi) मतगणना पूरी होने के बाद, कंट्रोल यूनितों को आयोग के विद्यमान अनुदेश के अनुसार सीलबंद कर दिया जाएगा। उसके बाद ई वी एम (बैलट यूनित एवं कंट्रोल यूनित) को सुरक्षित भंडारण के लिए वापस स्ट्रांग रूम में भेज दिया जाना चाहिए।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 94(ए) के तहत निर्वाचन में उपयोग किए जाने के पश्चात और अनुवर्ती निर्वाचनों में उसका इस्तेमाल करने हेतु प्रत्येक ईवीएम की प्रतिधारण अवधि पर आयोग के दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:

(क) प्रत्येक मतदान मशीन (ईवीएम) जिसका इस्तेमाल निर्वाचन में किया गया हो और जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में रखा गया हो, सुरक्षा के मानक प्रोटोकॉल के तहत, निर्वाचन याचिका दाखिल करने की अवधि पूरी होने पर (यानी परिणाम घोषित होने की तारीख से 45 दिन) संबंधित उच्च न्यायालय से निर्वाचन याचिका की स्थिति की पुष्टि किए जाने तक यह अछूती रखी जाए।

(ख) निर्वाचनों के ऐसे मामलों में, जहां कोई निर्वाचन याचिका दायर नहीं की गई है या कोई अन्य अदालती मामले लंबित नहीं हैं, निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम को किसी भी भावी निर्वाचन या किसी अन्य उद्देश्य जैसे संचलन, ईवीएम के भौतिक सत्यापन इत्यादि के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा सकती है।

(ग) ऐसे निर्वाचन के मामले में जहां निर्वाचन याचिका दायर की गई हो, निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी: -

(i) यदि ईवीएम निर्वाचन याचिका की विषय-वस्तु है तो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र में प्रयुक्त ईवीएम को जिला निर्वाचन अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में तब तक रखा जाएगा जब तक कि न्यायालयों द्वारा निर्वाचन याचिका का निपटान नहीं कर दिया जाता।

(ii) यदि निर्वाचन याचिका का विषय ईवीएम नहीं है, तो किसी भी भावी चुनाव या किसी अन्य उद्देश्य जैसे संचलन, ईवीएम के प्रत्यक्ष सत्यापन आदि के लिए संबंधित ईवीएम को स्ट्रांग रूम से बाहर ले जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु संबंधित न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है।

(iii) यदि निर्वाचन याचिका/कोर्ट केस में शामिल न होने वाली ईवीएम, निर्वाचन याचिका/कोर्ट केस में शामिल ईवीएम के साथ जमा हो जाती हैं, तो ऐसी ईवीएम जो निर्वाचन याचिका/कोर्ट केस में शामिल नहीं है, को निर्वाचन याचिका/कोर्ट केस में शामिल ईवीएम से अलग करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा: -

- (क) निर्वाचन याचिका/कोर्ट केस में शामिल ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम को खोलने की सूचना निर्वाचन याचिका/कोर्ट केस दायर करने वाले याचिकाकर्ता/प्रतिवादी और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कम से कम 72 घंटे पहले लिखित रूप में दी जाएगी और स्ट्रांग रूम खोलने के दौरान उनसे उपस्थित रहने का अनुरोध किया जाएगा।
- (ख) जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन याचिका/कोर्ट केस दायर करने वाले याचिकाकर्ता/प्रतिवादी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला जाएगा।
- (ग) स्ट्रांग रूम से बाहर लाने के लिए किसी भी निर्वाचन याचिका/कोर्ट केस में शामिल न होने वाली ईवीएम को निर्वाचन याचिका/कोर्ट केस में शामिल ईवीएम से पृथक करना होगा। स्ट्रांग रूम से इस प्रकार बाहर लाई गई ईवीएम की एक सूची तैयार की जाएगी।
- (घ) केवल उन्हीं ईवीएम को स्ट्रांग रूम से बाहर लाया जाएगा जो किसी भी निर्वाचन याचिका/कोर्ट केस में शामिल नहीं हैं।
- (ङ.) पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।
- (च) स्ट्रांग रूम से बाहर निकाली गई ईवीएम की सूची की प्रतिलिपि और वीडियोग्राफी की प्रतिलिपि निर्वाचन याचिका/कोर्ट केस दायर करने वाले याचिकाकर्ता/प्रतिवादी को दी जाएगी और पावती प्राप्त की जाएगी।
- (घ) यदि कोर्ट केस का कोई अन्य मामला लंबित है, जैसे बूथ कब्जा, आदि, जिसमें कोई ईवीएम संलग्न है, संबंधित मतदान केंद्रों पर इस्तेमाल की गई उस ईवीएम या ईवीएमों को कथित मामले के अंतिम निपटान होने तक रखा जाए।
- (ङ.) निर्वाचन याचिका या कोर्ट केस के अंतिम निपटान के बाद, जैसा भी मामला हो, ऊपर उल्लिखित, ईवीएम का उपयोग आगामी निर्वाचनों के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा परिभाषित सुरक्षा उपायों के साथ तकनीकी सुरक्षा लक्षण एक साथ मिलकर ईवीएम को ऐसा बनाते हैं कि विनिर्माण, भण्डारण, परिवहन या निर्वाचनों के दौरान उपयोग में ईवीएम के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। जबकि

ओटीपी चिप का उपयोग करने जैसी डिजाइन सुविधाएं, कम्प्यूटर, इंटरनेट, किसी अन्य अनचाहे संचार के लिए वायरलेस या वायर के साथ ईवीएम की गैर-कनेक्टिविटी जैसी तकनीकी सुरक्षा, तथा डाटा अखण्डता की रक्षा के लिए एनकोडिंग जैसी अनेक आंतरिक सावधानियां पार्टी के प्रतिनिधियों द्वारा 24X7 संवीक्षा तथा निर्वाचनों के दौरान महत्वपूर्ण स्थानों पर सील करने तथा हस्ताक्षर करने में उनकी भागीदारी के प्रस्ताव देकर प्रशासनिक सुरक्षा उपायों के द्वारा छेड़छाड़ की किसी भी संभावना समाप्त हो जाती है।

इस प्रकार ईसीआई द्वारा उपयोग की जाने वाली भारतीय ईवीएम विश्व में अद्वितीय हैं तथा ईसीआई के नियंत्रण तथा संरक्षण में छेड़छाड़ रहित हैं।

तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी)

ई वी एम पर प्रथम तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन

- केन्द्रीय सरकार ने जनवरी 1990 में निर्वाचन सुधार समिति (गोस्वामी समिति) नियुक्त की जिसमें कई मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों के प्रतिनिधि शामिल थे।
- निर्वाचन सुधार समिति ने महसूस किया कि मशीनों के कार्यकरण की विश्वसनीयता के संबंध में जनता के मन में किन्हीं संदेहों या गलतफहमियों को दूर करने की दृष्टि से मशीनों की जांच तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा की जानी चाहिए और यह इच्छा व्यक्त की कि मशीनों की विश्वसनीयता के बारे में विचार किए गए संदेह एवं गलतफहमी का कोई आधार नहीं है, तकनीकी विशेषज्ञों से एक अनापत्ति प्राप्त की जानी चाहिए।
- ई वी एम के मूल्यांकन के लिए प्रोफेसर एस सम्पत्त, अध्यक्ष तकनीकी सलाहकार समिति, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, प्रोफेसर पी वी इंदिरेसन, आई आई टी दिल्ली और डा. राव सी. कसारबाडा, निदेशक, इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ईआरडीसी, त्रिवेंद्रम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई।
- समिति, अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री की समीक्षा, विनिर्माताओं द्वारा तकनीकी प्रस्तुति, निर्वाचन प्रशासकों, तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक और विस्तृत प्रयोगशाला जांच के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ई वी एम एक सुरक्षित प्रणाली है। इसलिए, विशेषज्ञ समिति ने अप्रैल 1990 में आगे और विलंब किए बिना ई वी एम के प्रयोग की एकमत से सिफारिश की।

द्वितीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन

- आयोग ने इन मशीनों को निर्वाचनों में वास्तविक प्रयोग के लिए अंतिम रूप से स्वीकार करने से पहले उन्नत ई वी एम (वर्ष 2006 के बाद वाली ई वी एम) का मूल्यांकन करवाने के लिए दिसंबर 2005 में एक बार पुनः तकनीकी विशेषज्ञ समिति गठित की जिसमें प्रोफेसर पी. वी. इंदिरेसन, प्रोफेसर डी. टी. साहनी, आई आई टी दिल्ली और प्रोफेसर ए. के अग्रवाल, आई आई टी दिल्ली शामिल थे।

तकनीकी विशेषज्ञ समिति का विस्तार

नवंबर, 2010 में आयोग ने दो और विशेषज्ञों अर्थात् प्रोफेसर डी. के. शर्मा, इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियरिंग विभाग, आई आई टी मुंबई, तथा प्रोफेसर रजत मूना, कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजिनियरिंग विभाग, आई आई टी कानपुर (अब निदेशक, आईआईटी भिलाई) को सम्मिलित करके अपनी तकनीकी विशेषज्ञ समिति का विस्तार किया।

तकनीकी विशेषज्ञ समिति की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:-

1. प्रोफेसर डी.टी. साहनी, आईआईटी दिल्ली
2. प्रोफेसर रजत मूना, निदेशक आईआईटी भिलाई
3. प्रोफेसर दिनेश शर्मा, आईआईटी बोम्बे
4. प्रोफेसर ए.के. अग्रवाला, आईआईटी दिल्ली

तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य अपने संबंधित क्षेत्रों में प्रतिष्ठित अनुभवी तथा विशिष्ट विशेषज्ञ हैं। टीईसी के सदस्यों के पास उनके श्रेय के लिए कई विश्वसनीय और अग्रणी उपलब्धियों के साथ प्रमाणित तकनीकी उत्कृष्टता के साथ एक शानदार अकादमिक रिकॉर्ड है। यह तथ्य कि वे पब्लिक डोमेन में उत्कृष्टता के विभिन्न केन्द्रों से आते हैं जो उनकी क्षमता, योग्यता और विश्वसनीयता को और अधिक बढ़ाता है। ईवीएम/वीवीपीएटी के डिजाइन तथा विकास की दिशा में तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए सराहनीय योगदान की भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा भी प्रशंसा की गई है।

ईवीएम पर तकनीकी विशेषज्ञ समिति की भूमिका

भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम के विशिष्ट तकनीकी लक्षण डिजाइन तथा प्रदर्शन सुधार के मूल्यांकन में सहायता करने के लिए एक स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ समिति बनाई हुई है।

तकनीकी विशेषज्ञ समिति की निम्नलिखित भूमिका रही है:-

- (i) ईवीएम/वीवीपीएटी के नए संस्करणों के विनिर्देशनों तथा डिजाइनों का निर्माण करने के लिए सलाह देना ताकि वे हार्डवेयर और साफ्टवेयर डिजाइन दोनों में नवीनतम तकनीक को शामिल कर सकें और छेड़छाड़ के प्रति सुदृढीकरण में सुधार कर सकें।
- (ii) ईवीएम पर विनिर्माताओं के डिजाइन प्रस्तावों की जांच करना तथा सुधार के लिए संस्तुतियां देना।
- (iii) जहां कहीं अनुरोध किया जाए, डिजाइन प्रक्रिया पर परामर्श देना।
- (iv) ईवीएम में छेड़छाड़ पर उठाए गए संदेहों की जांच करना।
- (v) अन्य कोई सलाह जो आयोग चाहे या कोई अन्य तकनीकी कार्य जो आयोग समय-समय पर सौंप सकता है।

आयोग तकनीकी विशेषज्ञ समिति के साथ नियमित गहन तथा व्यापक बैठकें आयोजित करता है और ईवीएम/वीवीपीएटी के डिजाइन, तकनीकी विनिर्देशनों तथा संबंधित मामलों या समय-समय पर आने वाले किसी भी प्रकार के अन्य तकनीकी मामलों का पुनरीक्षण करता है।

ईवीएम में तकनीक का विकास एवं समावेशन:

ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दोनों, तेजी से विकसित होती तकनीक पर आधारित हैं। मतदान में ईवीएम के उपयोग के साथ सार्वजनिक तथा राजनैतिक दलों से कई उपयोगी सुझाव आए हैं तथा भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम के प्रत्येक संस्करण के साथ नई सुविधाओं को शामिल किया है। इसके साथ ही, समय-समय पर समकालिक सॉफ्टवेयर कार्यप्रणाली में समय अनुसार सुधार हुआ है, समकालिक घटकों में समय अनुसार सुधार हुआ है तथा समकालिक सुरक्षा प्रणाली को यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान में रखा गया था कि प्रत्येक संस्करण के ईवीएम में सबसे अच्छी प्रणाली उपयोग की जा रही है। इसके बावजूद भी ईवीएम की छेड़छाड़-रहित प्रकृति का सभी संस्करणों में सर्वाधिक महत्व रहा है। उस सीमा तक सुरक्षा सुविधाओं का उपयोग उस समय उपलब्ध तकनीक के आधार पर किया गया था तथा ईवीएम की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया गया था। ईवीएम के उपयोग पर भारत निर्वाचन आयोग की सख्त प्रशासनिक पद्धतियों ने ही वर्षों तक ईवीएम के विश्वसनीय अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) की सलाह पर ईवीएम में, समय-समय पर, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के लिए उपलब्ध तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित कुछ लक्षण जोड़े गए थे। इलेक्ट्रॉनिकी में अत्याधुनिक तकनीक की उपलब्धता के कारण ईवीएम के डिजाइन में सुधार किए गए हैं, पूर्व संस्करण के ईवीएम में भी ऐसे मुख्य लक्षण उपलब्ध थे। इन सभी के बावजूद, ईवीएम की छेड़छाड़-रहित प्रकृति का ईवीएम के सभी संस्करणों में सर्वोच्च महत्व रहा है। इसके साथ-साथ ईवीएम के उपयोग पर भारत निर्वाचन की सख्त प्रशासनिक पद्धतियों ने वर्षों तक ईवीएम का विश्वसनीय प्रचालन सुनिश्चित किया है।

तकनीकी प्रगति के कारण एम2(2006के बाद वाली) ईवीएम में तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा कुछ निम्नलिखित नए लक्षण जोड़े गए:-

- (i) बैलेट यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट के बीच सक्रिय कोडिंग।
- (ii) रीयल टाइम क्लॉक
- (iii) कुंजी दबाए जाने का समय-अंकन

तकनीक में नवीनतम विकास के कारण एम3(2013 के बाद वाली) ईवीएम में तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा कुछ निम्नलिखित नए लक्षण जोड़े गए:-

- (i) ईवीएम के सभी संघटक जैसे बीयू, सीयू एव वीवीपीएटी के बीच पारस्परिक अभिप्रमाणन
- (ii) स्वचालित स्व-निदान
- (iii) बैटरी लाइफ भविष्यवाणी
- (iv) कवर खोलने पर निष्क्रिय
- (v) वास्तविक इकाइयों की पहचान के लिए डिजिटल प्रमाणीकरण

एम2 वीवीपीएटी के लक्षण:-

- (i) थर्मल पेपर पर अभ्यर्थी का नाम, क्रम संख्या एवं निर्वाचन प्रतीक का मुद्रण
- (ii) त्रुटि पता लगाने के लिए सेंसर
- (iii) एम2 से एम3 में अद्यतित की जा सकती है।

तकनीकी विकास के कारण एम3 वीवीपीएटी में तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा जोड़े गए लक्षण:-

- (i) 384 अभ्यर्थियों तक का प्रबंधन करने के लिए 01 कंट्रोल यूनिट से जुड़ी 24 बैलेट यूनिट तक जोड़े जाने में सक्षम।
- (ii) बीईएल तथा ईसीआईएल ईवीएम के बीच अंतर-संचालनीयता
- (iii) कवर के खोलने पर निष्क्रिय
- (iv) वास्तविक इकाइयों की पहचान के लिए डिजिटल प्रमाणीकरण।

अन्तर्राष्ट्रीय तुलना:

समय-समय पर यह मुद्दा उठाया जाता है कि कई बाह्य देशों ने मतदान मशीनों का प्रयोग बंद कर दिया है तो भारत में इनका प्रयोग क्यों किया जा रहा है?

पिछले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति होने से निर्वाचन प्रबंधन निकायों, पेशेवरों, विशेषज्ञों तथा कार्यकर्ताओं (विशेषकर ग्रीन एक्टिविस्ट) ने मतपत्र को हाथ से चिह्नित करने के नुकसान से बचाने के लिए विश्व के विभिन्न भागों में कागज रहित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रियाओं पर विचार किया। प्रौद्योगिकी तथा निर्वाचन प्रबंधन का मिलन अरसे पहले 1892 में हुआ था, जब कागजी मतपत्र का लम्बे समय तक प्रयोग किए जाने के पश्चात् न्यूयार्क में पहली 'लीवर वोटिंग मशीनों' का प्रयोग किया गया था। 1960 में, यूएसए में पंच कार्ड मशीनों को शुरू किया गया तथा वहां 1975 में पहला ईवीएम शुरू किया गया। तब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में काफी उन्नति हुई है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के प्रकार:

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया तीन प्रकार की हो सकती है:

- i. निर्दिष्ट मतदान केन्द्रों पर रखी डायरेक्ट रिकार्डिंग मशीनें
- ii. इंटरनेट वोटिंग
 - रिमोट ऑनलाइन वोटिंग
 - निर्दिष्ट मतदान केन्द्रों पर
- iii. ऑप्टिकल स्कैनर
 - स्टैण्ड अलोन (अपने किस्म की अनूठी)
 - परिणामों के केन्द्रीयकृत गणना के लिए नेटवर्क की गई

भारत में प्रयोग की जाने वाली ईवीएम स्टैण्ड अलोन डायरेक्ट रिकार्डिंग मशीनें पहली प्रकार के अंतर्गत आती हैं जिनमें किसी प्रकार की नेटवर्क कनेक्टिविटी की संभावना नहीं है जहां मतदाता निर्वाचन के दिन निर्दिष्ट मतदान केन्द्र पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई सख्त प्रशासनिक सुरक्षा में अपना वोट डालते हैं।

हालांकि भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम भी डायरेक्ट रिकार्डिंग मशीन हैं किन्तु भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम डायरेक्ट रिकार्डिंग या इंटरनेट वोटिंग या ऑप्टिकल स्कैनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग की जाने वाली किसी भी ईवीएम से पूरी तरह से भिन्न है। भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम की जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में प्रयुक्त डीआरएम के साथ विश्लेषणात्मक तुलना करने पर जो स्पष्ट हुआ वह निम्नलिखित है:

नीदरलैण्ड

नीदरलैण्ड में 1990-2007 के मध्य इलेक्ट्रानिक वोटिंग का प्रयोग किया गया। वोटिंग मशीनों का निर्माण एक निजी डच-कंपनी एनईडीएपी (Nederlandse Apparaten Fabrik NV) द्वारा किया गया था। वर्ष 2006 में सरकार ने वोटिंग मशीनों का स्वतंत्र रूप से परीक्षण करने का आदेश दिया। एनईडीएपी मशीनों की सुरक्षा तथा विश्वसनीय विशेषताओं की समीक्षा करने के लिए दो स्वतंत्र आयोग, द वोटिंग मशीन डिजीजन-मेकिंग कमीशन तथा इलेक्शन प्रोसेस एडवायजरी कमीशन (ईपीएसी) की स्थापना क्रमशः 19 दिसम्बर, 2006 तथा 18 जनवरी, 2007 को भी गई थी।

दोनों आयोगों की टिप्पणियों के अनुसरण में, एनईडीएपी मशीनों तथा इलेक्ट्रानिक सुरक्षित वोटिंग को निम्नलिखित कारणों से 2007 में बंद कर दिया गया:-

- नीदरलैण्ड के इंटीरियर और किंगडम रिलेशन मंत्रालय (एसओआईकेआर) को एनईडीएपी के बारे में ज्ञान का अभाव था जिसकी वजह से निर्वाचनों के संचालन के लिए अधिकारियों को बाहरी कार्यकर्ताओं पर निर्भर रहना पड़ता था।
- प्रौद्योगिकी वेंडर निर्णय प्रक्रिया के भाग बन गए और मंत्रालय प्रभावकारी पर्यवेक्षण करने की स्थिति में नहीं था।
- एप्लाइड साइंटिफिक रिसर्च के लिए डच संगठन (Togpast Natuur Wetenschappelijk Onderzoek, TNO) ने इन मशीनों को प्रमाणित किया और इनकी जांच की तथा इन्हें "आउटडेटेड स्टैण्डर्ड" वाला कहा जो आधुनिक प्रौद्योगिकी और सुरक्षा संबंधी खतरों से सुरक्षित नहीं थी।
- इसके अतिरिक्त, प्रमाणीकरण और जांच रिपोर्टों को सार्वजनिक नहीं किया गया जिससे स्वतंत्र विशेषज्ञों को विश्लेषण का सत्यापन करने से वंचित रखा गया।
- विधिक ढांचा, विशेषतौर से आवश्यक सुरक्षा अपेक्षाएं, इलेक्ट्रानिक मतदान प्रक्रिया की विशेषताओं से निपटने के लिए अपर्याप्त था।

(नीदरलैण्ड में इलेक्ट्रानिक मतदान पर व्यापक रिपोर्ट के लिए संपर्क करें:

<https://www.ndi.org/sites/default/files/5netherlands.pdf>)

जर्मनी:

जर्मनी में एनईडीएपी द्वारा निर्मित-ई मतदान मशीनों का प्रयोग इनके आलोचना में आने से पूर्व 2005-2009 के बीच किया गया था और अंत में इन्हें बंद कर दिया गया। द फेडेरल कंस्टिट्यूशन कोर्ट ऑफ जर्मनी ने वर्ष 2009 में एनईडीएपी मशीनों के प्रयोग को निम्नलिखित कारणों से बन्द करने का आदेश दिया।

- एनईडीएपी इलेक्ट्रानिक मशीनों के प्रयोग ने निर्वाचनों की सार्वजनिक प्रकृति, (मूल विधि के अनुच्छेद 20.1 और 20.2 के संयोजन में अनुच्छेद 38) के उस सिद्धांत का उल्लंघन किया जिसकी यह अपेक्षा है कि जब तक अन्य संवैधानिक हित किसी अपवाद को न्यायोचित न ठहरायें, निर्वाचनों में सभी आवश्यक चरण सार्वजनिक परीक्षण के अधीन हैं।

- इसने यह भी पाया कि "नागरिकों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में आवश्यक सोपानों की जांच करना और बिना किसी विशिष्ट विशेषज्ञ की जानकारी से परिणामों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना संभव होना चाहिए"

((निम्नलिखित लिंक में न्याय निर्णय देखें: <http://www.bundesverfassungsgcricht.de/shared/docs/Entscheidung/En/2009/03/cs200903032bvc000307en.html;jessionid=FEA71E86E2CEEo#oFF7AAAC90572279C.2cid383>))

आयरलैंड

आयरलैंड में एनईडीएपी मशीनों का प्रयोग 2002-2004 के बीच किया गया था। इन मशीनों के प्रयोग पर प्रश्न उठाए गए जिसके उपरान्त दो स्वतंत्र आयोग स्थापित किए गए। दोनों आयोगों ने चुनी गई इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली की गोपनीयता, यथार्थता और परीक्षण पर यह निष्कर्ष निकाला कि आयरलैंड निर्वाचनों में प्रयुक्त एनईडीएपी मशीनों का प्रयोग निम्नलिखित आधारों पर नहीं किया जा सकता:-

- अपर्याप्त तकनीकी सुरक्षा उपाय
- सीडी के प्रयोग द्वारा डाटा का असुरक्षित अंतरण
- एकल प्रत्यायित निकाय द्वारा शुरू से आखिर तक व्यापक स्वतंत्र जांच, सत्यापन और प्रमाणीकरण का अभाव ,
- सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मशीनों की भौतिक सुरक्षा में विसंगतियां
- मतदान उपस्कर के भंडारण, परिवहन, व्यवस्थापन, प्रयोग और निपटान के बारे में स्पष्ट नीति निर्देशन का अभाव; और
- इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रों की पहचान, स्थिति और संचालन को रिकार्ड करने के लिए व्यापक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर का अभाव।

(कृपया लिंक देखें:- <http://www.unic.pt/images/stories/publicacoes1/oolIndex.pdf>;
<http://www.unic.pt/images/stories/publicacoes1/part%200%20Index.pdf>)

संयुक्त राज्य अमेरिका

वर्ष 2000 में यूएसए के राष्ट्रपतीय निर्वाचनों में मतदान प्रणाली पर विवाद होने के बाद, मतदान प्रणाली की समीक्षा की गई (स्टीव, गोल्डस्मिथ और टर्नर, 2012:185)। तदनुसार प्रत्यक्ष रिकार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक (डीआरई) प्रणाली (जैसे प्रीमियर इलेक्शन साल्यूशन्स, जिसे साधारणतया डाइबोल्ड कहा जाता है, द्वारा विकसित व्यापक रूप से प्रयुक्त एक्यूवोर टीएस) शुरू की गई। डीआरई प्रणाली तीन बेसिक अंतरापृष्ठों में से एक (पुशबटन, टचस्क्रीन या डायल)" का प्रयोग करती है जिसके माध्यम से "मतदाता अपने मतों को सीधा कंप्यूटर मेमोरी में रिकार्ड करते हैं। मतदाताओं के विकल्पों को मेमोरी कार्ट्रिज, डिसकेट या स्मार्ट कार्ड के माध्यम से डीआरई में स्टोर किया जाता है..... कुछ डीआरई को वोटर वेरिफाइड पेपर आडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) प्रिंटर्स के साथ सुसज्जित किया जा सकता है"। वर्तमान में, यूएसए में 27 राज्यों में डायरेक्ट रिकार्डिंग मशीनों का प्रयोग किया जाता है जिनमें से

15 राज्यों में पेपर आडिट ट्रेल का प्रयोग किया जाता है। अन्य मतदान प्रणालियों में शामिल हैं: ऑप्टिकल स्कैन पेपर बैलेट प्रणाली, बैलेट मार्किंग डिवाइसेज और पंच कार्ड बैलेट।

(लिंक देखें: <http://www.verifiedvoting.org/resorces/voting-equipment/>)

अन्य देश

ब्राजील में, निर्वाचनों में उपयोग की जाने वाली मशीनों को इलेक्ट्रॉनिक बैलेट बॉक्सिस कहा जाता है, जो स्वतंत्र प्रत्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक रिकार्डिंग प्रणाली हैं। वेनेजुएला में एसएटीआईएस (स्मार्टमेटिक आडिटेबल इलेक्शन सिस्टम्स) मतदान मशीनों का उपयोग किया जाता है जिन्हें पूरे देश में वर्ष 2004 में पूरी तरह से क्रियान्वित कर दिया गया था। (स्टीव गोल्डस्मिथ एवं टर्नर 2012: 185)

भारत:

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें विश्व के अन्य भागों में प्रयोग की जा रही ई-वोटिंग मशीनों की तुलना में निम्नलिखित कारणों से अद्वितीय हैं:

- भा.नि.आ. की ईवीएम बेजोड़ और नेटवर्क रहित मशीनें हैं।
- भा.नि.आ. की ईवीएम का निर्माण दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किया जाता है अर्थात् ईसीआईएल और बीईएल, न कि अन्य देशों में प्रयोग की जा रही मशीनों की तरह, जिनका निर्माण पूरी तरह से निजी कंपनियां करती हैं। इस प्रकार से ईसीआई की ईवीएम के निर्णय लेने अथवा इसके निर्माण में निजी व्यापारियों अथवा तकनीकी विक्रेताओं का निहित स्वार्थ होने का कोई अंदेशा या अवसर नहीं रह जाता है।
- ईसीआई की ईवीएम की संपूर्ण जांच प्रक्रिया करने के पश्चात् एक स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा इन्हें बार-बार सफलतापूर्वक प्रमाणित और सत्यापित किया गया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एसटीक्यूसी, एक प्रत्यायित तृतीय पक्ष कंपनी, निर्माताओं द्वारा तैयार ईसीआई की मशीनों का मानकीकरण एवं सत्यापन करती है लेकिन नीदरलैंड में प्रयोग की जाने वाली मशीनों में ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती।
- ईसीआई की ईवीएम में डाटा मशीनों के अन्दर ही स्टोर होता है और इसे किसी भी डिवाइस से अंतरित नहीं किया जा सकता है, जबकि अन्य देशों में जहां डीआरएस में मतदान का डाटा रिकार्ड किया जाता है और इसे सीडी आदि के द्वारा अंतरित किया जाता है।
- आयोग द्वारा ईसीआई की मशीनों के प्रयोग, भण्डारण और परिवहन ट्रेकिंग के लिए संपूर्ण सुरक्षा नियम और प्रशासनिक उपाय किए गए हैं; जबकि अन्य देशों में जहां एनईएपी मशीनों का उपयोग किया जाता है ऐसा नहीं किया गया है
- नीदरलैंड के एमओआईकेआर में ऐसा नहीं किया जाता है किन्तु, आयोग को प्रतिष्ठित प्रोफेसरो वाली एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का संपूर्ण सहयोग मिलता है।
- प्रत्येक ईवीएम पर एक विशिष्ट नम्बर होता है जिसे ईवीएम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्वाचन आयोग के डाटाबेस में रिकार्ड किया जाता है। ईवीएम की इस संख्या की डाटाबेस में कभी भी पुर्नजांच की जा सकती है।

- इन मशीनों में प्रयोग किए गए सॉफ्टवेयर की एक ही बार प्रोग्रामिंग (ओटीपी) की जा सकती है, जिसमें विनिर्माण के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
- देशभर में विधिक ढांचे के अनुसार ईसीआई की ईवीएमस को सदैव कड़ी, एक समान, उच्च स्तर की प्रशासनिक और भौतिक सुरक्षा में रखा जाता है।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61ए के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। देशभर में विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी कई बार विभिन्न निर्णयों में ईवीएम के प्रयोग का अनुमोदन किया गया है और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वर्ष 2004 में ईसीआई की ईवीएम को इसकी पारदर्शिता और अद्भुत क्षमता के कारण इसे “राष्ट्र का गौरव” घोषित किया था।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में भारत निर्वाचन आयोग ने वीवीपीएटी तकनीक प्रारंभ की है ताकि सार्वजनिक परख सुनिश्चित हो सके। वर्ष 2019 तक आयोग पूरे देश में वीवीपीएटी लागू करने के प्रति कटिबद्ध है। इस प्रकार डाले गए प्रत्येक मत की शत प्रतिशत मतदाता प्रामाणिकता और संपरीक्षणता हो जाएगी, जबकि इसके विपरित एनईडीएपी मशीनों में ऐसी सुविधा के अभाव में जर्मनी के उच्चतम न्यायालय ने इन मशीनों के उपयोग को असंवैधानिक कहते हुए इनके उपयोग की अनुमति नहीं दी थी जबकि भारतीय उच्चतम न्यायालय ने देश में निर्वाचनों के आयोजन में ईवीएम के प्रयोग को अनुमोदित किया है।
- अतः ईसीआई की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की किसी अन्य स्थान पर उपयोग की जा रही मशीनों से तुलना करना अव्यावहारिक है।

वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी)

दिनांक 4 अक्टूबर, 2010 को आयोजित सभी राजनैतिक दलों की बैठक में दलों ने ईवीएम के प्रति संतोष प्रकट किया किंतु कुछ दलों ने आयोग से अनुरोध किया कि मतदान प्रक्रिया में आगे और पारदर्शिता एवं सत्यापनीयता (वेरिफायबिलिटी) के लिए वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल का प्रयोग शुरू किया जाए। वीवीपीएटी जैसे उपकरण को न्यूयार्क शहर में पहली बार मार्च 2001 में प्रदर्शित किए जाने और 2002 में सेक्रामेंटो, कैलिफोर्निया में प्रथम बार प्रयोग करने के बाद, भारत में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कुछ समय तक वीवीपीएटी की मांग आती रही। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह मांग तकनीकी विशेषज्ञ समिति के पास भेज दी गई।

वीवीपीएटी का प्रयोग शुरू करने में यह अन्तर्निहित है कि एक पेपर पर्ची जैनेरेट की जाती है जिसमें कंट्रोल यूनिट में वोट की रिकार्डिंग के साथ अभ्यर्थी का नाम एवं प्रतीक विद्यमान रहता है ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में ईवीएम पर प्रदर्शित किए जा रहे परिणाम को सत्यापित करने के लिए पेपर स्लिप की गणना की जा सके। वीवीपीएटी के अधीन बैलटिंग यूनिट के साथ एक प्रिंटर संलग्न किया जाता है और इसे मतदान कम्पार्टमेंट में रखा जाता है। एक पारदर्शी खिड़की के जरिए वीवीपीएटी पर पेपर पर्ची 07 सेकंड के लिए दिखाई देती है। इस बारे में जांच करने और इस पर सिफारिश करने के लिए आयोग ने इस मामले को ईवीएम संबंधी तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) को भेजा। विशेषज्ञ समिति ने ईवीएम निर्माताओं, नामतः बीईएल एवं ईसीआईएल के साथ इस मुद्दे पर अनेक बैठकें की और उसके बाद ईवीएम के साथ वीवीपीएटी प्रणाली के डिजाइन की आवश्यकता का पता लगाने के लिए उन्होंने राजनीतिक दलों और अन्य सिविल सोसाइटी सदस्यों से मुलाकात की।

विशेषज्ञ समिति के निदेश पर, बीईएल एवं ईसीआईएल ने इसकी एक प्रतिकृति बनाई और इसे वर्ष 2011 में समिति एवं आयोग के समक्ष प्रदर्शित किया। ईवीएम एवं वीवीपीएटी प्रणाली संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर, आयोग ने जुलाई 2011 में लद्दाख (जम्मू एवं कश्मीर), तिरुवनंतपुरम (केरल), चेरापूंजी (मेघालय), पूर्वी दिल्ली जिला (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) तथा जैसलमेर (राजस्थान) में वीवीपीएटी के क्षेत्र परीक्षण हेतु छद्म निर्वाचन संचालित किया। राजनैतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं एवं सिविल सोसायटी के सदस्यों सहित सभी हितधारियों ने क्षेत्र परीक्षण में भाग लिया तथा इसे उत्साहपूर्वक देखा। वीवीपीएटी प्रणाली के प्रथम क्षेत्र परीक्षण के बाद, आयोग ने वीवीपीएटी को और अधिक सुचारु बनाने के लिए वीवीपीएटी प्रणाली का विस्तृत पुनर्आकलन किया। तदनुसार, विनिर्माताओं ने वीवीपीएटी प्रतिकृति का दूसरा संस्करण (वर्जन) विकसित किया। इसका पुनः जुलाई-अगस्त 2012 में दूसरा क्षेत्र परीक्षण किया गया।

तकनीकी विशेषज्ञ समिति की 19.02.2013 को आयोजित बैठक में, समिति ने वीवीपीएटी का डिजाइन अनुमोदित किया और आयोग से सिफारिश भी की कि वीवीपीएटी को प्रयोग करने के लिए नियमों के संशोधन के बारे में कार्रवाई की जाए। 10 मई, 2013 को सर्वदलीय बैठक में सभी राजनैतिक दलों के सामने इस मॉडल का प्रदर्शन किया गया। भारत सरकार ने संशोधित निर्वाचन

संचालन नियम, 1961 को 14 अगस्त, 2013 को अधिसूचित किया जिससे आयोग ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का प्रयोग करने में समर्थ हो गया। आयोग ने ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का पहली बार प्रयोग नागालैण्ड के 51-नोकसेन (अनुसूचित जनजाति) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन में 4 सितंबर 2013 को किया।

8 अक्टूबर, 2013 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर अपने न्यायनिर्णय में वीवीपीएटी को चरणों में शुरू करने का आदेश दिया और सरकार से इसके प्रापण के लिए निधियां मंजूर करने के लिए कहा। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने वीवीपीएटी प्रणाली चरणबद्ध तरीके से शुरू की ताकि वर्ष 2019 तक इसे पूरी तरह से क्रियान्वित किया जा सके। वर्ष 2013 में भारत निर्वाचन आयोग ने 20,000 वीवीपीएटी प्राप्त किए। 25 नवंबर, 2013 को मिजोरम की 10 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में, 4 दिसंबर, 2013 को दिल्ली में एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में और उसके बाद अनुवर्ती निर्वाचनों में वीवीपीएटी का प्रयोग आरंभ किया गया।

निम्नलिखित तालिका हमें एक झलक में भारत में वीवीपीएटी के सफर के बारे में बताती है।

दिनांक	कालक्रम के अनुसार घटनाएं
4 अक्टूबर 2010	एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। ईवीएम के साथ वीवीपीएटी शुरू करने पर सहमति बनी।
जुलाई 2011	प्रोटोटाइप निर्मित होने के पश्चात, तिरुवनंतपुरम (केरल), दिल्ली, चेरापूंजी (मेघालय) जैसलमेर (राजस्थान) और लेह (जम्मू-कश्मीर) में फील्ड परीक्षण आयोजित किया गया।
जुलाई-अगस्त 2012	दूसरा फील्ड परीक्षण आयोजित किया गया।
19 फरवरी 2013	तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा अंतिम मॉडल अनुमोदित किया गया
10 मई 2013	सभी राजनीतिक दलों को मॉडल प्रदर्शित किया गया।
14 अगस्त 2013	निर्वाचन संचालन नियम 1961 संशोधित किया गया और अधिसूचित किया गया।
4 सितंबर 2013	भारत निर्वाचन आयोग ने नागालैण्ड में 51 नोकसेन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप-निर्वाचनों में ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का प्रयोग किया।
8 अक्टूबर 2013	उच्चतम न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को चरणबद्ध तरीके से वीवीपीएटी प्रणाली शुरू करने का आदेश दिया। इसे पूरी तरह से 2019 तक क्रियान्वित किया जाना होगा।
25 नवंबर 2013	मिजोरम के 10 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी प्रयोग किए

	गए।
4 दिसंबर 2013	दिल्ली के एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में और उसके बाद अनुवर्ती निर्वाचनों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया।
फरवरी-मार्च 2017	पंजाब में 33 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, मणिपुर में 6 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, उत्तराखंड में 3 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश में 30 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों और गोवा में 40 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 52,000 वीवीपीएटी प्रयोग किए गए।
अप्रैल 2017	सरकार से कुल 3173.47 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत के 16,15,000 वीवीपीएटी की खरीद का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

अभी तक 270 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों एवं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी प्रयोग में लाई गई हैं। वर्ष 2017 में गोवा निर्वाचनों में सभी 40 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी लगाई गई। भारत निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों, जहां हाल ही में निर्वाचन आयोजित किए गए थे, लगभग 53,500 वीवीपीएटी कार्यरत की गई।

वर्तमान मुद्दे एवं विवाद:

मार्च 2017 में राज्य विधान सभा निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के बाद, कुछ राजनीतिक दलों ने ईवीएम को छेड़छाड़ किए जाने योग्य बताते हुए, इसके जरिए निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता के बारे में संदेह व्यक्त किया है और इसीलिए इसे एक अविश्वनीय मतदान उपकरण कहा है।

10.4.2017 को तेरह (13) राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आयोग से मिले और ईवीएम के प्रयोग से की जाने वाली मतदान प्रणाली की पारदर्शिता के बारे में सरोकार जताते हुए उन्होंने एक संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इन दलों के कुछ नेता लोकप्रिय मतों के डाले जाने और उनके रिकार्ड किए जाने के लिए ईवीएम के प्रयोग के खिलाफ अपनी आशंका जताते हुए और अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए या तो भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) से मिले या उन्हें पत्र लिखे। उनके द्वारा आयोग को दी गई याचिकाओं और प्रतिवेदनों के कुछ उद्धरण फिर से नीचे प्रस्तुत हैं:

- “उपर्युक्त के आलोक में, आग्रहपूर्वक अनुरोध है कि (क) वर्तमान राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर/डीआरओ, भिंड, को बदलने/प्रतिस्थापित करने पर विचार करें। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए यह एक न्यूनतम अपेक्षा है। (ख) भारत निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश के दो उप-निर्वाचनों में तैनात की गई सभी मतदान मशीनों की प्रामाणिकता का पुनरीक्षण एवं पुनः सत्यापन करने हेतु निष्पक्ष एवं आरोप-रहित विशेषज्ञों की नियुक्ति का आदेश दे सकता है जिसे राजनीतिक दलों और/या अभ्यर्थियों के अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पारदर्शिता पूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। (ग) यह आवश्यक है कि संपूर्ण प्रक्रिया की फिर से पूर्णतया जांच की जानी चाहिए और मशीनों के अनुरक्षण, प्रचालन और डाटा संभरण से जुड़े व्यक्तियों एवं एजेंसियों और आगे आने वाले निर्वाचनों में ईवीएम के प्रयोग से पहले भंडारण सहित अन्य ड्यूटियों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले सभी पक्षों को विश्वास में लिया जाना चाहिए।
(अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का दिनांकित 01-04-2017 का पत्र)

- “भिंड की घटना के संबंध में, कृपया अपने अधिकारियों की उपस्थिति में उस विशेष मशीन की जांच करने की हमें अनुमति दें।” (आम आदमी पार्टी का दिनांक 03-04-2017 का पत्र)
- यह सभी संबंधित राजनीतिक दलों के सर्वोपरि हित में है कि इन घटनाओं/आरोपों की निष्पक्ष रूप से जांच की जाए और इसके बारे में सच्चाई को भारत की जनता के समक्ष लाया जाए.....। यह अत्यावश्यक है कि भारत निर्वाचन आयोग जिसके पास स्पष्ट, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से राष्ट्रीय और राज्यीय निर्वाचनों का संचालन करने का अधिदेश है, प्रमुख राजनैतिक दलों द्वारा व्यक्त किए गए सरोकारों एवं आशंकाओं पर तब तक

जरूरी रूप से ध्यान दे जब तक कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ एवं गड़बड़ी करने संबंधी मुद्दों का निराकरण न हो जाए और वैश्विक आधार पर ईवीएम की छेड़-छाड़ रहित और परिशुद्ध प्रौद्योगिकी स्थापित एवं पृष्ठांकित न हो जाए तथा राजनीतिक दलों की संतुष्टि के लिए आगामी निर्वाचन पुरानी मतपत्र-प्रणाली के अंतर्गत संचालित किए जाने चाहिए **(राजनीतिक दलों की ओर से दिनांक 10-4-2017 का अभ्यावेदन)**।

- दो और घटानाएं आयोग की जानकारी में लाई गई - एक भिंड (मध्य प्रदेश) से संबंधित और दूसरी धौलपुर (राजस्थान) से संबंधित। घटनाओं की जांच की गई और तथ्य इस प्रकार हैं:
- जहां तक जिला भिंड के अटेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की घटना का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि अटेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप-निर्वाचन 9 अप्रैल 2017 को आयोजित होने थे। 31 मार्च, 2017 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश ने जिला भिंड की अटेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप-निर्वाचन हेतु मतदान की तैयारी की जांच करने के लिए एक संवीक्षा बैठक आयोजित की थी। संवीक्षा बैठक समाप्त करने के बाद, मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश ने वहां उपस्थित मीडिया कर्मियों साथ एक बैठक की और उन्होंने बैठक हॉल के नजदीक आयोजित वीवीपीएटी युक्त ईवीएम मशीन के प्रदर्शन में भाग लिया। वीवीपीएटी युक्त ईवीएम के प्रदर्शन के पश्चात्, बैठक हाल में मीडिया कर्मियों ने कुछेक मुद्दे उठाए और वीवीपीएटी मशीन द्वारा एक विशेष राजनीतिक दल के एक ही प्रतीक के प्रिंट होने के बारे में आरोप लगाए। आयोग ने 31 मार्च 2017 को भिंड में ईवीएम-वीवीपीएटी प्रदर्शन के दौरान उठाए गए मुद्दों के बारे में तत्काल एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह इंगित किया गया कि आरोप पूर्णरूप से अप्रमाणित एवं आधारहीन थे। श्री भंवरलाल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आंध्र प्रदेश के नेतृत्व वाले विशेष जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला कि 31 मार्च, 2017 को अटेर (भिंड) में प्रदर्शन के दौरान प्रयोग की गई ईवीएम एवं वीवीपीएटी में कोई अनियमितता या छेड़छाड़ नहीं पाई गई। 31 मार्च 2017 के प्रदर्शन के मतपत्र यूनिट (बीयू), नियंत्रण यूनिट (सीयू) और वीवीपीएटी की तकनीकी जांच, प्रदर्शन के दौरान उपस्थित अधिकारियों की मौखिक जांच और सीयू से पुनः प्राप्त किए गए आंकड़ों ने अंतिम रूप से यह सिद्ध कर दिया कि प्रदर्शन के दौरान बीयू के 4 बटन निम्नलिखित क्रम से दबाए गए:

बटन सं.	प्रतीक	अभ्यर्थी का नाम
03	हैंड पंप	राजू पाल
04	कमल	सत्य देव पचोरी

03	हैंड पंप	राजू पाल
01	हाथ	अंबुज शुक्ला

इसलिए, यह स्पष्ट है कि 31 मार्च, 2017 को आयोजित प्रदर्शन के दौरान ईवीएम पर चार बटनों को दबाने से सही संगत प्रतीक प्रदर्शित हुए, न कि किसी विशेष दल के प्रतीक प्रदर्शित हुए। आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल आरक्षित वीवीपीएटी को, जोकि निर्वाचन याचिका का हिस्सा नहीं थी, दूसरी जगह में आयोजित किए जा रहे अन्य सभी उप-निर्वाचनों के लिए यथा प्रयोजनीय भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश में कानपुर से लाई गई थी। कोई भी ईवीएम उत्तर प्रदेश से नहीं लाई गई थी।

वास्तव में, 31 मार्च 2017 को सक्षम अधिकारियों द्वारा ईवीएम मशीन के छद्म प्रदर्शन पर आयोग के विहित प्रोटोकालों और अनुदेशों के अननुपालन की वजह से भ्रान्ति पैदा हुई थी, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश, कानपुर जिले में गोविंदनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की वीवीपीएटी में पहले से संचित किए गए प्रतीकों एवं नामों के आंकड़ों को मिटाया नहीं गया था। तथापि, प्रत्येक बटन को दबाने पर एक ही प्रतीक आने वाला आरोप सर्वथा और पूर्णतया गलत एवं निराधार थे। कुछ भी हो, आयोग ने प्रक्रियात्मक चूकों और मौजूदा अनुदेशों के अननुपालन पर गंभीरता से विचार किया और उक्त चूक के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू कर दी। इस संबंध में आयोग द्वारा जारी किया गया विस्तृत प्रेस नोट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे अनुलग्नक-2 के रूप में भी दिया गया है।

धौलपुर की घटना, 9 अप्रैल 2017 को राजस्थान में धौलपुर उप निर्वाचनों में 18 छेड़छाड़ की गई और खराब ईवीएम के बारे में वास्तविक रूप से गलत एवं भ्रामक समाचारों से संबंधित है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि किसी एक दल को दिए गए मत दूसरे दल के रिकार्ड में जा रहे थे। इस संबंध में, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से एक विस्कृत रिपोर्ट मांगी गई और इस मामले की उचित जांच की गई। आरोपों के विपरीत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान द्वारा यह पुष्टि की गई कि मतदान से पहले 8 ईवीएम बदली गई और तैनात की गई 231 में से धौलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में केवल 2 ईवीएम मतदान प्रक्रिया के दौरान खराबी के कारण बदली गई थी, जो 0.1 प्रतिशत से भी कम है। प्रत्येक मतदान के दौरान ईवीएम का 1-2 प्रतिशत खराब हो जाना या अक्रियाशील हो जाना स्वाभाविक है और इन्हें हमेशा बदला जाना पूर्ण रूपेण एक सामान्य घटना है। तथापि, इन खराब ईवीएम में से किसी ईवीएम ने भी कभी गलत या भ्रान्तिपूर्ण परिणाम नहीं दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी सूचित किया कि संपूर्ण मतदान अवधि के दौरान कहीं से भी किसी मतदाता या अभ्यर्थी/राजनैतिक दल की ओर से मतदान की गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं मिली। इस मद के संबंध में आयोग द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और यहां पर अनुलग्नक-3 के रूप में भी दी गई है।

सभी राजनीतिक दलों की बैठक

12 मई, 2017 को सभी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दलों के साथ संविधान क्लब, नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 07 राष्ट्रीय और 35 राज्यीय दलों ने भाग लिया था। बैठक में विचार-विमर्श के मुख्य मुद्दों में से एक मुद्दा, निर्वाचनों के दौरान ईवीएम के साथ वोटर वेरिफायबल पेपर ट्रेल (वीवीपीएटी) का उपयोग किया जाना था।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. नसीम जैदी ने, अपने उद्घाटन संबोधन में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला:

- उन्होंने भिन्ड एवं धौलपुर में उप-निर्वाचनों के दौरान ईवीएम से छेड़-छाड़ के आरोपों की तथाकथित घटनाओं के बारे में कुछ राजनैतिक दलों द्वारा उठाए प्रश्नों का उल्लेख किया तथा दोहराया कि इन घटनाओं के बारे में आधारहीन धारणाएं बनाई गई थीं तथा पक्षपातपूर्ण मतदान परिणाम का कोई मामला नहीं था।
- उन्होंने तकनीकी, प्रशासनिक नयाचार एवं प्रक्रिया के विविध रक्षोपायों पर प्रकाश डाला जो ईवीएम एवं वीवीपीएटी को किसी प्रकार की गड़बड़ी या छेड़-छाड़ की घटना के विरुद्ध सशक्त बनाते हैं।
- उन्होंने सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों को सूचित किया कि आयोग एक चुनौती रखेगा तथा राजनैतिक दलों को यह प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा कि क्या हाल ही में सम्पन्न विधान सभा के निर्वाचनों में प्रयुक्त ईवीएमों से छेड़-छाड़ की गई थी या क्या ईवीएम में निर्धारित तकनीकी एवं प्रशासनिक सुरक्षा के अन्तर्गत भी छेड़-छाड़ की जा सकती है।
- माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सुनिश्चित किया कि आयोग संसदीय एवं राज्य विधान सभा निर्वाचनों के सभी भावी निर्वाचनों में वीवीपीएटी की 100% कवरेज करेगा।

श्री सुदीप जैन, महानिदेशक, भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम के संबंध में एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया जिसमें उन्होंने इसकी सुरक्षित डिजाइन विशेषता, विकास प्रक्रिया, विभिन्न स्तरों पर पणधारियों की सहभागिता तथा ईवीएम को सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं का वर्णन किया।

इस संबंध में जारी किया गया प्रेस नोट **अनुबंध-4** पर है।

ईवीएम चुनौती

सभी राजनैतिक दलों की 12 मई, 2017 को हुई बैठक में आयोग ने राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूचित किया था कि वह एक ईवीएम संबंधी चुनौती रखेगा तथा राजनैतिक दलों को यह प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा कि क्या फरवरी-मार्च, 2017 में सम्पन्न राज्य विधान-सभा के निर्वाचनों में प्रयुक्त ईवीएमों से छेड़-छाड़ की गई थी या क्या ईवीएम में निर्धारित तकनीकी एवं प्रशासनिक सुरक्षा के अंतर्गत भी छेड़-छाड़ की जा सकती है।

आयोग ने ईवीएम संबंधी चुनौती की घोषणा करने के लिए 20 मई, 2017 को एक प्रेस कांफ्रेंस बुलाई थी और 3 जून, 2017 से ईवीएम संबंधी चुनौती में भाग लेने के लिए सभी राष्ट्रीय और राज्यीय मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों को निमंत्रण भेजा था। इस संबंध में जारी प्रेस नोट **अनुबंध-5** पर संलग्न है।

केवल दो राजनैतिक दलों, यथा: राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) ने ईवीएम संबंधी चुनौती में भाग लेने के प्रति अपनी रुचि दिखाई। दोनों दल 3 जून, 2017 को चुनौती स्थल पर पहुंचे। किन्तु, उन्होंने चुनौती में भाग लेने की इच्छा व्यक्त नहीं की बल्कि केवल ईवीएम प्रक्रिया को समझने की ही रुचि व्यक्त की। उन्होंने अपने संदेह दूर करने के लिए आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति से परस्पर और व्यापक वार्तालाप किया।

ईवीएम संबंधी चुनौती 3 जून, 2017 को ही समाप्त हो गई थी और आयोग द्वारा जारी किया गया प्रेस नोट **अनुबंध-6** पर है।

मौजूदा स्थिति:

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 8 अक्टूबर, 2013 के आदेश में कहा है कि वीवीपीएटी पद्धति से ईवीएम मतदान प्रणालीकी परिशुद्धता सुनिश्चित होती है। इस प्रणाली में संपूर्ण पारदर्शिता लाने और मतदाताओं का विश्वास बनाए रखने के लिए ईवीएममें वीवीपीएटी होना आवश्यक है क्योंकि मतदान कुछ नहीं अपितु, अभिव्यक्ति का एक ऐसा कृत्य है जिसका लोकतांत्रिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण स्थान है। उच्चतम न्यायालय ने वीवीपीएटी की शुरुआत करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए प्रयासों और अच्छे कार्यों की प्रशंसा की और इस प्रक्रिया को आगामी साधारण निर्वाचनों में आनुक्रमिक चरणों अथवा भौगोलिक स्थितिवार प्रारंभ करने की अनुमति दी। न्यायालय ने चरणबद्ध ढंग से वीवीपीएटी पद्धति के क्रियान्वयन हेतु वीवीपीएटी की यूनितों की खरीद के लिए भारत सरकार को अपेक्षित वित्तीय सहायता देने का निदेश भी दिया।

ईवीएम के संबंध में चल रहे वाद-विवाद के बीच, भारत निर्वाचन आयोग ने न केवल इन मशीनों की पारदर्शिता, विश्वसनीयता, छेड़-छाड़ रहित होने और मजबूती के संबंध में अपने विश्वास की पुनःपुष्टि की बल्कि मतदान प्रणाली की शुचिता को बचाने और मतदाताओं के विश्वास को मजबूत बनाने के लिए वीवीपीएटी मशीनों के तत्काल परिनियोजन पर भी बल दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी मतदान केन्द्रों पर 100% वीवीपीएटी कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माताओं को निधियों का आबंटन करने के मामले को प्रबलता से उठाया ताकि वीवीपीएटी मशीनों का अपेक्षित मात्रा में समयपूर्वक निर्माण किया जा सके और भारत निर्वाचन आयोग को इनकी आपूर्ति की जा सके। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्माताओं की उत्पादन क्षमता की संपूर्ण समीक्षा भी की और उन पर यह दबाव भी बनाया कि अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर इन मशीनों को देने की समय-सारणी का कड़ाई से पालन करें।

आयोग के निरन्तर अनुवर्तन से 16,15,000 वीवीपीएटी मशीनों की खरीद के लिए 2616.30 करोड़रूपये की धनराशि 19 अप्रैल, 2017 को आबंटित कर दी गई थी और निर्माताओं को आदेश जारी कर दिए गए हैं। यहां उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि एम 3 ईवीएम के उत्पादन के लिए सरकार द्वारा 1939.95 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी जा चुकी है और यह राशि जारी भी की जा चुकी है। निर्माताओं ने इन ईवीएमों और वीवीपीएटी मशीनों के निर्माण और भारत निर्वाचन आयोग को सितम्बर, 2018 तक इनकी आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।

आयोग उन सभी भावी निर्वाचनों में ईवीएम सहित वीवीपीएटी मशीनों का उपयोग करने के लिए कटिबद्ध है, जो संसद और राज्य विधान सभाओं के लिए आयोग के पर्यवेक्षण और दिशा-निर्देशनों के अधीन संचलित किए जाने हैं।

सभी राजनैतिक दलों की 12 मई, 2017 को हुई बैठक में आयोग ने सभी भावी निर्वाचनों में 100% वीवीपीएटी मशीनों का उपयोग करने का निर्णय लिया। आयोग के उपर्युक्त निर्णय को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को 19 सितम्बर, 2017 को औपचारिक रूप से भेज दिया गया था।

निष्कर्ष:

जैसा कि स्पष्ट है, भारतीय निर्वाचनों में प्रयुक्त ईवीएम ने चुनौतियों का सामना करते हुए क्रमिक विकास की एक लम्बी यात्रा तय की है और इसकी शुरुआत से ही पिछले कई वर्षों में यह निर्वाचकीय सुधार की एक प्रभावी मशीन के रूप में उभरी है। इसने लोगों के विश्वास को बढ़ाने के साथ-साथ विश्व की नज़रों में भारतीय निर्वाचनों की वैधता को भी बढ़ाया है।

भारतीय ईवीएम विश्व के अन्य भागों में प्रयुक्त ऐसी सभी मशीनों में सर्वोत्तम विश्वसनीय, छेड़-छाड़ रहित और पारदर्शी मशीनों में से एक है। भारतीय ईवीएमों ने बहुत से अफ्रीकी-एशियाई देशों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। वास्तव में, अभी तक, कोई भी यह प्रदर्शित नहीं कर पाया है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा धारित और इसके द्वारा प्रयुक्त मशीनों में छेड़-छाड़ अथवा हेराफेरी की जा सकती है। जो कुछ भी प्रदर्शित किया जा रहा है अथवा प्रदर्शित किए जाने का दावा किया जा रहा है वह निजी रूप से बनाई गई "भा.नि.आ.- की ईवीएम जैसी दिखने वाली" मशीन पर प्रदर्शित किया गया है, न कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रयुक्त वास्तविक भा.नि.आ. की ईवीएम पर। हाल ही में यह आरोप लगने पर कि भिन्ड(मध्य प्रदेश) और धौलपुर(राजस्थान) में ईवीएमों में डाले गए मत केवल एक राजनैतिक दल को ही जा रहे थे, भारत निर्वाचन आयोग ने तुरंत एक जांच की जिसमें यह पाया गया कि ऐसे समस्त आरोप आधारहीन थे।

आज भारत निर्वाचन आयोग तकनीकी सुरक्षात्मक विशेषताओं और कड़े प्रशासनिक प्रोटोकॉल एवं प्रक्रियात्मक सुरक्षापायों, जिनका मतदान के दौरान और इसके पश्चात् पालन करना अनिवार्य है, को देखते हुए अपनी ईवीएमों के छेड़-छाड़ रहित होने के अपने विश्वास की पुनःपुष्टि करता है। इस संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देना उपयुक्त होगा जिसमें न्यायालय द्वारा कहा गया कि भारत में ईवीएम एक "राष्ट्रीय गर्व" है और सच्चाई यह है कि भारतीय निर्वाचनों को व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर "वैश्विक स्वर्ण मानक" (ग्लोबल गोल्ड स्टैंडर्ड) के रूप में स्वीकार किया जाता है।

आयोग और निर्वाचन प्रणाली के पणधारियों ने एक बोधगम्य निर्णय लिया है कि निर्वाचन प्रबंधन के विकट कार्य और इससे पैदा होने वाली व्यापक संभार-तंत्रीय संबंधी (प्रचालन) चुनौतियों का सटीक उत्तर ईवीएम ही है।

भारत निर्वाचन आयोग यह आशा करता है कि जब देश के समस्त मतदान केन्द्रों में वीवीपीएटी मशीनों का प्रयोग होना आरंभ हो जाएगा तो निर्वाचन संचालन के प्रति विश्वास एवं पारदर्शिता और बढ़ जाएगी।

आयोग का दृढ़ विश्वास है कि सभी भावी निर्वाचनों में वीवीपीएटी युक्त ईवीएम मशीनों का प्रयोग करने से हमारे देश में ईवीएम आधारित मतदान प्रणाली अत्यधिक पारदर्शी और विश्वसनीय हो जाएगी और अंततः इन मशीनों के बारे में समस्त गलत और आधारहीन संदेहों एवं आशंकाओं पर पूर्ण विराम लग जाएगा।

आयोग वीवीपीएटी मशीनों के प्रकार्यों, उपयोग और लाभ के बारे में तथा निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और प्रमाणिकता को सुदृढ़ करने में इसकी अत्यधिक उपयोगिता के बारे में मतदाताओं को

शिक्षित, और जागरूक बनाने के लिए अपनी प्रमुख पहल स्वीप के अंतर्गत एक व्यापक, संगठित और देश-व्यापी मतदाता शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ करेगा। आयोग वीवीपीएटी मशीनों के लाभ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सभी महत्वपूर्ण पणधारियों, विशेषकर राजनैतिक दलों, से नम्रतापूर्वक सहयोग देने का निवेदन करता है। आयोग का विश्वास है कि निर्वाचन प्रक्रिया में सभी पणधारियों के सहयोगपूर्ण प्रयासों से निर्वाचन प्रबंधन में सतत् सुधार होगा और हमारी निर्वाचन प्रणाली और ज्यादा पारदर्शी, सहभागी, संसूचित एवं विश्वसनीय बनेगी।

आयोग निर्वाचन प्रक्रिया में समस्त महत्वपूर्ण पणधारियों के साथ खुले, रचनात्मक और व्यापक वार्तालापमें दृढ़ विश्वास करता है और राजनैतिक दल देश में लोकतांत्रिक स्तंभ के प्रभावी पणधारी हैं, ईवीएमों के प्रयोग से संबंधित हालिया मुद्दों पर विचार करते हुए, आयोग ने 12 मई, 2017 को सभी दलों की एक बैठक आयोजित की। उक्त बैठक का प्रयोजन इस अति आवश्यक मुद्दे पर निर्वाचकीय कार्यक्षेत्र (एरिना) में महत्वपूर्ण प्रतिभागियों के बीच गहन वार्तालाप और विस्तृत विचार-विमर्श करने को सुगम बनाना था ताकि बैठक में समस्त विचार और प्रति-विचारों को रखा जा सके तथा इन पर पारदर्शी और ठोस निर्णय लिया जा सके।

सभी राजनैतिक दलों की बैठक में आयोग द्वारा संसद और राज्य विधान सभा के सभी भावी निर्वाचनों में वीवीपीएटी की 100%कवरेज सुनिश्चित की गई। इस बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूचित किया गया था कि आयोग एक चुनौती रखेगा और राजनैतिक दलों को यह प्रदर्शित करने का अवसर देगा कि क्या हाल ही में सम्पन्न विधान सभाओं के निर्वाचनों में उपयोग की गई ईवीएमों से छेड़-छाड़ की गई थी अथवा क्या ईवीएमों में निर्धारित तकनीकी एवं प्रशासनिक सुरक्षा के अंतर्गत भी छेड़-छाड़ की जा सकती है।

इसके पश्चात् 20 मई, 2017 को आयोग ने ईवीएम चुनौती की घोषणा की और सभी राष्ट्रीय और राज्यीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को 3 जून, 2017 से चुनौती में भाग लेने का निमंत्रण भेजा। केवल दो राजनैतिक दलों, यथा: राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया(माक्सवादी) ने ईवीएम चुनौती में भाग लेने की इच्छा प्रकट की। किन्तु, उन्होंने चुनौती में भाग नहीं लिया बल्कि केवल ईवीएम प्रक्रिया को समझने में रुचिदिखाई। उन्होंने अपने संदेह दूर करने के लिए आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति से विस्तृत वार्तालाप किया। ईवीएम की चुनौती 3 जुलाई, 2017 को समाप्त हुई।

12 मई, 2017 से संसद और राज्य विधान-सभा के प्रत्येक निर्वाचन के आयोजन में वीवीपीएटी युक्त ईवीएममशीनों का उपयोग किया गया है और आयोग संसद और राज्य विधान-सभा के सभी भावी निर्वाचनों में 100% वीवीपीएटी मशीनों के परिनियोजन के लिए कटिबद्ध है।

आयोग सभी नागरिकों और पणधारियों से अनुरोध करता है कि वे हमारी निर्वाचन प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक, सतर्क, और सचेत रहें तथा आयोग को देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संचालित करने के अपने संवैधानिक अधिदेश का निर्वहन करने में सहयोग दें।

अनुबंध-1

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	निर्वाचन, जिनमें ईवीएमों का उपयोग किया गया			
	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष
आन्ध्र प्रदेश	2004	2009	2014	
अरुणाचल प्रदेश	2004	2009	2014	
असम	2001	2006	2011	2016
बिहार	2000	2005	2010	2015
छत्तीसगढ़	2000	2003	2008	2013
गोवा	2002	2007	2012	2017
गुजरात	2002	2007	2012	
हरियाणा	2000	2005	2009	2014
हिमाचल प्रदेश	2003	2007	2012	
जम्मू-कश्मीर*	2000	2004	2009	2014
झारखण्ड	2000	2005	2010	2014
कर्नाटक	2004	2008	2013	
केरल	2001	2006	2011	2016
मध्य प्रदेश	2003	2003	2013	
महाराष्ट्र	2004	2009	2014	
मणिपुर	2002	2007	2012	2017
मेघालय	2003	2008	2013	
मिज़ोरम	2003	2008	2013	
नागालैण्ड	2003	2008	2013	
उड़ीसा	2000	2004	2009	2014
पंजाब	2002	2007	2012	2017
राजस्थान	2003	2008	2013	
सिक्किम	2004	2009	2014	
तमिलनाडु	2001	2006	2011	2016
त्रिपुरा	2003	2008	2013	
उत्तर प्रदेश	2002	2007	2012	2017
उत्तराखण्ड	2002	2007	2012	2017

पश्चिम बंगाल	2001	2006	2011	2017
दिल्ली	2003	2008	2013	2015
पुडुचेरी	2001	2006	2011	2016

कुल : 107 राज्य विधान सभा निर्वाचन

वर्ष 2004, 2009 और 2014 में लोकसभा के साधारण निर्वाचनों में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में भी ईवीएमों का प्रयोग किया गया था।

अनुबंध - 2

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.प्रेस नोट/34/2017

दिनांक: 7 अप्रैल, 2017

प्रेस विज्ञप्ति

विषय: भिंड (मध्य प्रदेश) प्रकरण पर जांच रिपोर्ट

श्री भंवर लाल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आन्ध्र प्रदेश के नेतृत्व वाले विशेष जांच दल ने आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। दल ने यह पाया है कि 31 मार्च, 2017 को अटेर(भिंड) में प्रदर्शन के दौरान प्रयोग की गई ईवीएम तथा वीवीपीएटी में कोई विसंगति नहीं है या इसमें कोई छेड़-छाड़ नहीं हुई है। मीडिया में तथा राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए विभिन्न आरोपों के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जांच कराई गई थी।

2. 31 मार्च के प्रदर्शन के बैलेट यूनिट(बी यू), कंट्रोल यूनिट (सी यू) तथा वीवीपीएटी की तकनीकी जांच, प्रदर्शन के दौरान वहां उपस्थित अधिकारियों की मौखिक जांच, सी यू से प्राप्त किए गए डाटा ने यह निश्चित तौर पर सिद्ध कर दिया है कि प्रदर्शन के दौरान बी यू के चार बटनों को निम्नलिखित क्रम में दबाया गया था:

बटन सं	प्रतीक	अभ्यर्थी का नाम
03	हैंडपम्प	राजू पाल
04	कमल	सत्यदेव पचोरी
03	हैंडपम्प	राजू पाल
01	हाथ	अम्बुज शुक्ला

अतः यह स्पष्ट है कि प्रदर्शन के दौरान ईवीएम पर विभिन्न बटनों को दबाए जाने पर संबंधित प्रतीक दिखाई दिए थे।

3. दल ने अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला कि यह कहना पूर्णतः असत्य है कि 31 मार्च को यथा आरोपित प्रदर्शन के दौरान विभिन्न बटनों को दबाने पर अनेक बार कमल की पर्चियां मुद्रित हुई थी।

4. कानपुर नगर के गोविन्द नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, जहां से वीवीपीएटी (ईवीएम नहीं) प्राप्त की गई थी, के पूर्व के अपलोड किए गए डाटा को नहीं हटाए जाने से और आयोग के निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार प्रदर्शन से पहले डमी अभ्यर्थियों के प्रतीक/डाटा को पुनः अपलोड किए जाने से संबंधित चूक के कारण आयोग द्वारा उपयुक्त कार्रवाई करना आवश्यक है।

आरोपों पर जांच समिति का निष्कर्ष निम्नानुसार है:

1. भिंड में प्रदर्शन में प्रयोग की गई ईवीएम उत्तर प्रदेश से नहीं लाई गई थी। तथापि, प्रदर्शन में प्रयोग की गई वीवीपीएटी उत्तर प्रदेश से लाई गई थी। चूंकि वीवीपीएटी सीमित संख्या में हैं तथा 5 राज्यों के पिछले निर्वाचनों के दौरान सभी निर्वाचनरत राज्यों द्वारा प्रयोग की गई थी, अतः आयोग द्वारा 10 राज्यों के उप-निर्वाचनों के लिए वीवीपीएटी का वितरण निर्वाचन कराए गए विभिन्न राज्यों से निर्वाचन करवाए जाने वाले विभिन्न राज्यों को वीवीपीएटी आबंटित करते हुए किया गया था। इस मामले में, वीवीपीएटी उत्तर प्रदेश से आबंटित की गई थी और इसे कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश के गोविन्द नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मंगाया गया था।
2. उत्तर प्रदेश से वीवीपीएटी मंगवाया जाना कानून का उल्लंघन नहीं है। विधि के अनुसार, केवल मतदान में प्रयोग की गई ईवीएम तथा बक्से में रखी गई वीवीपीएटी पर्चियों को ही निर्वाचन याचिका, यदि कोई हो, के उद्देश्य से, 45 दिनों की अवधि के लिए संरक्षित किया जाना अपेक्षित है। वीवीपीएटी मशीनों को हटाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि इन्हें निर्वाचन याचिकाओं के लिए संरक्षित किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः **वीवीपीएटी के माध्यम से मुद्रित तथा बक्से में रखी पेपर पर्चियों को अलग से सुरक्षित रखा जाना अपेक्षित है।** इस मामले में तथापि, मतदान के दौरान एवजी के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए केवल आरक्षित रखी गई वीवीपीएटी को ही ले जाकर अत्याधिक सावधानी बरती गई थी, जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है।

समिति ने संस्तुति की है कि-जांच निर्णायक रूप से यह प्रमाणित करती है कि :-

1. उक्त ईवीएम/वीवीपीएटी सहित ईवीएम तथा वीवीपीएटी, की कार्य प्रणाली की सटीकता संदेह से परे है।
2. जांच रिपोर्टों में पाई गई चूकों के लिए आयोग जिला निर्वाचन अधिकारी तथा रिटर्निंग अधिकारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकता है।
3. आयोग ईवीएम/वीवीपीएटी से संबंधित प्रत्येक क्रियाकलाप को निष्पादित करने के लिए जांच सूची निर्धारित कर सकता है जिसका निर्वाचन प्राधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए तथा इसकी आयोग द्वारा एमआईएस ऑनलाइन के माध्यम से निगरानी की जानी चाहिए। समय-समय पर जारी किए गए विद्यमान अनुदेशों को इन जांच सूचियों के रूप में, संकलित किया जाए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम/वीवीपीएटी पर विभिन्न क्रियाकलापों को निष्पादित किए जाने के संबंध में निर्धारित उक्त संशोधित जांच सूचियों का पीठासीन अधिकारी से लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर तक की समस्त निर्वाचन मशीनरी द्वारा अनिवार्य रूप में सख्ती से अनुपालन किया जाए।
4. आयोग यह दोहराना चाहता है कि निर्वाचकीय मामलों को निष्पादित करने में लापरवाही और कम से कम अनुपयुक्त टिप्पणियों का तो कोई स्थान नहीं है क्योंकि निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता ही भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है।

ह0/-
(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक

अनुबंध - 3

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

ईसीआई/प्रेनो/35/2017

दिनांक: 11 अप्रैल, 2017

प्रेस नोट

विषय: धौलपुर उप-निर्वाचन के संबंध में स्पष्टीकरण।

मीडिया के एक वर्ग ने खबर दी है कि दिनांक 09 अप्रैल, 2017 को धौलपुर, राजस्थान में आयोजित उप निर्वाचन के दौरान 18 ईवीएम खराब हो गईं। इन रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि एक पार्टी को दिए गए वोट दूसरी पार्टी को जा रहे थे।

इस संबंध में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है और सीईओ ने पुष्टि की है कि मतदान प्रक्रिया के दौरान लगाई गई 231 मशीनों में से केवल 02 ईवीएम को ही किसी खराबी की वजह से बदला गया था जो कि 0.1 प्रतिशत से भी कम है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी सूचित किया है कि संपूर्ण मतदान अवधि के दौरान किसी मतदाता या अभ्यर्थी/राजनैतिक दल द्वारा कहीं से भी मतदान में गड़बड़ी होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के पास ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचन कराने का संवैधानिक अधिदेश नहीं है।

उपर्युक्त के आलोक में, मीडिया के एक वर्ग में उल्लिखित रिपोर्टें गलत एवं आधारहीन पाई गई हैं।

ह0/-
(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक

अनुबंध - 4

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

प्रेस नोट

सं.ईसीआई/पीएन/39/2017

दिनांक: 12 मई, 2017

विषय: ईवीएम/वीवीपीएटी तथा अन्य निर्वाचन संबंधी सुधारों से संबंधित मामलों पर सभी राजनैतिक दलों की बैठक।

निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के साथ आज संविधान क्लब, नई दिल्ली में बैठक आयोजित की:-

- i) ईवीएम तथा वीवीपीएटी।
- ii) निर्वाचनों में रिश्वत को संज्ञेय अपराध बनाना।
- iii) निर्वाचनों में रिश्वत के अपराध के लिए आरोपों की विरचना पर निरर्हता।
- iv) वीवीपीएटी पुनर्गणना नियमों पर सुझाव।

07 राष्ट्रीय दलों तथा 35 राज्यीय दलों ने इस बैठक में भाग लिया।



अपने उद्घाटन संबोधन में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, डॉ.नसीम ज़ैदी ने सभी राजनैतिक दलों के योगदान का उल्लेख किया तथा बताया कि आयोग द्वारा सभी राजनैतिक दलों के सहयोग से निर्वाचकीय प्रक्रियाओं तथा प्रणालियों के उन्नयन पर लक्षित सुव्यवस्थित सुधार एवम् प्रगामी उपाय विकसित किए गए हैं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने हाल ही में सम्पन्न उप-निर्वाचनों के दौरान भिन्ड एवं धौलपुर में ईवीएम से छेड़-छाड़ के तथाकथित घटनाओं के बारे में कुछ राजनैतिक दलों द्वारा उठाए प्रश्नों को संदर्भित किया तथा दोहराया कि इन घटनाओं के बारे में आधारहीन धारणाएं बनाई गई थी तथा पक्षपातपूर्ण मतदान परिणाम का कोई मामला नहीं था।

आयोग ने तकनीक, प्रशासनिक नयाचार एवं प्रक्रियात्मक सुरक्षा की व्यापक रेंज पर प्रकाश डाला जो ईवीएम एवं वीवीपीएटी को किसी प्रकार की गड़बड़ी या छेड़छाड़ की घटना के विरुद्ध सशक्त बनाती है। उन्होंने कहा कि आयोग इन सुझावों को सुनने के लिए हमेशा तैयार है कि ईवीएम की अखण्डता एवं विश्वसनीयता में और अधिक सुधार कैसे किए जाएं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी राजनैतिक प्रतिनिधियों को सूचित किया कि आयोग एक चुनौती रखेगा तथा राजनैतिक दलों को यह प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा कि हाल ही में सम्पन्न विधान सभाओं के निर्वाचनों में उपयोग की गई ईवीएमों से छेड़-छाड़ की गई थी या कि ईवीएम में निर्धारित तकनीक एवं प्रशासनिक सुरक्षा के अन्तर्गत भी छेड़-छाड़ की जा सकती है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि आयोग संसदीय एवं राज्य विधान सभा निर्वाचनों के सभी भावी निर्वाचनों में वीवीपीएटी की 100% कवरेज सुनिश्चित करेगा। ईवीएम की वीवीपीएटी पट्टियों को गिना जाएगा जिसकी प्रतिशतता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग जल्द ही एक रूपरेखा तैयार करेगा। निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, आयोग ने निर्वाचनों के दौरान धन-बल के दुरुपयोग तथा रिश्वतखोरी के संबंध में निर्वाचन सुधार के प्रस्ताव तैयार किए हैं। आयोग ने, राजनैतिक दलों के निधीयन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आयकर अधिनियम तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधनों का प्रस्ताव भी तैयार किया है।

डॉ. नसीम ज़ैदी ने राजनैतिक दलों को निर्वाचनों के लिए सभी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरणों जैसे प्रथम स्तरीय जांच, ईवीएम/वीवीपीएटी/मतदान कार्मिकों का यादृच्छीकरण, ईवीएम को तैयार करने/अभ्यर्थी सैटिंग, मॉक पोल, ईवीएम को मुहरबंद करने आदि में उनकी निरंतर तथा गुणात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह जोर भी दिया कि निरन्तर भागीदारी राजनीतिक दलों सहित सभी पणधारियों की साझा जिम्मेदारी है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भारत निर्वाचन आयोग की सभी राजनैतिक दलों के प्रति निष्पक्ष छवि एवं समान दूरी अपनाने तथा किसी का पक्ष न लेने की बात संसूचित की जिसने वैश्विक समुदाय की नजरों में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।

श्री सुदीप जैन, महानिदेशक, भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम के संबंध में एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया जिसमें उन्होंने इसके सुरक्षित डिजाइन विशिष्टता, विकास प्रक्रिया, विभिन्न स्तरों पर पणधारियों की सहभागिता तथा ईवीएम सुरक्षित बनाने हेतु प्रशासनिक प्रक्रियाओं का वर्णन किया।



राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने एजेन्डा की प्रत्येक मद पर अपने विचार एवं सुझाव दिए।

आयोग ने राजनैतिक दलों को आश्वासन दिया कि ईवीएम से संबंधित उनकी चिंताएं और आशंकाएं नोट कर ली गई हैं तथा आगामी चुनौतियों एवं अग्रिम आवश्यक कार्रवाई के माध्यम से उन पर विधिवत रूप से विचार किया जाएगा एवं उन्हें हल किया जाएगा। अन्य निर्वाचन संबंधी सुधारों के संबंध में उनके विचारों/सुझावों पर विचार किया जाएगा तथा उपयुक्त रूप से आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

ह/-
(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक

अनुबंध - 5

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं० ईसीआई/प्रे.नो./42/2017

दिनांक: 20 मई, 2017

प्रेस नोट

विषय: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम चुनौती ।

1. भारत निर्वाचन आयोग को भारत में सत्यनिष्ठा के साथ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन में विश्व स्तर पर “स्वर्णमानक” के रूप में स्वीकार्यता प्राप्त है। इसने निर्वाचनों के अब तक के सबसे दक्ष, निर्बाध और व्यावसायिक संचालन के मानक स्थापित किए हैं और निर्वाचन प्रक्रियाओं और प्रणालियों में सुधार लाने और उसे बेहतर बनाने में नवीनतम तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने, उसे अंगीकार करने और कार्यान्वित करने में यह सर्वदा अग्रणी रहा है।
2. आयोग ने उचित विधिक सहयोग द्वारा विधिवत रूप से समर्थित पूरे देश में पारदर्शी, विश्वसनीय और सुरक्षित रूप से मतों की रिकार्डिंग, भण्डारण और गणना के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन(ईवीएम) की शुरुआत की अग्रणी पहल की है।
3. पिछले 20 वर्षों से, आयोग ने ईवीएम का प्रयोग करते हुए 03 लोक सभा निर्वाचन और 107 राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों का सफलतापूर्वक संचालन किया है। मतदान प्रक्रिया में विश्वसनीयता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और विभिन्न विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में सितम्बर, 2013 से वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल(वीवीपीएटी) मशीनों का भी प्रयोग किया गया है।
4. नब्बे के दशक में ईवीएम की शुरुआत आयोग द्वारा किया गया एक सकारात्मक निर्वाचकीय सुधार था। समय-समय पर और किसी-किसी जगह से ईवीएम की कार्यप्रणाली पर कुछ संदेह उठाए गए हैं।
5. मार्च, 2017 में पांच राज्यों(यू.पी., उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर) के विधान सभा निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के पश्चात ईवीएम की कार्यप्रणाली पर फिर से कुछ संदेह उठाए गए हैं। पांच राज्यों के विधान सभा निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के पश्चात आयोग में कुछ शिकायतें और सुझाव प्राप्त हुए थे। आयोग ने इन शिकायतों की विधिवत रूप से जांच की और उन दावों के समर्थन

में साक्ष्यों और विश्वसनीय सामग्री सूचना की मांग की परंतु अब तक भारत निर्वाचन आयोग को शिकायतकर्ताओं द्वारा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

6. तेरह राजनैतिक दलों का एक समूह 10 अप्रैल, 2017 को आयोग को मिला और उन्होंने ईवीएम के प्रयोग के संबंध में कुछ संदेह व्यक्त किए। कुछ राजनैतिक दलों ने अप्रैल, 2017 के पहले सप्ताह में भिंड(मध्य प्रदेश) और धौलपुर(राजस्थान) में हुए उप-निर्वाचनों में प्रदर्शन(वास्तविक मतदान में नहीं) के दौरान दिनांक 31/03/2017 को प्रयोग किए गए वीवीपीएटी से संबंधित घटनाओं के बारे में प्रश्न उठाए।
7. राजनैतिक दलों की चिंता को समझते हुए आयोग ने दिनांक 12 मई, 2017 को एक सर्व-दलीय बैठक संचालित की। निम्नलिखित के संबंध में उसी दिन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक प्रेस वक्तव्य भी जारी किया गया:

(i) आयोग ने सभी राजनैतिक दलों के समक्ष कहा कि आगामी सभी निर्वाचन अनिवार्य रूप से वीवीपीएटी मशीनों के साथ किए जाएंगे। आयोग का यह दृढ़ विश्वास है कि आगामी सभी निर्वाचनों में सभी मतदान केन्द्रों में ईवीएम सहित वीवीपीएटी का प्रयोग ईवीएम आधारित मतदान प्रणाली में अत्यधिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता लाएगा। यह प्रत्येक मतदाता को वीवीपीएटी में स्वयं यह देखने में सक्षम बनाएगा कि क्या उसका मत सही अभ्यर्थी को गया है। बैलेट यूनिट में बटन को दबाने के पश्चात संबंधित अभ्यर्थी का नाम और प्रतीक वीवीपीएटी मशीन के स्क्रीन पर दिखाई देगा और नाम और प्रतीक दर्शाने वाली पेपर स्लिप वीवीपीएटी के साथ जुड़े हुए सीलबद्ध बक्से में गिर जाएगी। इन पर्चियों को मतदाता द्वारा ईवीएम में डाले गए मत के ऑडिट ट्रेल के रूप में माना जाएगा। ऑडिट ट्रेल मतदाताओं के भरोसे और आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। ईवीएम सहित वीवीपीएटी का प्रयोग ईवीएम के संबंध में गलत रूप से सूचित सभी संदेहों और आशंकाओं को निश्चित रूप से समाप्त कर देगा। यह एक गर्व का विषय भी होगा कि 100% वीवीपीएटी या पेपर ट्रेल का प्रयोग करके भारत विश्व का पहला देश बन जाएगा, यह एक ऐसा तत्व है जो कि नीदरलैंड, जर्मनी और आयरलैंड सहित बहुत से देशों में नहीं था। 100% परिनियोजन हेतु अपेक्षित वीवीपीएटी की खरीद के लिए निधियों की संस्वीकृति पहले ही प्राप्त हो चुकी है और इसका उत्पादन अगस्त, 2017 में आरंभ हो जाएगा, जिसे सितम्बर, 2018 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

(ii) यह भी कहा गया था कि आयोग ने वीवीपीएटी पर्चियों की गणना के संबंध में विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा दिए गए सुझावों पर भी विचार किया है। आयोग एक निश्चित प्रतिशत तक ही वीवीपीएटी पर्चियों की गणना करेगा, जिसका निर्धारण आयोग द्वारा ही किया जाएगा। आयोग इस संबंध में शीघ्र ही एक उचित रूपरेखा तैयार करेगा।

(iii) आयोग एक चुनौती रखेगा और सभी राजनैतिक दलों को यह प्रदर्शित करने का अवसर देगा कि हाल ही में सम्पन्न हुए विधान सभा निर्वाचनों में प्रयुक्त ईवीएम से क्या छेड़छाड़ हुई थी

या यह कि ईसीआई के प्रशासनिक और निर्धारित तकनीकी सुरक्षापायों के अधीन भी ईवीएम से क्या छेड़छाड़ की जा सकती है।

(IV) आयोग ने सभी दलों से यह आग्रह भी किया कि वे निर्वाचनों के दौरान सभी महत्वपूर्ण कदमों में अपनी सतत और गुणात्मक सहभागिता सुनिश्चित करें यथा प्रथम स्तरीय जांच(एफएलसी), ईवीएम/वीवीपीएटी/ मतदान कार्मिकों का यादृच्छिकीकरण, ईवीएम तैयार करना और अभ्यर्थी सेटिंग, छद्म मतदान, ईवीएम सील करना और उसका भंडारण करना। आयोग ने राजनैतिक दलों से इस संबंध में कुछ और सुझाव आमंत्रित किए कि कैसे उनकी सहभागिता को और बढ़ाया जाए ताकि हर समय संपूर्ण पारदर्शिता बनाई रखी जा सके।

(V) आयोग ने राजनैतिक दलों से यह भी आग्रह किया है कि निर्वाचन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा में सुधार लाना सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। हमने निर्वाचन और गैर-निर्वाचन अवधि के दौरान कमियों, यदि कोई हों, को दूर करने के लिए उनसे सुझाव मांगे थे। आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह पूर्ण पारदर्शिता चाहता है और उसके पास लोगों और अन्य हितधारकों से छिपाने के लिए कुछ नहीं है। आयोग अपनी प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए अपने हितधारकों से सर्वदा सुझाव प्राप्त करता रहेगा।

(VI) आयोग ने इस बात पर भी बल दिया कि आयोग प्रतिबद्ध है और यह सभी दलों और समूहों से समान दूरी बनाए रखता है। आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि इसका कोई पसंदीदा नहीं है। साथ ही ईसीआई द्वारा इस समान दूरी बनाए रखने से वैश्विक समुदाय की नजरों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है।

8. आयोग ने पहले ही, 07 अप्रैल, 2017 को भिंड (मध्य प्रदेश) में तथा साथ ही 11 अप्रैल, 2017 को धौलपुर(राजस्थान) में ईवीएम के संबंध में, भी 31 मार्च, 2017 को छद्म ईवीएम प्रदर्शन (यथा अभिकथित वास्तविक मतदान में नहीं) के दौरान कथित वीवीपीएटी घटना पर 16 मार्च, 2017 को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता पर विस्तृत प्रेस रिलीज जारी कर दी थी। भिंड में एक गलत धारणा बना दी गई कि बैलेट यूनिट पर दबाए गए किसी भी बटन से वीवीपीएटी द्वारा केवल एक ही प्रतीक मुद्रित हो रहा था। आयोग की संपूर्ण जांच से यह स्पष्ट हो गया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 31.03.2017 को हुए डेमो, के दौरान चार बटन दबाए गए थे न कि वास्तविक मतदान के दौरान, और प्रत्येक बार सही सदृश प्रतीक ही मुद्रित हो रहा था। दिनांक 12 मई, 2017 को सभी हितधारकों को ईवीएम पर 'स्टेटस पेपर' परिचालित किया गया जिसमें ईवीएम और वीवीपीएटी के संबंध में विभिन्न पहलुओं की सूचना और जागरूकता हेतु व्याख्या की गई थी। (ये सभी दस्तावेज ईसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं)।

9. महाराष्ट्र और अन्यत्र हाल ही में हुए नगर-पालिका निर्वाचनों के दौरान ईवीएम की तथा कथित छेड़छाड़ की कुछ शिकायतों ने भी ईसीआई की ईवीएम के संबंध में गलत धारणा बनाई। यह देखा गया था कि बहुतांश के मस्तिष्क में ईसीआई के क्षेत्राधिकार के संबंध में दुविधा है। हम इस अवसर पर एक बार पुनः यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि ईसीआई देश में राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकाय

के निर्वाचनों के संचालन और परिणामस्वरूप संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अंगीकृत विभिन्न प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। स्थानीय निकायों के ग्रामीण और शहरी दोनों ही तरह के निर्वाचनों का संचालन संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य निर्वाचन आयोग, एक पृथक संवैधानिक प्राधिकरण, द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, मुम्बई नगर निगम निर्वाचनों में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा शून्य मत प्राप्त करने की विशेष शिकायत एसईसी, महाराष्ट्र द्वारा पूर्णतः असत्य पाई गई है।

10. आयोग ईवीएम की सत्यनिष्ठा, उसके साथ छेड़छाड़ न कर सकने और उसकी विश्वसनीयता के प्रति पूर्णतः आश्वस्त है। आयोग के आत्मविश्वास का आधार विस्तृत तकनीकी और प्रशासनिक प्रोटोकॉल तथा प्रक्रियात्मक सुरक्षोपाय हैं जो हमारी ईवीएम और वीवीपीएटी की विनिर्माण, परिवहन, भंडारण, मतदान और मतगणना प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ से बचाव करते हैं। फिर भी, आयोग सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करता रहता है कि किस प्रकार से हमारी ईवीएम और वीवीपीएटी की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता में और अधिक सुधार लाया जा सकता है। आयोग ईवीएम प्रचालन के संबंध में संदेह की छाया भी नहीं पड़ने देगा।
11. आयोग उन सभी महत्वपूर्ण मामलों की ओर ध्यान दिलाना चाहता है जो कि पिछले दो महीनों में समय-समय पर उठाए गए हैं:

क) **ईसीआई-ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये स्टैंड-अलोन मशीनें हैं और ये मतदान के दौरान किसी भी समय इंटरनेट और/या किसी अन्य नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होती हैं।** अतः, इसमें हैकिंग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ईसीआई-ईवीएम में किसी प्रकार का फ्रीक्वेंसी(आवृत्ति) रिसेवर या वायरलेस के लिए डाटा डीकोडर नहीं होता है और इसलिए यह वायरलेस द्वारा कोई भी कोडेड सिग्नल प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः बाहरी हार्डवेयर वायरलेस, वाई-फाई या ब्लूटूथ युक्ति के माध्यम से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, ये मशीनें सर्वदा ईसीआई और इसके निर्वाचन प्राधिकारियों के संरक्षण में होती हैं।

ख) **विनिर्माण स्तर पर छेड़छाड़ को खारिज किया जाता है क्योंकि वहां पर सॉफ्टवेयर की सुरक्षा के संबंध में सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है।** इसके अतिरिक्त मशीनों को वर्ष 1989 से शुरू करके विभिन्न वर्षों में विनिर्मित किया गया है। विनिर्माण के पश्चात ईसीआई द्वारा ईवीएमों को राज्यों के अंदर राज्यों तथा जिलों में भेजा जाता है। इतने वर्षों पहले से ही विनिर्माता इस स्थिति में नहीं होते हैं कि वे यह जान पाए कि किसी निर्वाचन क्षेत्र से कौन सा अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ेगा और बैलेट यूनिट पर अभ्यर्थियों का क्या क्रम होगा और इसलिए विनिर्माण स्तर पर पूर्वनिर्धारित तरीके से ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।

ग) **की बटन दबाकर ट्रोजन हॉर्स को सक्रिय करके परिणामों को बदला नहीं जा सकता है** क्योंकि

1. ट्रोजन हॉर्स को माइक्रोकन्ट्रोलर चिप में बर्न हुई भारत निर्वाचन आयोग के ईवीएम के साफ्टवेयर कोड में नहीं डाला जा सकता है क्योंकि चिप केवल एक बार ही प्रोग्रामेबल है।

2. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए कड़े सुरक्षा उपायों ने ईवीएम तक पहुंच बनाना असंभव कर दिया है जो ट्रोजन हॉर्स डालने के लिए माइक्रो-कंट्रोलर को बदलने की कोशिश करने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षा है।
3. कंट्रोल यूनिट एक समय में केवल एक ही बटन दबाने के लिए बैलेट यूनिट को सक्रिय करती है। बैलेट यूनिट पर किसी भी अतिरिक्त बटन के दबाए जाने पर कंट्रोल यूनिट जड़ हो जाती है और इसमें कितने भी बटन दबाने या गुप्त कोडों द्वारा सिगनल भेजना असंभव हो जाता है। जब सीयू में बैलेट बटन को दबाया जाता है, तो सीयू मत को रजिस्टर करने में बीयू को सक्षम बना देता है और बीयू में बटन दबाने की प्रतीक्षा करता है। इस अवधि के दौरान, जब तक कि उस मत को डालने की पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती तब तक सीयू के सभी बटन निष्क्रिय हो जाते हैं। जब बैलेट यूनिट में मतदाता द्वारा एक बार कोई भी बटन (अभ्यर्थी मत बटन) दबा दिया जाता है तो बैलेट यूनिट मुख्य सूचना गतिशील रूप से एन्क्रिप्टेड फार्म में कंट्रोल यूनिट को भेज देती है। कंट्रोल यूनिट को डाटा मिल जाता है और वह साथ ही बीयू में लाल एलईडी लैम्प को चमकाकर उसके प्राप्त होने की सूचना देता है। सीयू में मतदान के समर्थ होने के पश्चात सीयू द्वारा केवल “फर्स्ट की प्रेस” का संकेत स्वीकार किया जाता है।

इसके बाद, यदि मतदाता दूसरे बटनों को दबाता जाता है तो उसका कोई लाभ नहीं है क्योंकि उन बाद में दबाए गए बटनों से सीयू और बीयू के बीच कोई संचार नहीं होगा और न ही बीयू कोई भी दबाए गए बटन को रजिस्टर करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक सीयू का प्रयोग करते हुए प्रत्येक समर्थित बैलेट के लिए केवल एक ही वैध बटन (फर्स्ट की प्रेस) को दबाया जाएगा। जब एक बार वैध बटन (मतदान प्रक्रिया) दबा दिया जाता है तो जब तक कोई अन्य मतपत्र सक्षम बटन नहीं दबाया जाता, तब तक कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के बीच कोई गतिविधि नहीं होगी। अतः देश में प्रयोग की जा रही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को तथाकथित “श्रृंखलाबद्ध की प्रेस” द्वारा कोई भी दुर्भावनापूर्ण संकेत भेजना असंभव है।

घ **ईसीआई-ईवीएम में भौतिक रूप से कोई छेड़-छाड़ नहीं की जा सकती और न ही उनके घटकों को किसी की नजर बचा कर बदला जा सकता है। यह स्पष्ट किया जा चुका है कि एम1 और एम2** जैसी पूर्ववर्ती जेनरेशन की मशीनों में माइक्रो कंट्रोलर/चिप एवं मदरबोर्ड बदलना मजबूत प्रशासनिक और तकनीकी सुरक्षा के कारण सम्भव नहीं है। साथ ही वर्ष 2013 के बाद तैयार की गई नई **एम3** ईवीएम में **छेड़-छाड़ का पता लगाने (टैम्पर डिटेक्शन)** और **स्वयं निदान (सेल्फ डायग्नोस्टिक)** जैसी अतिरिक्त विशेषताएं हैं। किसी भी क्षण कोई भी जब मशीन को खोलने की कोशिश करता है तो छेड़-छाड़ का पता लगाने वाली विशेषता, ईवीएम को निष्क्रिय कर देती है। जब भी ईवीएम चालू होती है **स्वयं निदान (सेल्फ डायग्नोस्टिक)** विशेषता उसकी पूर्ण रूप से जांच करती है। इसके हार्डवेयर या साफ्टवेयर में किसी भी बदलाव का तुरंत पता चल जाएगा। एम 3 जेनरेशन की 13.95 लाख बीयू और 9.30 लाख सीयू के उत्पादन के लिए निर्माताओं को 1900 करोड़ रुपए पहले से ही संस्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके साथ-साथ 16.15 लाख वीवीपीएटी भी उत्पादनाधीन है और इनके लिए 3173 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं।

ड) नवीनतम तकनीकी विशेषताएं ईसीआई-ईवीएम को छेड़-छाड़ रोधक बनाती है। ईसीआई-ईवीएम को 100% छेड़-छाड़ रोधक मशीन बनाने के लिए इसमें कुछ सबसे अत्याधुनिक तकनीकी विशेषताओं जैसे कि एक बारगी प्रोग्रामेबल (ओटीपी) माइक्रोकंट्रोलर, की कोडों की डायनमिक कोडिंग, प्रत्येक की (key) को दबाने की तारीख एवं समय मुद्रांकन, उन्नत एन्क्रिप्शन प्रौद्योगिकी और ईवीएम लॉजिस्टिक को संभालने के लिए ईवीएम-ट्रैकिंग साफ्टवेयर आदि का प्रयोग किया जाता है।

इसके अतिरिक्त एम3 ईवीएम के नए मॉडल में छेड़-छाड़ का पता लगाने और स्वयं निदान जैसी अन्य विशेषताएं भी शामिल हैं। ओटीपी साफ्टवेयर का अभिप्राय है कि ईसीआई की सुरक्षित अभिरक्षा के अंतर्गत ईवीएम में डाले गए प्रोग्राम में कोई भी बदलाव, किसी के भी द्वारा उसे पुनः लिखना या पुनः पढ़ना संभव नहीं है। यह ईवीएम को छेड़छाड़ रोधक बनाता है। यदि कोई अनधिकृत प्रयास करता है तो मशीन निष्क्रिय हो जाएगी।

च. कुछ लोगों द्वारा फैलायी गई गलत सूचना और लगाए गए आरोपों के विपरीत, भारत निर्वाचन आयोग विदेश में तैयार की गई किसी भी ईवीएम का प्रयोग नहीं करता है। ईवीएम दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड; बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड; हैदराबाद द्वारा देश में ही उत्पादित की जाती हैं। साफ्टवेयर प्रोग्राम कोड इन दोनों कंपनियों द्वारा इन-हाउस तैयार किए जाते हैं, न कि आउटसोर्स किए जाते हैं और इन्हें भारत निर्वाचन आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है और सर्वोच्च निष्ठा को बनाए रखने के लिए यह फैक्ट्री स्तर पर कड़ी सुरक्षा प्रक्रियाओं के अधीन होता है।

साफ्टवेयर प्रोग्राम को विनिर्माताओं द्वारा **मशीन कोड** में बदल दिया जाता है और उसके उपरांत ही इसे विदेश स्थित चिप विनिर्माता को दिया जाता है। (हमारे देश में सेमी-कंडक्टर को निर्मित करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है)। प्रत्येक माइक्रोचिप की एक पहचान संख्या होती है जो मेमोरी में होती है और उन पर निर्माताओं के डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं। अतः उनकी प्रतिस्थापना का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि विनिर्माताओं के पास वापिस लाई गई माइक्रोचिप साफ्टवेयर के संबंध में कार्यात्मक परीक्षण के अध्यक्षीन होती हैं। माइक्रोचिप को बदलने की किसी भी प्रकार की कोशिश का पता लगाया जा सकता है और ईवीएम को निष्क्रिय किया जा सकता है। इस प्रकार, विद्यमान प्रोग्राम में कुछ भी बदलाव करने और उसमें कुछ नया डालने का पता चल जाता है, इससे ईवीएम कार्य करना बंद कर देती है क्योंकि ईवीएम छेड़-छाड़ रोधी है। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी प्रगति के कारण बीईएल और ईसीआईएल में ही चिप पर साफ्टवेयर की फ्यूजिंग हो सकती है और इसलिए एम3 में बीईएल और ईसीआईएल के अंदर चिप में साफ्टवेयर को फ्यूज कर दिया जाता है।

छ) ईवीएम के परिवहन के दौरान अथवा भंडारण स्थल पर किसी भी प्रकार का जोड़-तोड़ करने की संभावना नहीं है। जिला मुख्यालयों में ईवीएम को उपयुक्त सुरक्षा में दोहरी सुरक्षा प्रणाली में रखा जाता है। इनकी सुरक्षा की समय-समय पर जांच की जाती है। निर्वाचन प्राधिकारी स्ट्रांग रूम को नहीं खोलते और वे केवल नियमित जांच करते हैं कि क्या यह पूरी तरह से सुरक्षित है और क्या इस पर सही ढंग से ताला लगा है या नहीं।

कोई भी अनधिकृत व्यक्ति किसी भी समय ईवीएमों तक नहीं पहुंच सकता। जब निर्वाचन नहीं हो रहे होते हैं तो जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सभी ईवीएम का वार्षिक वास्तविक सत्यापन किया जाता है और रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जाती है। इसके अतिरिक्त, स्ट्रांग रूम सदैव राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोले जाते हैं।

ज) **ईसीआई - ईवीएम की छेड़-छाड़ रोधकता सुनिश्चित करने हेतु भिन्न - भिन्न स्तरों पर जांच-पड़ताल की जाती है जो निम्नलिखित है:-**

- **प्रथम स्तरीय जांच:** प्रत्येक ईवीएम की तकनीकी एवं भौतिक जांच करने के पश्चात बीईएल/ईसीआईएल के प्राधिकृत इंजीनियर घटकों की मौलिकता को प्रमाणित करते हैं। यह जांच एवं सत्यापन राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है। खराब ईवीएम को वापिस फैक्टरी भेजा जाता है। प्रथम स्तरीय जांच के हॉल को स्वच्छ रखा जाता है, जिसमें सीमित प्रवेश होता है और इसके अन्दर कोई कैमरा, मोबाइल फोन या जासूसी पेन ले जाने की अनुमति नहीं होती है। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रत्येक ईवीएम पर छदम् मतदान किया जाता है। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा यादृच्छिक रूप से चुनी गई पांच प्रतिशत ईवीएम पर कम से कम एक हजार छद्म मत डाले जाते हैं और उन्हें इसका परिणाम दर्शाया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियो बनाई जाती है।
- **अभ्यर्थियों की सेंटिंग:** एक अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय अभ्यर्थियों की सेंटिंग करने की प्रक्रिया है जो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों को अंतिम रूप देने के बाद अपनाई जाती है। बैलेट यूनिट में एक बैलेट पेपर डाला जाता है जिसे गुलाबी रंग के पेपर से सील कर दिया जाता है। इस प्रकार इस स्थिति में बैलेट यूनिट सील हो जाती है। जहां वीवीपीएटी का प्रयोग किया जाता है उनमें उस स्थिति पर प्रत्येक वीवीपीएटी में अभ्यर्थियों के प्रतीकों को भी डाल दिया जाता है। एक बार फिर प्रत्येक ईवीएम पर छदम् मतदान किया जाता है और पांच प्रतिशत ईवीएम को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है और उनपर एक हजार छदम् मत डाले जाते हैं।
- **यादृच्छिकीकरण:** ईवीएम का दो बार यादृच्छिकीकरण किया जाता है पहली बार निर्वाचन क्षेत्र को ईवीएम आवंटित करते समय और दूसरी बार मतदान केन्द्रों पर, ताकि किसी केन्द्र को नियत अथवा निर्धारित आवंटन की आशंका से बचा जा सके। इस प्रकार यह प्रशंसनीय है कि जब तक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता, तब तक पहले यादृच्छिकीकरण तक, यह किसी को भी नहीं पता होता कि मतदान पेपर पर किसका नाम किस क्रम में है, मतदान पेपर पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम वर्णक्रम में रखे जाते हैं, सबसे पहले राष्ट्रीय और राज्य दलों के, इसके पश्चात अन्य पंजीकृत दलों के और बाद में निर्दलीय अभ्यर्थियों एवं नोटा को स्थान दिया जाता है। इस प्रकार बैलेट यूनिट पर किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी की क्रम संख्या

अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी राजनैतिक दल के अभ्यर्थी की क्रम संख्या राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में नियत अथवा पूर्व निर्धारित नहीं होती है। अतः अभ्यर्थियों के नामों की सेटिंग होने तक कोई भी, यहां तक कि रिटर्निंग अधिकारी अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी अथवा आयोग, यह नहीं जान सकता कि किस बैलेट यूनिट पर कौन सा बटन किस अभ्यर्थी को दिया जाएगा।

- मतदान के दिन भी, मतदान प्रारंभ होने से पहले अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं के सामने कम से कम 50 छदम मत डाले जाते हैं।
- मतदान के पश्चात, ईवीएम सील कर दी जाती है और इस सील पर मतदान अभिकर्ता अपने हस्ताक्षर करते हैं। मतदान अभिकर्ता मतदान में प्रयुक्त ईवीएम को मतदान केन्द्र से ईवीएम स्ट्रांग रूम तक ले जाने के दौरान स्ट्रांग रूम तक जा सकते हैं।
- **स्ट्रांग रूम:** मतदान के पश्चात, जहां ईवीएम को रखा जाता है वहां अभ्यर्थी अथवा उनके प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम पर अपनी-अपनी सील लगा सकते हैं और स्ट्रांग रूम के सामने ठहर भी सकते हैं। इन स्ट्रांग रूमों की निगरानी सीसीटीवी सुविधाओं सहित, बहुस्तरीय आधार पर 24x7 घंटे की जाती है।
- **मतगणना केन्द्र:** मतदान में प्रयुक्त ईवीएम को संपूर्ण सुरक्षा और अभ्यर्थियों की उपस्थिति में मतदान केन्द्रों पर लाया जाता है और कंट्रोल यूनिट (सीयू) पर लगी सीलों की विशिष्ट पहचान सं., मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षरों को मत गणना आरंभ होने से पहले अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों को दिखाया जाता है।

12 ईवीएम को छेड़छाड़ रहित बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई सुस्पष्ट जांच और सुरक्षा उपायों के उपर्युक्त अनुक्रम को देखते हुए यह स्पष्ट है कि न तो ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है न ही ईसीआई की ईवीएम की पद्धति में कोई परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मतदान की प्रक्रिया में न तो खराब मशीन अथवा न ही ऐसी मशीन, जो भारत निर्वाचन आयोग की नहीं है, को कभी, किसी भी समय शामिल/पुनः शामिल नहीं किया जा सकता है। बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट का मिलान नहीं होने के कारण उपरोक्त प्रक्रिया के द्वारा ऐसी किसी भी ईवीएम मशीन का पता तुरंत चल जाएगा जो भारत निर्वाचन आयोग की नहीं है।

13. कुछ लोग तर्क देते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देश ईवीएम क्यों नहीं अपनाते हैं और कुछ देशों ने इसका प्रयोग क्यों बंद कर दिया है?

भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम विश्व भर की किसी भी ईवीएम से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हैं। नीदरलैंड, आयरलैंड और जर्मनी में प्रयुक्त ईवीएम का निर्माण निजी कंपनियों द्वारा किया जाता था और उनका भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम में स्वतंत्र टीईसी अथवा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित थर्ड पार्टी द्वारा एक कड़े सत्यापन और

प्रमाणीकरण की तरह कोई स्वतंत्र रूप से सत्यापन नहीं किया जाता था। नीदरलैंड की इन नेडप ईवीएम मशीनों में मतदान के डाटा का अंतरण एक सीडी के माध्यम से किया जाता था, जबकि हमारे देश की ईवीएम में ऐसा नहीं किया जाता और डाटा मशीन के अंदर ही भंडारित रहता है, और इसे कभी भी अंतरित नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इन देशों में एक संपूर्ण सुदृढ़ प्रशासनिक और सुरक्षात्मक प्रणाली तथा विधिक ढांचे का अभाव था। अंत में, उनकी ईवीएम की लेखा परीक्षा नहीं की जा सकती थी।

समय-समय पर यह मुद्दा उठाया जाता है कि विदेशी राष्ट्रों ने मतदान मशीनों का प्रयोग बंद कर दिया है तो भारत में इनका प्रयोग क्यों किया जा रहा है? पिछले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति होने से निर्वाचन प्रबंधन निकायों, पेशेवरों, विशेषज्ञों तथा कार्यकर्ताओं (विशेषकर ग्रीन एक्टिविस्ट) ने मतपत्र को मैनुअल तरीके से चिह्नित करने के नुकसान से बचने के लिए विश्व के विभिन्न भागों में कागजरहित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रियाओं पर विचार किया है। प्रौद्योगिकी तथा निर्वाचन प्रबंधन का मिलन अरसे पहले 1892 का है, जब कागजी मतपत्र का लम्बे समय तक प्रयोग किए जाने के पश्चात् न्यूयार्क में पहली 'लीवर वोटिंग मशीनों' का प्रयोग किया गया था। वर्ष 1960 में, यूएसए में पंच कार्ड मशीनों को शुरू किया गया तथा वहां 1975 में पहली ईवीएम शुरू की गई थी। तब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में काफी उन्नति हुई है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के प्रकार:

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया तीन प्रकार की हो सकती है:

(i). निर्दिष्ट मतदान केन्द्रों पर रखी प्रत्यक्ष रिकार्डिंग मशीनें

(ii). इंटरनेट वोटिंग

- रिमोट ऑनलाइन वोटिंग
- निर्दिष्ट मतदान केन्द्रों पर

(iii). ऑप्टिकल स्कैनर

- अपने किस्म की अनूठी स्टैण्ड अलोन
- परिणामों की केन्द्रीयकृत गणना के लिए नेटवर्क की गई

भारत में प्रयोग की जाने वाली ईवीएम स्टैण्ड अलोन प्रत्यक्ष रिकार्डिंग मशीनों की पहली किस्म के अंतर्गत आती हैं जिनमें किसी प्रकार की नेटवर्क कनेक्टिविटी की संभावना नहीं है जहां मतदाता निर्वाचन के दिन निर्दिष्ट मतदान केन्द्र पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई सख्त प्रशासनिक सुरक्षा में अपना वोट डालते हैं।

हालांकि भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम भी प्रत्यक्ष रिकार्डिंग मशीन हैं तथापि भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग की जाने वाली प्रत्यक्ष रिकार्डिंग या इंटरनेट वोटिंग या ऑप्टिकल स्कैनिंग के लिए किसी भी ईवीएम से पूरी तरह से भिन्न है। भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम की जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में प्रयुक्त डीआरएम के साथ विश्लेषणात्मक तुलना करने पर यह स्पष्ट रूप से उजागर हुआ है जो निम्नलिखित है:

नीदरलैंड

नीदरलैंड में 1990-2007 के मध्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का प्रयोग किया गया। वोटिंग मशीनों का निर्माण एक निजी डच-कंपनी एनईडीएपी (Nederlandse Apparaten Fabriek NV) द्वारा किया गया था। वर्ष 2006 में सरकार ने वोटिंग मशीनों का स्वतंत्र रूप से परीक्षण करने का आदेश दिया। एनईडीएपी मशीनों की सुरक्षा तथा विश्वसनीयता संबंधी विशेषताओं की समीक्षा करने के लिए दो स्वतंत्र आयोग, द वोटिंग मशीन डिसेजन-मेकिंग आयोग तथा इलेक्शन प्रोसेस एडवायजरी आयोग (ईपीएसी) का गठन क्रमशः 19 दिसम्बर, 2006 तथा 18 जनवरी, 2007 को किया गया था। दोनों आयोगों की टिप्पणियों के अनुसरण में, एनईडीएपी मशीनों तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को निम्नलिखित कारणों से 2007 में बंद कर दिया गया:-

- नीदरलैंड के इंटीरियर और किंगडम रिलेशन मंत्रालय (एमओआईकेआर) को एनईडीएपी के बारे में पर्याप्त तकनीकी जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से निर्वाचनों के संचालन के लिए अधिकारियों को बाहरी कार्यकताओं पर निर्भर रहना पड़ता था।
- प्रौद्योगिकी वेंडर निर्णय प्रक्रिया के भाग बन गए और मंत्रालय प्रभावी पर्यवेक्षण करने की स्थिति में नहीं था।
- आर्गेनाइजेशन फार डच एप्लाइड साइन्टिफिक रिसर्च (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, TNO) ने इन मशीनों को “पुराने मानक” अपनाकर प्रमाणित किया और इनकी जांच की जो आधुनिक प्रौद्योगिकी और सुरक्षा संबंधी खतरों से सुरक्षित नहीं थे।
- इसके अतिरिक्त, प्रमाणीकरण और जांच रिपोर्टों को सावर्जनिक नहीं किया गया जिससे स्वतंत्र विशेषज्ञ विश्लेषण का सत्यापन करने से वंचित रह गए।
- विधिक ढांचा, विशेषतौर से आवश्यक सुरक्षा अपेक्षाएं, इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया की विशेषताओं से निपटने के लिए अपर्याप्त था।

(नीदरलैंड में इलेक्ट्रॉनिक मतदान पर व्यापक रिपोर्ट के लिए निम्नलिखित लिंक देखें:

<https://www.ndi.org/sites/default/files/5-netherlands.pdf>)

जर्मनी:

जर्मनी में, एनईडीएपी द्वारा निर्मित-ई मतदान मशीनों का प्रयोग इनकी आलोचना किए जाने से पूर्व 2005-2009 के बीच किया गया था और अंत में इन्हें बंद कर दिया गया। बंडेस्वरफासुंगस्गेरिच्ट (द फेडरल कंस्टिट्यूशन कोर्ट ऑफ जर्मनी) ने वर्ष 2009 में एनईडीएपी मशीनों के प्रयोग को निम्नलिखित कारणों से बन्द करने का आदेश दिया:

- एनईडीएपी इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के प्रयोग ने निर्वाचनों की सार्वजनिक प्रकृति, (मूल विधि के अनुच्छेद 20.1 और 20.2 के संयोजन में अनुच्छेद 38) के उस सिद्धांत का उल्लंघन किया जिसमें यह अपेक्षा है कि जब तक अन्य संवैधानिक हित किसी अपवाद को न्यायोचित न ठहरायें, निर्वाचनों में सभी आवश्यक चरण सार्वजनिक परीक्षण के अध्वधीन हैं।
- इसने यह भी टिप्पणी की थी कि “नागरिकों के लिए निर्वाचन क्रिया में आवश्यक सोपानों की जांच करना और बिना किसी विशिष्ट विशेषज्ञ की जानकारी से परिणामों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना संभव होना चाहिए”।

((निम्नलिखित लिंक में निर्णय देखें: http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/En/2009/03/cs20090303_2bvc000307en.html;jsessionid=FEA71E86E2CEE030FF7AAAC90572279C.2_cid383)

आयरलैंड:

आयरलैंड में एनईडीएपी मशीनों का प्रयोग 2002-2004 के बीच किया गया था। इन मशीनों के प्रयोग पर प्रश्न चिह्न लगाया गया जिसकी वजह से दो स्वतंत्र आयोग गठित किए गए। चुनी गई इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली की गोपनीयता, सटीकता और परीक्षण संबंधी दोनों आयोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आयरलैंड में निर्वाचनों में एनईडीएपी की मशीनों का प्रयोग निम्नलिखित आधारों पर नहीं किया जा सकता था:

- अपर्याप्त प्रौद्योगिकीय सुरक्षा
- सीडी के प्रयोग द्वारा डाटा का असुरक्षित अंतरण
- एकल प्रत्यायित निकाय द्वारा संपूर्ण व्यापक स्वतंत्र जांच, सत्यापन और प्रमाणीकरण का अभाव ,
- सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मशीनों की भौतिक सुरक्षा में असंगतियां
- इलेक्ट्रॉनिक मतदान उपस्करों के भंडारण, परिवहन, व्यवस्थापन, प्रयोग और निपटान की तुलना में स्पष्ट नीतिगत दिशा निर्देशों का अभाव।
- इलेक्ट्रॉनिक मतदान उपस्करों की पहचान, स्थिति और आवाजाही को रिकार्ड करने के लिए व्यापक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर का अभाव।

(लिंक देखें:- <http://www.unic.pt/images/stories/publicacoes1/oolIndex.pdf>;
<http://www.unic.pt/images/stories/publicacoes1/part%200%20Index.pdf>)

संयुक्त राज्य अमरीका

वर्ष 2000 में यूएसए के राष्ट्रपतीय निर्वाचनों में मतदान पद्धति पर विवाद के बाद, मतदान पद्धति की समीक्षा की गयी (स्टीव, गोल्डस्मिथ और टर्नर, 2012:185)। तदनुसार प्रत्यक्ष रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक (डीआरई) प्रणालियाँ (जैसे प्रीमियर इलेक्शन साल्यूशन, जिसे साधारणतया डाइबोल्ड कहा जाता है, द्वारा विकसित व्यापक रूप से प्रयुक्त एक्यूवोट टीएस) शुरू की गयीं। डीआरई प्रणाली में “तीन बेसिक अंतरापृष्ठों में से एक (पुशबटन, टचस्क्रीन या डायल)” का प्रयोग होता है जिसके माध्यम से “मतदाता अपने मतों को सीधा कंप्यूटर मेमोरी में रिकार्ड करता है। मतदाताओं के विकल्पों को

मैमोरी कार्ट्रिज, डिसकेट या स्मार्ट कार्ड के माध्यम से डीआरई में स्टोर किया जाता है..... कुछ डीआरई को वोटर वेरिफाइड पेपर आडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) प्रिंटर के साथ सुसज्जित किया जा सकता है.....”। वर्तमान में, यूएसए में 27 राज्यों में प्रत्यक्ष रिकार्डिंग मशीनों का प्रयोग किया जाता है जिनमें से 15 राज्यों में पेपर आडिट ट्रेल का प्रयोग किया जाता है। अन्य मतदान पद्धतियों में शामिल हैं: ऑप्टिकल स्कैन पेपर बैलट प्रणालियां, बैलेट मार्किंग डिवाइसिज और पंच कार्ड बैलेट।

(लिंक देखें: <http://www.verifiedvoting.org/resorces/voting-equipment/>)

अन्य देश:

ब्राजील में, निर्वाचनों में उपयोग की जाने वाली मशीनों को 'इलेक्ट्रॉनिक बैलेट बॉक्सिस' कहा जाता है, जो अपने आप में अनूठी प्रत्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक रिकार्डिंग प्रणालियां हैं। वेनेजुएला में, एसएटीआईएस (स्मार्टमेटिक आडिटेबल इलेक्शन सिस्टमस) मतदान मशीनों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें पूरे देश में वर्ष 2004 में पूरी तरह से क्रियान्वित कर दिया गया था। (इस्टीव गोल्डस्मिथ एवं टर्नर 2012: 185)

भारत:

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीने विश्व के अन्य भागों में प्रयुक्त ई-वोटिंग मशीनों की तुलना में निम्नलिखित कारणों की वजह से सचमुच अद्वितीय हैं:

- भा.नि.आ. की ईवीएम बेजोड़ और नेटवर्क रहित मशीनें हैं।
- अन्य देशों में प्रयोग की जा रही मशीनों, जिनका निर्माण पूरी तरह से निजी कंपनियों करती हैं के विपरीत भा.नि.आ. की ईवीएम का निर्माण दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किया जाता है अर्थात् ईसीआईएल और बीईएल। इस प्रकार ईसीआई की ईवीएमस के निर्णय लेने की प्रक्रिया अथवा इसके निर्माण में निजी पक्षकारों अथवा तकनीकी विक्रेताओं का निहित स्वार्थ होने का कोई अंदेशा या अवसर नहीं रह जाता।
- ईसीआई की ईवीएमस को संपूर्ण जांच प्रक्रिया करने के पश्चात् एक स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा बार-बार सफलतापूर्वक प्रमाणित और सत्यापित किया जाता है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एसटीक्यूसी, एक अधिकृत तृतीय पक्ष संस्था, निर्माताओं द्वारा उत्पादित ईसीआई की ईवीएम मशीनों का मानकीकरण एवं सत्यापन करती है लेकिन नीदरलैंड में प्रयोग की जाने वाली मशीनों में ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती।
- ईसीआई की ईवीएमस में डाटा आंतरिक रूप से स्टोर होता है और इसे किसी भी डिवाइस से अंतरित नहीं किया जा सकता, जबकि अन्य देशों में डीआरएम में रिकार्ड मतदान का डाटा सीडी आदि के द्वारा अंतरित किया जाता है।
- एनईडीएपी मशीनें प्रयोग करने वाले अन्य देशों के विपरीत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ईसीआई की मशीनों के प्रयोग, भण्डारण, परिवहन और ट्रेकिंग के लिए संपूर्ण सुरक्षा संबंधी नयाचार और प्रशासनिक उपाय किए गए हैं।
- नीदरलैंड के एमोआईकेआर के विपरीत आयोग को प्रतिष्ठित प्रोफेसरों वाली एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का संपूर्ण सहयोग मिलता है।

- प्रत्येक ईवीएम पर एक विशिष्ट नम्बर होता है जिसे ईवीएम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्वाचन आयोग के डाटाबेस में रिकार्ड किया जाता है। ईवीएम की इस संख्या की डाटाबेस से सदैव पुर्नजांच की जा सकती है।
- इन ईवीएम मशीनों में प्रयोग किए गए सॉफ्टवेयर की एक ही बार प्रोग्रामिंग (ओटीपी) की जा सकती है, जिसे उत्पादन के उपरांत दोबारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
- देशभर में विधिक ढांचे के अनुसार ईसीआई की ईवीएमस को सदैव कड़ी, एक समान, उच्च स्तर की प्रशासनिक और भौतिक सुरक्षा में रखा जाता है।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61ए के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग को ईवीएम का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। देशभर में विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी कई बार विभिन्न निर्णयों में ईवीएमस के प्रयोग को उचित ठहराया है और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वर्ष 2004 में ईसीआई की ईवीएम को इसकी पारदर्शिता और सुदृढ़ता के कारण इसे "राष्ट्र का गौरव" घोषित किया था।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में भारत निर्वाचन आयोग ने वीवीपीएटी तकनीक प्रारंभ की है ताकि सार्वजनिक परख सुनिश्चित हो सके। वर्ष 2019 तक आयोग पूरे देश में वीवीपीएटी लागू करने के प्रति कटिबद्ध है। इस प्रकार डाले गए प्रत्येक मत की शतप्रतिशत मतदाता प्रामाणिकता और संपरीक्षणता हो जाएगी, जबकि इसके विपरित एनईडीएपी मशीनों में ऐसी सुविधा के अभाव में जर्मनी के उच्चतम न्यायालय ने इन मशीनों के उपयोग को असंवैधानिक कहते हुए इनके उपयोग की अनुमति नहीं दी थी जबकि भारतीय उच्चतम न्यायालय ने देश में निर्वाचनों के आयोजन में ईवीएम के प्रयोग को वैध माना है।
- अतः, ईसीआई की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की किसी अन्य स्थान पर उपयोग की जा रही मशीनों से तुलना करना अनुचित है। आयोग ने हमेशा एक स्पष्ट एवं पारदर्शी रूप से कार्य किया है और हमेशा अपनी प्रक्रियाओं के लिए प्रश्नों, संदेहों तथा रचनात्मक एवं शिष्ट आलोचनाओं का स्वागत किया है ताकि हम निर्वाचकीय प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत बना सकें। 12 मई, 2017 को हुई राजनीतिक दल की बैठक के दौरान आयोग ने राजनीतिक दलों को एक खुली चुनौती देने का वचन दिया था ताकि वे यह प्रदर्शित कर सकें कि पांच राज्यों में प्रयोग किए गए ईवीएम में छेड़छाड़ की गई थी या तकनीकी तथा प्रशासनिक सुरक्षा प्रबंधों के होते हुए भी ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है। तदनुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने, 3 जून, 2017 से सभी राजनीतिक दलों को खुली चुनौती देने का प्रस्ताव किया।

चुनौती की रूपरेखा:

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उन नामित व्यक्तियों को ईसीआई मुख्यालय में आयोग द्वारा निर्धारित मौजूदा प्रशासनिक तथा सुरक्षा प्रोटोकॉल की रूपरेखा के भीतर अपने दावों को प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिन्होंने निर्वाचन लड़ा और यह दावा किया कि भारत निर्वाचन आयोग के स्वामित्व के

अधीन रखी गई मशीनों तथा फरवरी-मार्च, 2017 में पांच राज्यों नामतः पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश में हाल ही में आयोजित विधान सभा के साधारण निर्वाचनों में प्रयोग की गई मशीनों में छेड़-छाड़ की गई थी या यह कि इनमें ईसीआई के तकनीकी तथा प्रशासनिक सुरक्षा प्रबंधों के अधीन भी छेड़-छाड़ की जा सकती है।

आयोग की ईवीएम चुनौती की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:-

चुनौती कथन-1:-

यह कि पांच राज्यों के साधारण निर्वाचन, 2017 में उपयोग की गई ईवीएम के साथ मतदान के पश्चात ईवीएम में स्टोर किए गए परिणामों में हेर-फेर करके किसी अभ्यर्थी/राजनीतिक दल विशेष का पक्ष लेने के लिए छेड़छाड़ की गई थी। अतः, चुनौतीदाता को इन निर्वाचनों में प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट के परिणामों में वैसे ही परिदृश्य में परिवर्तन करना होगा जैसा कि मतदान के पश्चात अर्थात् स्ट्रांग रूम में स्टोर की हुई अवधि के दौरान अथवा मतगणना के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के तकनीकी और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रहती हैं, यह निम्नलिखित के माध्यम से करना होगा,

क: सीयू अथवा बीयू अथवा दोनों पर बटनों के कम्बीनेशन को दबाते हुए, अथवा

ख: बाहरी वायरलैस/ब्लूटूथ/मोबाइल फोन इत्यादि के द्वारा सीयू अथवा बीयू अथवा दोनों के कम्प्युनिकेशन के द्वारा

चुनौती कथन-1।

यह कि पांच राज्यों के साधारण निर्वाचनों - 2017 में प्रयोग की गई ईवीएम के साथ मतदान के दिन से पूर्व या मतदान के दिन छेड़छाड़ की गई थी। अतः, दावाकर्ताओं को इन्हीं मतदानों में प्रयुक्त ईवीएम के परिणामों को ठीक उन्हीं परिदृश्यों में परिवर्तित करना होगा जैसा मतदान से पहले, अर्थात् स्ट्रांग रूम में भंडारण के दौरान अथवा मतदान के दौरान, भारत निर्वाचन आयोग के तकनीकी और प्रशासनिक सुरक्षात्मक उपायों के अंतर्गत ईवीएम रखी जाती है। यह निम्नलिखित के माध्यम से करना होगा:

क. सीयू या बीयू या दोनों के बटनों के कम्बीनेशन को दबाते हुए, अथवा

ख. बाहरी वायरलैस/ब्लूटूथ/मोबाइल फोन इत्यादि के द्वारा सीयू/अथवा बीयू या दोनों के कम्प्युनिकेशन के द्वारा।

चुनौती । तथा चुनौती ॥ के लिए सामान्य प्रक्रिया

1. ईवीएम चुनौती केवल उन राष्ट्रीय तथा राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के भाग लेने के लिए ही खुली है जिन्होंने पांच राज्यों अर्थात् गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों में भाग लिया था।
2. प्रत्येक राष्ट्रीय तथा राज्यीय मान्यता प्राप्त दल जो भाग लेना चाहता है, वह ईवीएम चुनौती में भाग लेने के लिए अधिकतम केवल 3 व्यक्तियों को ही नामित कर सकता है। प्रत्येक दल अधिकतम **3 प्राधिकृत व्यक्तियों**, यदि कोई हों, के नामों के बारे में सूचित कर सकता है, जो माल गोदाम से चुनी हुई ईवीएम को नई दिल्ली स्थित आयोग लाने के दौरान अपनी लागत पर जाना चाहता है।
3. वे राजनीतिक दल जो ईवीएम चुनौती में, भाग लेने को इच्छुक हैं, उन्हें भारत निर्वाचन आयोग को **26 मई, 2017 को अपराह्न 5.00 बजे** तक ई-मेल (evmchallenge@eci.gov.in) के माध्यम से अनिवार्य रूप से अपनी अभिरूचि की पुष्टि करनी होगी, जिसमें निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार नामित सदस्यों के विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को ईवीएम चुनौती में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जो भारत निर्वाचन आयोग को **26 मई, 2017 को अपराह्न 5.00 बजे** तक अपनी सहमति भेज देंगे। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया दल के शासकीय पत्र शीर्ष पर ही होनी चाहिए जिसपर राजनैतिक दल के अध्यक्ष या महासचिव द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षर होना चाहिए जिसे स्कैन किया जाएगा तथा उपर्युक्त ई-मेल आईडी पर मेल किया जाएगा।
4. इसके अतिरिक्त, यदि किसी राजनीतिक दल के नामित, जिन्हें चुनौती के लिए तारीख-समय स्लॉट आबंटित किया गया है, पूर्व सूचना या अनुमोदन के बिना निर्धारित समय एवं स्थान पर रिपोर्ट करने में असफल रहते हैं तो उन्हें ईवीएम चुनौती में भाग लेने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा।
5. प्रत्येक राजनीतिक दल को निर्वाचन कराए गए पांच राज्यों में से किन्हीं 4 मतदान केन्द्रों से उनकी पसंद की अधिकतम 4 ईवीएम का चयन करने की अनुमति दी जाएगी। उदाहरणार्थ; 4 मतदान केन्द्रों से अधिकतम 4 ईवीएम चुनी जा सकती हैं, किसी राज्य में या पांच राज्यों में किसी भी एक राज्य से या तो एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से या बहुल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से। यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्वाचन याचिका (ईपी) में शामिल कोई भी ईवीएम या सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा सीलबंद की गई कोई भी ईवीएम इस ईवीएम चुनौती का हिस्सा

नहीं होगी। यदि कोई राजनीतिक दल किसी विशेष ईवीएम का उल्लेख नहीं करना चाहता है, परन्तु वह चाहता है कि भारत निर्वाचन आयोग अपनी पसंद की कोई भी ईवीएम उपलब्ध कराए, तो उन्हें **26 मई, 2017 तक** इसकी सूचना आयोग को देनी चाहिए।

6. ईवीएम के विकल्प के बारे में सूचना **26 मई, 2017 को अपराहन 5.00 बजे** तक निर्धारित पोफार्मा में ई-मेल (evmchallenge@eci.gov.in) करनी होगी।

7. कंट्रोल यूनितों (सीयू), बैलेट यूनितों (बीयू), (यथानियोजित एक अथवा अधिक) और वीवीपीएटी (जहां भी प्रयुक्त हों) सहित, **चुनी हुई ईवीएमों को** ईवीएम स्ट्रांग रूम/गोदामों को खोलने एवं ईवीएम को लाने-ले जाने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुपालन में, जैसा है, जहां है के आधार पर, नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग में लाया जाएगा।

8. राज्य स्तर पर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, यदि वे चाहें इसके लिए स्वतंत्र है कि जहां ईवीएमों को वर्तमान में रखा गया है, उन जिला/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के ईवीएम स्ट्रांग रूमों को खोलने के समय मौजूद रहें, मशीनों पर लगी विभिन्न सीलों का (प्रोटोकॉल के अनुसार) निरीक्षण करें और सीलबंद ट्रकों में भारत निर्वाचन आयोग में मशीनों को लाने के दौरान उनके साथ रहें।

9. चूँकि, इन मशीनों का प्रयोग हाल ही में सम्पन्न निर्वाचनों में किया गया था और मतगणना के बाद उन्हें गोदामों में रखा गया था, अतः इन मशीनों में अभी भी अभ्यर्थियों की सैटिंग और उक्त निर्वाचन का परिणाम भी होगा।

10. पिछले निर्वाचनों में मतगणना के दौरान मशीनों के यथा रिकार्ड परिणाम भी पेपर के रूप में उपलब्ध होंगे जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी इत्यादि के लिए डाले गए मतों तथा डाले गए कुल मतों का ब्यौरा भी शामिल होगा।

11. भाग लेने वाले प्रत्येक राजनैतिक दल को चुनौती कथन 1 और 2 को सिद्ध करने के लिए 4 घंटे का चुनौती स्लॉट प्रदान किया जाएगा, जिसमें उनके रजिस्ट्रीकृत नामित व्यक्ति को उनके द्वारा चुनी हुई ईवीएम में से एक ईवीएम (सीयू+बीयू+वीवीपीएटी यदि लगी हुई है तो) तक पहुंच प्रदान की जाएगी। यदि चुनी गई पहली ईवीएम लाने-ले जाने की वजह से निष्क्रिय हो गई है तो चुनौती के लिए दूसरी चुनी हुई ईवीएम को प्रयोग करने के लिए दिया जाएगा और इसी प्रकार अन्य के लिए प्रक्रिया दोहराई जाएगी। तथापि, यदि कोई राजनैतिक दल अधिक समय लेना

चाहता है तो वह आयोग को लिखित में अनुरोध करेगा, जो मामले की मेरिट और तर्कसंगतता की मांग के अनुसार निर्णय लेगा।

12. नामित व्यक्ति, यदि ऐसा चाहे तो, चुनौती हेतु कार्यवाही से पूर्व सीयू में पहले से स्टोर किए गए पिछले निर्वाचन के परिणाम की जांच कर सकता है और यह सत्यापन कर सकता है कि यह सीयू से परिणामों की घोषणा के ईसीआई प्रोटोकॉल के अनुसार उपर्युक्त मद संख्या 10 में ईसीआई द्वारा दिए परिणाम के अनुसार है। यह कदम वैकल्पिक है और यदि वे इसका विकल्प चुनने के लिए लिखित में अनुरोध करना चाहें तो यह रिकार्ड किया जाएगा। पुनः मतगणना को भी रिकार्ड किया जाएगा।

13. राजनैतिक दलों के प्रतिभागी नामित व्यक्तियों को चुनौती को सिद्ध करने के लिए, चुनौती संबंधी ईवीएम पर निम्नलिखित पद्धतियों की अनुमति होगी:

क. सीयू अथवा बीयू या दोनों पर किसी भी क्रम के बटनों को दबाना।

ख. किसी भी बाहरी वायरलैस/ब्लूटूथ/मोबाइल फोन उपकरण/ट्रांसमीटर का प्रयोग।

14. चुनौती देने वाले व्यक्ति द्वारा दबाए गए सभी बटनों को बटन दबाने की वास्तविक प्रक्रिया से पूर्व उसके संबंध में घोषणा करनी होगी और मतदान में "चुनौती साबित करने" के लिए "संचालन की सही प्रक्रिया के लिखित रिकॉर्ड" रखने के लिए इन्हें ईसीआई काउंटर स्टाफ द्वारा मैन्युअल रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा। यदि चुनौतीदाता मतदान के दौरान मोबाइल या ब्लूटूथ का प्रयोग करना चाहता है तो उसे निर्वाचन प्राधिकारियों को सूचित करना चाहिए और इसे भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। यह विशेष रूप से तब सुसंगत है, यदि चुनौती देने वाला व्यक्ति कोई छद्म मतदान या पूर्ण मतदान बटन दबाकर या मोबाइल फोन/ब्लूटूथ द्वारा चुनौती कथन को सिद्ध करने के लिए छेड़छाड़ का प्रयास करने के दौरान ऐसा करना चाहता है।

15. सभी 'की प्रैसेस' को ईसीआई काउंटर स्टाफ तथा रिकार्डिंग कैमरा के स्पष्ट और निर्बाध दृश्य में किया जाएगा और विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रेसर से ऐसा किया जाएगा ताकि चुनौती देने वाले व्यक्ति द्वारा अंगुलियों का प्रयोग करते हुए किसी प्रकार के भ्रम या अस्पष्टता की स्थिति से बचा जा सके।

16. चुनौती II के दौरान ईवीएम को खोला जा सकता है और केवल आंखों से देखकर ही इसका निरीक्षण किया जा सकता है, क्योंकि प्रथम स्तरीय जांच के समय ही इसकी अनुमति दी जाती

है। किन्तु, चुनौती I के दौरान इन्हें खोला नहीं जा सकता क्योंकि वास्तविक मतदान परिदृश्य की अवधि के दौरान मतदान समाप्ति के पश्चात मतगणना होने तक इन्हे सील बंद रखा जाता है।

17. चुनौती की अवधि के दौरान, किसी लिखित प्रतिवेदन अथवा किसी विवाद या निर्वचन संबंधी मामले में, भारत निर्वाचन आयोग के प्रभारी-अधिकारी का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

18. ईवीएम चुनौती का आयोजन निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली में 03.06.2017 से किया जाएगा।

चुनौती का निष्कर्ष :

1. चुनौती I के अंतर्गत चुनौतीदाता को “ असफल ” माना जाएगा, यदि:

- क. चुनौतीदाता द्वारा छेड़छाड़ करने का प्रयास करते समय ही ईवीएम कार्य करना बंद कर देती है। (कारण: ईसीआई की ईवीएम इस प्रकार डिजाइन की गई हैं कि यदि इसमें किसी प्रकार की अवांछित तकनीकी से कार्य किया जाए तो यह कोई गलत परिणाम देने के बजाय स्वतः ‘एरर मोड में’ चली जाती हैं।
- ख. ईवीएम प्रचालनाधीन रहती है और चुनौती प्रयास करने के पश्चात कंट्रोलिंग यूनिट पर दर्शाया गया परिणाम वैसा ही है जैसा कि चुने गए सीयू में स्टोर हुए परिणाम को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किया गया था। (क्लीयर बटन दबाने से पहले)
- ग. यदि चुनौतीदाता ईवीएम की चुनौती के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों में से, किसी दिशा-निर्देश का उल्लंघन करता है।
- घ. चुनौतीदाता वर्तमान चुनौती से अपना नाम वापस ले लेता है।

2. चुनौती II के अंतर्गत चुनौतीदाता को “ असफल ” माना जाएगा, यदि:

- क. चुनौतीदाता द्वारा छेड़-छाड़ करने का प्रयास करते समय ही ईवीएम कार्य करना बंद कर देती है या खराब हो जाती है। (कारण: ईसीआई की ईवीएम इस प्रकार डिजाइन की गई हैं कि वे कोई गलत परिणाम देने के बजाय स्वतः ‘एरर मोड में’ चली जाती हैं यदि इसमें किसी प्रकार का अप्राधिकृत अथवा अनचाहा तकनीकी कार्य किया जाए।
- ख. ईवीएम प्रचालनाधीन रहती है और पहले से स्टोर किए गए परिणाम को हटाने के बाद, चुनौतीदाता द्वारा उस पर चुनौती प्रयास के साथ-साथ छद्म मतदान या संपूर्ण मतदान किया जाता है और हाथ से डाले गए मतों (भारत निर्वाचन

आयोग के कर्मचारी द्वारा) का योग वही होता है जो उक्त छद्म/पूर्ण मतदान के पश्चात, चुनी हुई कंट्रोल यूनिट पर स्टोर किया गया था।

ग. यदि चुनौतीदाता ईवीएम की चुनौती के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों में से किसी दिशा-निर्देश का उल्लंघन करता है।

घ. चुनौतीदाता वर्तमान चुनौती से अपना नाम वापस ले लेता है।

10. कतिपय न कहने वाले व्यक्तियों ने मांग की है कि भारत निर्वाचन आयोग को या तो ईवीएम में छेड़छाड़ करने के लिए उन्हें मशीन अपने साथ ले जाने अथवा उसका आंतरिक सर्किट आदि बदलने की अनुमति देनी चाहिए। यह कहना वैसा ही है जैसे कि उन्हें एक नई मशीन बनाने की अनुमति दे दी जाए और वे हमारी प्रणाली में अपनी नई ईवीएम लगा दें। इसके अतिरिक्त, यह हर कोई जानता है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के “इंटरनल सर्किट” में परिवर्तन करना डिवाइस में परिवर्तन करने के समान है” इसके पश्चात यह डिवाइस मूल डिवाइस जैसी नहीं रह सकती है। एक सामान्य व्यक्ति भी यह समझता है कि ईसीआई की ईवीएम से भिन्न अथवा ऐसी ईवीएम, जिसका इंटरनल सर्किट भिन्न है, सामान्यतया एक भिन्न मशीन है अथवा यह भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम जैसी दिखती है, इसलिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह गारंटी कभी नहीं दी जा सकती कि यह सटीक परिणाम देगी। हमारे प्रशासनिक सुरक्षा उपायों के अंतर्गत ऐसे परिदृश्य को पूरी तरह से नकार दिया जाता है और इसी कारण से चुनौती में इसका प्रस्ताव नहीं किया गया।

11. आयोग, देश के सभी नागरिकों, मतदाताओं, राजनैतिक दलों और अन्य सभी हितधारकों का आभार प्रकट करता है कि 67 से अधिक वर्षों से उनका आयोग के प्रति दृढ़ और अटूट विश्वास बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, आयोग सभी राजनैतिक दलों का भी धन्यवाद करता है जिन्होंने भारत निर्वाचन आयोग में अपना निरंतर भरोसा और विश्वास व्यक्त किया है, जैसा कि 12 मई, को सर्वदलीय बैठक में सभी राजनैतिक दलों ने वार्तालाप के दौरान व्यक्त किया था। आयोग देश के लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि वह निर्वाचनों की शुचिता, सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता कायम रखने और अपने देश के निर्वाचकीय लोकतंत्र में लोगों के भरोसे और विश्वास को और मजबूत करने में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मैं देश के नागरिकों को पुनः आश्वासन देता हूँ कि आयोग निर्वाचन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा में लोगों के विश्वास को कभी डगमगाने नहीं देगा। आयोग की इच्छा है कि देश के सभी नागरिक, हितधारक हमारी निर्वाचकीय प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक, सजग और सतर्क रहें ताकि आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के आयोजन को और सुदृढ़ किया जा सके।

(धीरेन्द्र ओझा)

निदेशक

अनुबंध-6

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड नई दिल्ली-110001

सं.ईसीआई/प्रेस नोट/47/2017

दिनांक: 3 जून, 2017

प्रेस नोट

विषय- ईवीएम चुनौती का समापन।

प्रारंभ में भारत निर्वाचन आयोग सभी हितधारकों का, ईवीएम के प्रति अपने भरोसे एवं विश्वास की पुनः पुष्टि करने के लिए, चाहे वह ईवीएम चुनौती की पूर्ण प्रक्रिया में भाग लेकर किया गया हो या अन्यथा, धन्यवाद करता है। भारत निर्वाचन आयोग ने, एक असाधारण उपाय में, सभी राष्ट्रीय एवं राज्यीय मान्यता-प्राप्त राजनैतिक दलों को आमंत्रित किया था कि वे आएँ और इसके द्वारा दिनांक 20 मई, 2017 को घोषित ईवीएम चुनौती में चुनौती की रूपरेखा के अनुसार भाग लें। केवल दो राजनैतिक दलों नामतः एनसीपी एवं सीपीआई(एम) ने दिनांक 26 मई, 2017 को अपराह्न 5:00 बजे तक ईवीएम चुनौती में भाग लेने के प्रति अपनी अभिरूचि प्रस्तुत की। चूंकि दोनों में से किसी भी राजनैतिक दल ने जिन पांच राज्यों में निर्वाचन सम्पन्न हुए हैं उनसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें चुने जाने के लिए अपनी पंसद निर्दिष्ट नहीं की। इसलिए आयोग दिनांक 03 जून, 2017 के लिए निर्धारित ईवीएम चुनौती के लिए पंजाब, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश की 12 विधान सभाओं से स्ट्रॉंग रूमों में मुहरबंद स्थिति में रखी गई 14 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को यादृच्छिक तरीके से लाया।

पहले ही, आयोग ने सभी राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के साथ 12 मई, 2017 को बैठक की थी जिसमें 42 दलों ने भाग लिया था। हालांकि, अधिकांश ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की सत्यनिष्ठा पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया परन्तु कुछ लोगों ने ईसीआई-ईवीएम की कार्य प्रणाली पर संदेह उठाना जारी रखा।

आयोग ने दिनांक 20 मई, 2017 को एक प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित की तथा बहुत विस्तार से यह बताया कि क्यों इसे तकनीकी और प्रशासनिक रक्षोपायों के भीतर काम करने वाली ईसीआई-ईवीएम के साथ हेर-फेर न कर सकने की बात पर पूर्ण विश्वास है। फिर आयोग ने ईवीएम चुनौती की घोषणा की और एक सम्पूर्ण रूपरेखा निर्दिष्ट की और सभी राजनैतिक दलों को निमंत्रण-पत्र के साथ दिनांक 20 मई, 2017 को भेजा।

आज दोनों दलों (एनसीपी एवं सीपीआई-एम) ने 7वें तल पर स्थित चुनौती स्थल पर रिपोर्ट किया। हालांकि, सीपीआई(एम) ने बताया कि वे चुनौती में नहीं भाग लेना चाहते हैं, वे केवल ईवीएम प्रक्रिया को समझना चाहते हैं। हमारे तकनीकी दल द्वारा उन्हें सम्पूर्ण प्रक्रिया का एक विस्तृत प्रदर्शन दिया गया। उन्होंने तकनीकी विशेषज्ञ समिति के साथ वार्तालाप करने की इच्छा व्यक्त की तथा उन्होंने एक विस्तृत संदेह निवारण सत्र में भाग लिया जिसमें आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा गंभीर तकनीकी

संदेहों को दूर किया गया। सीपीआई(एम) दल ने फिर पूर्ण संतुष्टि व्यक्त की और सुझाव दिया कि इस प्रकार के संदेहों को दूर करने के लिए आयोग को अग्रसक्रियता से तकनीकी समुदाय(विशेषज्ञों) के साथ ऐसे प्रदर्शनों और जागरूकता सत्रों का आयोजन करना चाहिए। आयोग ने उनके अत्यन्त रचनात्मक सुझाव का स्वागत किया।

श्रीमती वंदना चवाण, सांसद की अगुवाई वाले एनसीपी दल ने सूचित किया कि वे भी किसी चुनौती में भाग नहीं लेना चाहते हैं परन्तु केवल सिद्धांत रूप में भाग लेने के इच्छुक हैं। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती अनुरोध का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने ईवीएम की मेमोरी संख्या तथा बैटरी संख्या उन्हें चार दिन पहले उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया था। महानिदेशक, श्री सुदीप जैन ने उन्हें सूचित किया कि आयोग ने उनके अनुरोध का पहले ही उल्लेख करते हुए उत्तर दे दिया है कि ईवीएम को मुहरबंद स्थितियों में रखा जाना होता है इसलिए आयोग के लिए यह संभव नहीं है कि वह दलीय प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में ईवीएम से मेमोरी तथा बैटरी संख्या निकालने के लिए उन्हें खोले। तदनुसार, आयोग ने सूचित किया था कि दल इन संख्या को चुनौती के समय जो चुनौती रूपरेखा के अनुसार उपलब्ध कराई गई हैं, मुहरबंद ईवीएम को स्वयं खोलकर प्राप्त कर सकता है। महानिदेशक ने उन्हें दोबारा सूचित किया कि वे एक ईवीएम चुन सकते हैं और मेमोरी संख्याएं प्राप्त करने के लिए उसे खोल सकते हैं। हालांकि, एनसीपी प्रतिनिधि ने यह कहते हुए एक पत्र प्रस्तुत किया कि वे इस सूचना के उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण चुनौती में भाग नहीं ले सकते हैं। अपने में एनसीपी प्रतिनिधि ने, उन्हें 14 ईवीएम की सूची में से एक का चयन करने के लिए कहकर, ईवीएम चयन प्रोटोकॉल में आखिरी क्षण में बदलाव करने के प्रति भी आपत्ति व्यक्त की।

तब आयोग ने उन्हें अपने सभी तकनीकी संदेह दूर करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ समिति के साथ चर्चा करने का प्रस्ताव दिया। फिर एनसीपी दल ने तकनीकी विशेषज्ञ समिति के साथ विस्तृत चर्चा की जिससे उनके द्वारा आज प्रस्तुत पत्र में सूचीबद्ध 8 मामलों सहित उनके सभी मुद्दों का स्पष्टीकरण हो गया तथा आज प्रस्तुत पत्र का प्रत्युत्तर भी अलग से भेजा जाएगा।

एनसीपी दल ने एक बार फिर आयोग से मुलाकात की जहां आयोग ने अपना प्रस्ताव दोहराया कि वे अभी भी चुनौती में भाग ले सकते हैं या ईवीएम चुनकर और मशीन को अपने आप खोलकर मेमोरी एवं बैटरी संख्या प्राप्त करके सिद्धांत रूप में जानकारी ले सकते हैं। आयोग ने उनके समक्ष यह प्रस्ताव भी रखा कि वे अपनी बात साबित करने के लिए पुनः आ सकते हैं जैसा कि उन्होंने मांग रखी थी।

हालांकि, एनसीपी प्रतिनिधियों ने उल्लेख किया कि उनके सभी संदेहों का स्रोत महाराष्ट्र में नगरपालिका निर्वाचनों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों(ईवीएम) के साथ कथित गड़बड़ियों को लेकर था। आयोग ने स्पष्ट किया कि शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र द्वारा प्रयुक्त ईवीएम भारत निर्वाचन आयोग की नहीं हैं। एनसीपी दल ने तब यह अनुरोध करते हुए चुनौती-प्रक्रिया से बाहर आने की अपनी इच्छा व्यक्त की कि आयोग को एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो ईसीआई-ईवीएम को एसईसी-ईवीएम से सुस्पष्ट रूप में अलग दर्शाए। आयोग ने एनसीपी के सुझावों को नोट कर लिया है।

आयोग ने सार्वजनिक रूप से और सभी राजनैतिक दलों के समक्ष पहले ही कहा है कि आगामी सभी निर्वाचन अनिवार्य रूप से वीवीपीएटी मशीनों के साथ किए जाएंगे। आयोग का यह दृढ़ विश्वास है कि आगामी सभी निर्वाचनों में सभी मतदान केन्द्रों में वीवीपीएटी युक्त ईवीएम का उपयोग ईवीएम आधारित मतदान प्रणाली में अत्यधिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता लाएगा। ऑडिट ट्रेल मतदाताओं के भरोसे और विश्वास को और पुख्ता करेगा। वीवीपीएटी युक्त ईवीएम का उपयोग ईवीएम के संबंध में गलत रूप से फैलाए गए सभी संदेहों और आशंकाओं को निर्णायक रूप में समाप्त कर देगा।

माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने कल अपने निर्णय में कहा, “प्रथमदृष्टया, भारत निर्वाचन आयोग की सम्पूर्ण प्रेस विज्ञप्ति के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट है कि यह प्रणाली सील प्रूफ है। ईवीएम हैक नहीं की जा सकती। विनिर्माण चरण में किसी भी प्रकार का हेरफेर नहीं किया जा सकता है। बटन दबाने के अनुक्रम के माध्यम से ट्रोजन हॉर्स को एक्टिवेट करने से परिणाम नहीं बदले जा सकते। ईसीआई-ईवीएम के साथ बाह्य रूप से हेर-फेर नहीं किया जा सकता। ईवीएम में कुछ सबसे अधिक परिष्कृत प्रौद्योगिकीय विशेषताएं जैसे एक बारगी क्रमादेशन-योग्य(ओटीपी) माइक्रोकंट्रोलर्स, की कूटों (Key Codes) की डायनमिक कूटबद्धता, प्रत्येक की प्रेस करने की तारीख तथा समय का अंकन आदि का उपयोग किया जाता है। इन ईवीएमों के साथ परिवहन के दौरान या भण्डारण स्थान पर भी हेर-फेर नहीं किया जा सकता है। ईवीएम को हेर-फेर-रोधी बनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण तथा संतुलन की व्यवस्था है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि दृष्टिक निरीक्षण के लिए चुनौती II के दौरान ईवीएम को खोला जा सकता है और केवल आंखों से देखकर ही इसका निरीक्षण किया जा सकता है, क्योंकि प्रथम स्तरीय जांच के दौरान इसकी अनुमति दी जाती है।

आयोग, देश के सभी नागरिकों, मतदाताओं, राजनैतिक दलों और अन्य सभी हितधारकों का आभार प्रकट करता है कि पिछले 67 से अधिक वर्षों से उनका आयोग के प्रति दृढ़ और अटूट विश्वास बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, आयोग सभी राजनैतिक दलों का भी धन्यवाद करता है जिन्होंने भारत निर्वाचन आयोग में अपना निरंतर भरोसा और विश्वास व्यक्त किया है, जैसा कि 12 मई, को सर्वदलीय बैठक में राजनैतिक दलों के इंटरवेन्शनों के दौरान व्यक्त हुआ। आयोग देश के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता है कि यह निर्वाचनों की निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता कायम रखने में और अपने देश के निर्वाचकीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास को और सुदृढ़ करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मैं देश के नागरिकों को पुनः आश्वासन देता हूं कि निर्वाचन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा में लोगों का विश्वास कभी भी डगमगाने नहीं दिया जाएगा। आयोग की इच्छा है कि देश के सभी नागरिक और हितधारक हमारी निर्वाचन प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक, सतर्क और सावधान रहें ताकि आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन को और अधिक सुदृढ़ कर सके।

.....ह/-.....

(सुमन कुमार दास)

अवर सचिव

कोई मतदाता नहीं छूटे



भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001

दूरभाष: +91-11-23717391; फ़ैक्स: +91-11-23713412

यूआरएल: www.eci.nic.in

Ecisveep.nic.in